रांची, गुरुवार
01.10.2026
वर्ष : 11, अंक : 299, पृष्ठ : 12
मूल्य : दो रूपए

बिहान भारत

रांची से प्रकाशित हिन्दी दैनिक
खबरे हमारी, विश्वास आपका

website : www.bihanbharat.org | bihanbharat@gmail.com | @bihan_bharat | Bihan Bharat | @bihanbharat | RNI NO - JHAHIN/2015/73988

संक्षिप्त खबरें

प्रधानमंत्री आज संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह में होंगे शामिल

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुरुवार को यहां भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। वह सुबह 11 बजे समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री संघ लोक सेवा आयोग की शताब्दी के उपलक्ष्य में स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री भारत में संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों की नीतियों को आकार देने वाले 100 महत्वपूर्ण निर्णय पुस्तक का भी विमोचन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, यह कार्यक्रम वर्षभर चले शताब्दी समारोहों का समापन होगा। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना वर्ष 1926 में हुई थी। स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वर्षभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों की शुरूआत पिछले वर्ष 01 अक्टूबर को हुई थी।

अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेसवे पर बस और ट्रक की टक्कर, 5 लोगों की मौत

सूरत/आणंद। अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेसवे पर आणंद और नडियाद के बीच बुधवार तड़के साई दर्शन ट्रैवल्स की बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसे में बस में सवार पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य घायल बताए गए हैं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, साई दर्शन ट्रैवल्स की निजी लग्जरी बस सूरत से राजस्थान जा रही थी। बुधवार तड़के करीब 3:30 से 4 बजे के बीच बस आणंद से नडियाद की ओर जा रही थी, तभी उसकी ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे के समय अधिकांश यात्री सो रहे थे। अचानक हुए धमाके से यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई और कई लोग बस के भीतर फंस गए। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस तथा 108 एंबुलेंस को सूचना दी गई। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। मृतकों के शवों को पंचनामा कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।

चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्षी दल एकजुट, दो अक्टूबर से देशभर में चलायेंगे 'लोकतंत्र बचाओ' अभियान

एजेंसी

नई दिल्ली: विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर 'वोट चोरी' के आरोप लगाते हुए देश भर में दो अक्टूबर से आठ अक्टूबर तक 'लोकतंत्र बचाओ' अभियान चलाने की घोषणा की है।

गठबंधन की बुधवार को यहां करीब ढाई घंटे चली बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने संवाददाताओं को बताया कि बैठक में चुनाव आयोग और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों पर मिलकर लड़ाई लड़ने की प्रतिबद्धता दोहराई गयी। बैठक में बीस दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। श्री खरगे ने कहा कि गठबंधन के घटक दल दो अक्टूबर से आठ अक्टूबर तक देश के प्रत्येक जिले में 'लोकतंत्र बचाओ' अभियान चलायेंगे तथा जिलाधिकारियों के कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन किया जायेगा।

छह अक्टूबर को सभी विपक्षी दलों के सांसद चुनाव आयोग तक मार्च करेंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात कर 'वोट चोरी' से जुड़े मुद्दों तथा सरकार के क्रियाकलापों पर अपनी चिंता से उन्हें अवगत करायेगा। इस अभियान में जनता, युवाओं, तथा लोकतंत्र और एकता के लिए प्रतिबद्ध अन्य संगठनों को भी शामिल किया जायेगा। कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि विपक्ष देश भर में पांच बड़ी रैलियां भी आयोजित करेगा, जिनकी तारीखें बाद में घोषित की जाएंगी। पहली बड़ी रैली नवंबर में दिल्ली में होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के संरक्षण में चुनावों में 'वोट चोरी' हो रही है। उन्होंने कहा कि श्री राहुल गांधी जिन मुद्दों को पहले से उठा रहे थे, अब वे बातें सही साबित होती दिखाई दे रही हैं।

नोटबंदी की तरह अब 'वोटबंदी' के जरिए लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं। उन्होंने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से संबंधित सभी मामलों का उच्चतम न्यायालय में जल्द निपटारा किए जाने की मांग की ताकि लोगों को न्याय मिल सके। साथ ही उन्होंने हर चुनाव मतपत्रों से कराने की मांग भी दोहराई।

शेष 11 पर

बड़गाई जमीन केस में सीएम हेमंत सोरेन पर आरोप तय

बिभा संवाददाता

रांची : बड़गाई अंचल की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े कथित फजीर्वाड़े और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ विशेष पीएमएलए अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं। इसके साथ ही मामले में मुख्यमंत्री समेत कुल 17 आरोपियों के खिलाफ ट्रायल की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इससे पहले 16 आरोपियों के खिलाफ आरोप गठित किए जा चुके थे।

आरोप गठन की कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश हुए। अदालत ने उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को पढ़कर सुनाया। इस पर हेमंत सोरेन ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया और कहा कि उन्होंने किसी तरह का अपराध नहीं किया है।

यह मामला रांची के बड़गाई अंचल स्थित करीब 8.86 एकड़ जमीन से जुड़ा है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच के अनुसार, जमीन के रिकॉर्ड में कथित हेरफेर, फर्जी दस्तावेज तैयार करने और जमीन पर कथित अवैध कब्जे से जुड़े पहलुओं की जांच की गई है। ईडी ने इस मामले को मनी लॉन्ड्रिंग से भी जोड़ा है।

मामले में भानु प्रताप प्रसाद, अंतू तिर्की, विनोद कुमार सिंह, बिजेंद्र सिंह, बिपिन सिंह, प्रियरंजन सहाय, मनोज कुमार यादव, कुमार राजश्री, राजकुमार पाहन, संजीत कुमार, शेखर कुशवाहा, तापस घोष, मोहम्मद इरशाद अख्तर, अफसर अली, मोहम्मद सद्दाम हुसैन और मोहम्मद इरशाद समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ पहले ही आरोप गठित किए जा चुके हैं।

आरोप तय होने के बाद अब मामले में ट्रायल की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। हालांकि, आरोप गठन को दोष सिद्ध होना नहीं माना जाता है। मुकदमे के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष को अपना-अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा। आरोपों की पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगी।

30 नवंबर से अभियोजन पेश करेगा गवाह

अदालत ने आरोप गठन के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 नवंबर की तिथि निर्धारित की है। उस दिन से अभियोजन को गवाह पेश करने का निर्देश दिया गया है। इस मामले में कुल 17 आरोपित हैं। हेमंत सोरेन को छोड़कर अन्य 16 आरोपितों के खिलाफ पहले ही आरोप गठन हो चुका है।

डिजिटल हेल्थ से बदलेगी झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था : स्वास्थ्य मंत्री

बिभा संवाददाता

रांची। झारखंड डिजिटल हेल्थ कॉन्क्लेव-2026 का शुभारंभ बुधवार को बीएनआर चाणक्य होटल में हुआ।

इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना, 10-बेडेड टेली-आईसीयू, एचआरआईएस पोर्टल और झारखंड ई-हेल्थ पोर्टल का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, चिकित्सक, तकनीकी विशेषज्ञ, सिविल सर्जन और निजी अस्पतालों के प्रतिनिधि मौजूद थे।

इस अवसर पर मंत्री इरफान अंसारी ने बतौर मुख्य अतिथि कहा कि डिजिटल हेल्थ स्वास्थ्य व्यवस्था को आधुनिक, सुलभ और पारदर्शी बनाने के साथ गरीब और ग्रामीण मरीजों के लिए तकनीकी कवच का काम करेगी। उन्होंने कहा कि सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें हकीकत में बदलने के लिए मेहनत और इच्छाशक्ति जरूरी है। मंत्री ने कहा कि डिजिटल हेल्थ के दम पर झारखंड अपने पैरों पर खड़ा होगा। टेलीमेडिसिन, टेली-आईसीयू और टेली-रेडियोलॉजी के माध्यम से दूरदराज के मरीजों तक विशेषज्ञ चिकित्सकीय सलाह पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। रोबोटिक सर्जरी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल की दिशा में भी काम हो रहा है।

मौके पर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के तहत कनेक्टिविटी, एचएमआईएस, सीसीटीवी मॉनिटरिंग और डिजिटल डैशबोर्ड पर काम किया जा रहा है। एचएमआईएस से मरीज घर बैठे पंजीकरण, भुगतान और डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि एचआरआईएस के जरिए स्वास्थ्यकर्मियों की नियुक्ति से सेवानिवृत्ति तक का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा।

कार्यक्रम में डॉ आरएस शर्मा और अन्य विशेषज्ञों ने भी डिजिटल स्वास्थ्य की संभावनाओं पर विचार रखे। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी सहित अन्य सहित लोग मौजूद थे।

शुभमन गिल का रिकॉर्ड दोहरा शतक,भारत को 2-0 की अपराजेय बढ़त

एजेंसी

गुवाहाटी। भारतीय कप्तान शुभमन गिल के रिकॉर्डतोड़ दोहरे शतक और रोहित शर्मा के शानदार शतक की बदौलत भारत ने बुधवार को दूसरे वनडे में वेस्टइंडीज को आठ विकेट से हरा दिया। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में सात विकेट पर 405 रन बनाए थे। भारत ने 43.3 ओवर में दो विकेट खोकर 406 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इस जीत के साथ भारत ने तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली।

यह भारत के 52 साल के वनडे इतिहास में पहली बार है, जब उसने 400 से ज्यादा रन के लक्ष्य का सफल पीछा किया है। वनडे क्रिकेट में इससे पहले केवल दक्षिण अफ्रीका ने 400 से ज्यादा के लक्ष्य का सफल पीछा किया था। उसने 2006 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 438 रन का लक्ष्य हासिल किया था।

कप्तान शुभमन गिल ने 133 गेंदों पर नाबाद 223 रन की शानदार पारी खेली। उन्होंने 26 चौके और आठ छक्के लगाए। गिल ने 117 गेंदों में दोहरा शतक पूरा कर वनडे क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। उन्होंने ईशान किशन का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ 126 गेंदों में दोहरा शतक लगाया था। यह गिल का वनडे में दूसरा दोहरा शतक है। इससे पहले उन्होंने 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 208 रन बनाए थे।

रोहित शर्मा ने भी शतक लगाते हुए 75 गेंदों पर 101 रन बनाए। उन्होंने 10 चौके और छह छक्के लगाए। गिल और रोहित ने पहले विकेट के लिए 255 रन की साझेदारी की, जिसने भारत की जीत की नींव रखी। विराट कोहली 29 रन बनाकर आउट हुए, जबकि ऋतुराज गायकवाड़ 31 रन बनाकर नाबाद रहे।

इससे पहले. वेस्टइंडीज की ओर से जॉन कैंपबेल ने 68 गेंदों में 101 रन बनाए। कप्तान शे होप ने 94 गेंदों पर 104 रन की पारी खेली। आमिर जांगू ने भी 69 गेंदों में अपना दूसरा वनडे शतक पूरा किया और 114 रन बनाकर नाबाद रहे। वेस्टइंडीज के तीन बल्लेबाजों का एक ही वनडे में शतक लगाना भी इस मैच की खास उपलब्धि रही। टीम ने पहली बार वनडे में 400 रन का आंकड़ा पार किया।

भारत की ओर से गुरनूर बराड़, कुलदीप यादव और रवींद्र जडेजा ने दो-दो विकेट लिए।

कैबिनेट : ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के तीसरे चरण को मंजूरी, बैटरी भंडारण और राज्यों के बीच सप्लाई होगी बेहतर

एजेंसी

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण-3 योजना को मंजूरी दी है। योजना बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ राज्यों के बीच बिजली सप्लाई प्रणाली का विकास करेगी। यह योजना 135 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा निकासी और 50 गीगावाट बैटरी ऊर्जा भंडारण में सहायक होगी।

परियोजना पर 1,86,405 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसमें 54,082 करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता शामिल है। योजना को वित्त वर्ष 2032-33 तक स्थापित करने का लक्ष्य है। यह सहायता राज्य के भीतर पारेषण शुल्क को कम करने और बिजली की लागत को नियंत्रित करने में भी सहायक होगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने उक्त आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। केन्द्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने राष्ट्रीय मीडिया केन्द्र में मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी।

मंत्री के अनुसार इससे राज्य के भीतर नवीकरणीय ऊर्जा का एकीकरण और बिजली निकासी सुगम होगी। अंतरराज्यीय पारेषण को मजबूती मिलेगी। योजना साल 2035 तक 900 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता स्थापित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगी। उन्होंने बताया कि इससे अनियमित बिजली आपूर्ति, ग्रिड में भीड़भाड़ और अधिक मांग के समय में बिजली कटौती को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। साथ ही गैर-सौर ऊर्जा वाले समय की मांग को भी पूरा किया जा सकेगा।

जीईसी-3 भारत के 2035 तक 900 गीगावाट स्थापित गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगी। यह दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा में योगदान देगी, कार्बन फुटप्रिंट को कम करेगी और बिजली, विनिर्माण, निर्माण और ऊर्जा भंडारण क्षेत्रों में रोजगार सृजित करेगी।

दिल्ली के लिए इंटेलीजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, 42 कोरिडोर का होगा प्रबंधन

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक के बेहतर प्रबंधन और उसमें सुधार के लिए केंद्र सरकार ने ह्यइंटेलीजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टमह्ण को मंजूरी दी है। इससे दिल्ली के 2,242 महत्वपूर्ण ट्रैफिक कॉरिडोर का वास्तविक समय में प्रबंधन होगा। इसके लिए 1,789 .52 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने बुधवार को इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। वहीं, केन्द्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने राष्ट्रीय मीडिया केन्द्र में मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। इसके तहत एआई का उपयोग करने वाले ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाएंगे। यह सिग्नल यातायात की स्थिति को देखते हुए ट्रैफिक लाइट के समय को बदलेंगे। आपातकालीन वाहनों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस व्यवस्था की यह विशेषता होगी कि यह ट्रैफिक जाम और किसी तरह के सड़क हादसे की त्वरित पहचान संभव होगी। इससे वाहन चालकों को ट्रैफिक के बारे में यथासमय जानकारी मिलेगी और उन्हें डायवर्जन या पार्किंग की भी जानकारी दी जाएगी। इस परियोजना में 1,092 अनुकूली यातायात नियंत्रण प्रणाली और 1,029 प्रवर्तन स्थल शामिल होंगे। कार्यान्वयन प्रदर्शन-आधारित होगा, जिसमें प्रत्येक चरण को निर्धारित परीक्षण, चालू करने, स्वीकृति और प्रदर्शन मापदंडों के आधार पर पिछले चरण के मूल्यांकन के बाद ही शुरू किया जाएगा।

बिंदल मॉल फायरिंग कांड का पुलिस ने किया खुलासा, छत्तीसगढ़ से चार आरोपी गिरफ्तार

बिभा संवाददाता

जमशेदपुर। बिंदल मॉल उडिपी रेस्टोरेंट में हुई गोलीबारी की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए चार कथित साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में सीतारामडेरा निवासी शंकर मुंडा, परसुडीह खासमहल निवासी रमेश कुमार शर्मा उर्फ टीटू शर्मा, परसुडीह प्रमोदनगर निवासी मनोज कुमार सरकार और बिरसानगर निवासी दीपू कुमार ओझा शामिल हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों को छत्तीसगढ़ के रायपुर से गिरफ्तार किया है।

बुधवार को एसएसपी डॉ. एहतेशाम वकारिब ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि 26 सितंबर को उडिपी रेस्टोरेंट में हुई गोलीबारी में डोमिनिक, रिजवान, दिलशान उर्फ दानिय और कृष्णा चौधरी घायल हुए थे। सभी का इलाज टीएमएच में चल रहा है। घटना के बाद पुलिस ने मौके से खोखा, पिलेट्स और खून के नमूने बरामद किए थे। सीसीटीवी और अन्य वीडियो फुटेज की जांच के दौरान पुलिस को घटना में दो शूटरों के शामिल होने की जानकारी मिली। पुलिस के अनुसार मोहन यादव ने गोली चलाई थी, जबकि दूसरे शूटर की पहचान अजीत मंडल के रूप में हुई है। तीसरे व्यक्ति की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। पुलिस दोनों शूटरों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है।

एसएसपी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में घटना के पीछे रेलवे ठेकेदारी और जमीन के कारोबार से जुड़ी पुरानी रंजिश सामने आई है। पुलिस के अनुसार जमीन की खरीद-बिक्री को लेकर विवाद के कारण चारों आरोपियों ने मिलकर गोलीबारी की साजिश रची थी और शूटरों के माध्यम से घटना को अंजाम दिलाया।

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार शंकर मुंडा के खिलाफ सिदगोड़ा, डुमरिया और टाटानगर रेल थाना में छह मामले दर्ज हैं। रमेश कुमार शर्मा उर्फ गुड्डू शर्मा, टीटू शर्मा व अमित शर्मा के खिलाफ 13, मनोज कुमार सरकार के खिलाफ सात और दीपू कुमार ओझा के खिलाफ तीन मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक एरटिगा कार और छह मोबाइल फोन जब्त किए हैं। संवाददाता सम्मेलन में ग्रामीण एसपी शुभम खंडेलवाल और सिटी एसपी ललित मीणा भी मौजूद थे।

महिलाओं की तरक्की से ही मजबूत होगा समाज, योजनाओं का लाभ लेकर आत्मनिर्भर बनें : संजीव सरदार

बिभा संवाददाता

पोटका : महिलाओं को स्वावलंबी और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से आसनबनी में आजीविका महिला संगठन समिति की ओर से खरछढर बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पोटका विधायक संजीव सरदार शामिल हुए। उन्होंने महिला समूहों की सदस्यों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं, सुझावों और आवश्यकताओं की जानकारी ली बैठक को संबोधित करते हुए विधायक संजीव सरदार ने कहा कि महिला सशक्तिकरण का मतलब सिर्फ महिलाओं तक सरकारी योजनाएं पहुंचाना नहीं, बल्कि उन्हें इतना सक्षम बनाना है कि वे अपने परिवार और समाज के आर्थिक विकास में स्वयं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। उन्होंने महिलाओं से कहा कि समूह के माध्यम से एक-दूसरे का सहयोग करें, नियमित बचत की आदत को मजबूत करें और अपनी क्षमता के अनुसार स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ें।

विधायक ने कहा कि सरकार की ओर से महिलाओं और ग्रामीण परिवारों के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। महिला समूहों को चाहिए कि वे इन योजनाओं की जानकारी हासिल करें और पात्रता के अनुसार उनका लाभ लें। उन्होंने कहा कि ह्लयोजना का लाभ तभी सार्थक होगा, जब उससे परिवार की आमदनी बढ़े, महिलाओं के हाथ में आर्थिक मजबूती आए और आत्मनिर्भरता का रास्ता खुले।

कालिकापुर में भी जेएसएलपीएस बैठक, महिलाओं ने साझा किए अनुभव

इसी क्रम में कालिकापुर में भी आजीविका महिला संगठन समिति की ओर से खरछढर बैठक आयोजित की गई। यहां भी विधायक संजीव सरदार ने महिलाओं एवं संगठन की सदस्यों से संवाद किया। महिलाओं ने अपने समूहों से जुड़े अनुभव, समस्याएं और सुझाव विधायक के सामने रखे। विधायक ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना और संबंधित विषयों पर आवश्यक सहयोग का भरोसा दिलाया। कालिकापुर में संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि जब एक महिला आर्थिक रूप से मजबूत होती है, तो उसका असर केवल उसके परिवार तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। इसलिए महिलाओं को अपने अधिकारों, सरकारी योजनाओं और रोजगार के अवसरों के प्रति जागरूक रहना चाहिए ह्व उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं अपने मेहनत और समूह की शक्ति के बल पर आत्मनिर्भरता की नई मिसाल कायम कर सकती हैं।

संक्षिप्त खबरें

टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के ज्वाइंट सेक्रेटरी हुए सेवानिवृत्त, विदाई समारोह आयोजित

जमशेदपुरः टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के संयुक्त महामंत्री एच एस सैनी सेवानिवृत्त होने पर टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन द्वारा विदाई समारोह आयोजित की गई। यूनियन कार्यालय में श्री सैनी को शॉल , पुष्प गुच्छ और उपहार भेंट कर सम्मानित किया गया। इस दौरान यूनियन के अध्यक्ष शशि भूषण प्रसाद, महामंत्री आरके सिंह , यूनियन के पदाधिकारी, कमेटी मेंबर तथा आरके सिंह फैंस क्लब के तमाम सदस्य मौजूद थे। अध्यक्ष शशि भूषण प्रसाद ने अपनी ओर से शुभकामनाएं देते हुए एच सैनी के कुशल व्यक्तित्व को सराहा तथा एक सैनी को एक सफल लीडर बताया। महामंत्री आरके सिंह ने कहा कि ट्रेड यूनियन का असली नेता वही होता है जो सबको साथ लेकर चले। यह गुण सैनी पा जी में है । उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त के बाद सैनी पा जी स्वस्थ रहें , खुशहाल रहे ऐसी ईश्वर से कामना करते हैं।? यूनियन हमेशा सैनी पा जी के साथ खड़ा रहेगा। यूनियन कार्यालय में आयोजित विदाई समारोह का संचालन अशोक उपाध्याय ने किया जबकि धन्यवाद ज्ञापन अनिल शर्मा ने किया। कंपनी परिसर में भी विदाई समारोह धूमधाम से आयोजित की गई। जिसमें अध्यक्ष शशि भूषण प्रसाद , महामंत्री आरके सिंह, एच आर हेड प्रणव कुमार, ईआर हेड सौमिक रॉय समेत अन्य मौजूद थे। सबों ने श्री सैनी शुभकामनाएं दी । यहां डिवीजन के कर्मचारियों ने श्री सैनी को उपहार भेंट किया। अतिथियों के द्वारा अंगवस्त्र एवं माला पहनाकर श्री सैनी का स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालन अभय कुमार ने किया।

श्री नाथ यूनिवर्सिटी ने चलाया स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जागरूकता अभियान

जमशेदपुर। श्रीनाथ यूनिवर्सिटी की एनएसएस इकाई की ओर से बुधवार को गम्हरिया के जगन्नाथपुर प्रोजेक्ट सहेली के तहत स्वास्थ्य एवं व्यक्तिगत स्वच्छता को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य मासिक धर्म से जुड़ी सही जानकारी लोगों तक पहुंचाना, व्यक्तिगत स्वच्छता के प्रति जागरूक करना तथा मासिक धर्म को लेकर समाज में मौजूद मिथकों और भ्रांतियों को दूर करना था। कार्यक्रम के दौरान श्रीनाथ यूनिवर्सिटी के एनएसएस स्वयंसेवकों ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। नाटक के माध्यम से मासिक धर्म चक्र, इस दौरान महिलाओं और किशोरियों के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों तथा सामाजिक संकोच जैसे विषयों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया। छात्रों ने अपने प्रदर्शन के जरिए यह संदेश कार्यक्रम का आयोजन एनएसएस समन्वयक शालिनी ओझा के निर्देशन और मार्गदर्शन में किया गया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय की शिक्षिकाओं रश्मि सिन्हा, नमामी भुइयां, सुदेशना पाल, शिक्षक हिंदोल चक्रवर्ती, रामशंकर गोस्वामी तथा योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विभाग के पीएचडी स्कॉलर राजेश कुमार गुप्ता की सक्रिय भागीदारी रही। कार्यक्रम के माध्यम से श्रीनाथ यूनिवर्सिटी एनएसएस समूह ने समुदाय के बीच स्वास्थ्य जागरूकता, सामाजिक जिम्मेदारी और ज्ञान के माध्यम से सशक्तिकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। साथ ही लोगों को मासिक धर्म से जुड़े विषयों पर बिना किसी झिझक, सामाजिक कलंक या गलत जानकारी के खुलकर बात करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

केसीबी कॉलेज में दो दिवसीय कांशी फूल युवा महोत्सव का भव्य आगाज

बेड़ो। करम चंद भगत महाविद्यालय, बेड़ो में बुधवार को दो दिवसीय कांशी फूल युवा महोत्सव 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। प्रतिभा-संस्कृति -एकता की भावना के साथ आयोजित महोत्सव में विद्यार्थियों की रचनात्मक प्रतिभा और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति को मंच प्रदान किया जा रहा है। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. प्रसनजीत मुखर्जी ने विभिन्न प्रतियोगिताओं का शुभारंभ करते हुए प्रतिभागियों को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने विद्यार्थियों को उत्साहपूर्वक अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास, रचनात्मकता, आत्मविश्वास और सांस्कृतिक चेतना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महोत्सव के दौरान संगीत, नृत्य, साहित्य, नाटक एवं ललित कला सहित विभिन्न विधाओं में प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। विद्यार्थियों ने उत्साह और उमंग के साथ प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और रचनात्मक गतिविधियों से पूरे महाविद्यालय परिसर में उत्सव का माहौल बना रहा। कार्यक्रम में डॉ. मीरा कुमारी, डॉ. नेहा टोप्पो, डॉ. राजा सिंह, डॉ. संतोष कुमार भगत, प्रो. अरविंद राणा बिलुंग, डॉ. ब्रह्मानंद साहू, डॉ. मीना पूर्ति, प्रो. धीरज उरांव, प्रो. प्रवीण दास, डॉ. पूनम कुमारी, डॉ. साधना कुमारी, डॉ. सवार्णी चक्रवर्ती, डॉ. स्मिता गुप्ता, उम्मे कुलसुम, डॉ. सुजाता बाला, डॉ. प्रमिला उरांव, डॉ. अल्पना मेहता, निरु कुमारी, सुनीता उरांव, डॉ. जे.डी. राम, डॉ. बदीउज्जमाँ, डॉ. वी.एन. पांडेय सहित अन्य शिक्षक-शिक्षिकाएं, शिक्षकेतर कर्मचारी एवं सैकड़ों छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

पुलिस जिस दिन चाह ले, उसी दिन से सट्टा और ड्रग्स का रुक जाएगा धंधा : सरयू राय

बिभा संवाददाता

जमशेदपुर। शहर में ड्रग्स और सट्टेबाजी के बढ़ते कारोबार को लेकर जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि ड्रग्स के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई शुरू की तो लगा था कि नेटवर्क की कड़ियां खुलेंगी और सरगना तक पुलिस पहुंचेगी, लेकिन अचानक कार्रवाई थम गई। कार्रवाई के अचानक रुकने से संदेह पैदा होना स्वाभाविक है।

यहां आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में सरयू राय ने कहा कि ड्रग्स और सट्टेबाजी अब केवल कानून-व्यवस्था की समस्या नहीं रह गई है। यह युवाओं के भविष्य, परिवारों की सुरक्षा और समाज के अस्तित्व से जुड़ा गंभीर सवाल है। उन्होंने कहा कि शहर में ड्रग्स का कारोबार तेजी से फैल रहा है और इसकी पहुंच स्कूल-कॉलेजों तक होने की बातें सामने आ रही हैं।

सरयू राय ने कहा कि जब पुलिस ने सट्टा और ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई की थी तो उन्होंने पुलिस की सराहना की थी। उनकी एसएसपी से भी बातचीत हुई थी। एसएसपी ने बताया था कि कार्रवाई के दौरान कई लिंक मिले हैं और आगे महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ सकती है। उन्हें उम्मीद थी कि पुलिस कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी और नेटवर्क के बड़े खिलाड़ियों तथा सरगनाओं तक पहुंचेगी। लेकिन कार्रवाई अचानक बंद हो गई। अगर कार्रवाई लगातार चलती रहती तो और लोग पकड़े जाते। संभव है कि सरगना भी पुलिस की गिरफ्त में आते। अचानक कार्रवाई बंद होने से सवाल उठना स्वाभाविक है।

सरयू राय ने दो टूक कहा कि सरगनाओं को पकड़ना पुलिस का काम है। सामाजिक संगठन और नागरिक केवल जागरूकता पैदा कर पुलिस को सहयोग कर सकते हैं। हम लोग सहयोग करते रहेंगे।

2 अक्टूबर को होगा विचार क्रांति सम्मेलन

श्री राय ने बताया कि महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को साकची स्थित धालभूम क्लब में पूर्वाह्न 11 बजे ह्लसट्टेबाजी एवं ड्रग्स के दुष्प्रभाव पर विचार क्रांति सम्मेलनह्व आयोजित किया जाएगा। इसके बाद सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक अधिकारी मनोज सिंह के नेतृत्व में जन-जागरूकता अभियान चलाने के स्वरूप पर विचार किया जाएगा। इसके बाद अभियान को व्यापक स्तर पर शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ड्रग्स युवाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, मानसिक स्थिति और रोजगार की संभावनाओं को प्रभावित करता है,

शौहर ने ड्रग्स का विरोध किया तो हो गई हत्या

प्रेस कांफ्रेंस में सलमा नामक महिला ने अपने पति की हत्या का मामला उठाते हुए कहा कि उनके शौहर ड्रग्स के खिलाफ लोगों को जागरूक करते थे। उनकी हत्या कर दी गई। सलमा के अनुसारः हत्या के आरोपी जेल में हैं, लेकिन ड्रग्स नेटवर्क अब भी चल रहा है। उन्होंने कहा कि शिकायत के बावजूद उन्हें पुलिस की ओर से सुरक्षा नहीं मिली। महिला ने दावा किया कि शहर में ब्राउन शुगर का कारोबार अब भी जारी है। पति की हत्या के बाद वह अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर इतनी चिंतित हैं कि उन्हें घर से बाहर निकलने नहीं देतीं। बच्चे पढ़ाई करते हैं और ट्यूशन भी लगा रखी है लेकिन पिता की हत्या के बाद उन्हें हर समय बच्चों की सुरक्षा का डर सताता रहता है।

श्री राय ने कहा कि ड्रग्स और सट्टेबाजी का कारोबार पुलिस की प्रभावी कार्रवाई के बिना लंबे समय तक नहीं चल सकता। जिस दिन पुलिस चाह लेगी, उसी दिन से यह धंधा रुक जाएगा

सरयू राय ने ऑनलाइन सट्टेबाजी को लेकर भी पुलिस से सक्रिय होने की मांग की। उन्होंने कहा कि एआई और डिजिटल तकनीक के दौर में ऑनलाइन सट्टेबाजी युवाओं की पहुंच में और आसान हो गई है। डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन आईडी और इंटरनेट आधारित नेटवर्क के जरिए चल रहे इस कारोबार की साइबर जांच जरूरी है। पुलिस को ऐसे नेटवर्क का स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए।

इंजन में लगी आग, स्कॉर्पियो का अगला हिस्सा जलकर राख

इटकी : प्रखंड के पूर्व उप प्रमुख एवं कांग्रेस नेता नरेश साहू के छोटे भाई दिनेश साहू की महिंद्रा स्कॉर्पियो जेऐच01डीटी -4920 में मंगलवार की रात अचानक आग लग गई। आग लगने से वाहन का अगला हिस्सा बुरी तरह जलकर क्षतिग्रस्त हो गया। जानकारी के अनुसार, नरेश साहू जरिया स्थित शकुंतला फ्यूल सेंटर से वाहन लेकर गढ़गांव स्थित अपने आवास पहुंचे और वाहन को घर के बाहर खड़ा कर अंदर खाना खाने चले गए। इसी दौरान बाहर से वाहन में आग लगने और जलने का शोर सुनाई दिया। आवाज सुनकर घर एवं आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और मोटर चलाकर पानी की मदद से आग बुझाने में जुट गए। स्थानीय लोगों की तत्परता से आग पर काबू पाया गया, जिससे आग को वाहन के अन्य हिस्सों और आसपास फैलने से रोका जा सका।

टाटा स्टील फाउंडेशन कर्मचारियों को मिलेगा 57 हजार रुपये का परफॉर्मेंस रिवॉर्ड

बिभा संवाददाता

जमशेदपुर। टाटा स्टील फाउंडेशन के कर्मचारियों को इस वर्ष 57 हजार रुपये का परफॉर्मेंस रिवॉर्ड दिया जाएगा। इसे लेकर बुधवार को प्रबंधन और टाटा स्टील फाउंडेशन इंप्लाइज यूनियन के बीच समझौता हुआ। समझौते के तहत फाउंडेशन के प्रत्येक कर्मचारी को 57 हजार रुपये की बोनस राशि देने पर सहमति बनी। प्रबंधन और यूनियन के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए। समझौते के दौरान प्रबंधन की ओर से सीईओ सौरव राय, सीओ देवदूत मोहंती, एलटीआर एमडी श्रीनिवास, अविनाश एका, असिस्टेंट मैनेजर कारण सिंह और मैनेजर अक्षय आनंद मौजूद थे। वहीं यूनियन की ओर से अध्यक्ष राकेश्वर पांडे, कार्यकारी अध्यक्ष बीके डिंडा, सलाहकार विजय खान, ददन सिंह, महासचिव अजय प्रताप सिंह मुंडा, संयुक्त सचिव वीरेंद्र टीयू, उपाध्यक्ष आरसी टुडू और सहायक सचिव सुरेंद्र प्रसाद ने समझौते पर हस्ताक्षर किए।

इस अवसर पर यूनियन अध्यक्ष राकेश्वर पांडे ने कहा कि टाटा स्टील फाउंडेशन देश के विभिन्न राज्यों के साथ-साथ टाटा स्टील के माइंस और कोलियरी क्षेत्रों में सामाजिक दायित्व के तहत लगातार बेहतर कार्य कर रहा है। फाउंडेशन के कार्यों का दायरा लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने सीईओ सौरव राय से भविष्य में सीएसआर के क्षेत्र में प्रस्तावित नई योजनाओं की जानकारी भी ली। सीईओ सौरव राय ने कहा कि टाटा स्टील फाउंडेशन समाज की जरूरतों के अनुरूप लगातार नए क्षेत्रों में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि आद उन्होंने कहा कि फाउंडेशन का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास और सामाजिक कार्यों का लाभ पहुंचाना है।

सौरव राय ने यूनियन से सुरक्षा को लेकर भी जागरूकता बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि वाहन चलाते समय हेलमेट, सुरक्षा जूते और सीट बेल्ट समेत अन्य सुरक्षा उपायों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना चाहिए, ताकि कर्मचारी स्वयं सुरक्षित रहें और समाज में भी सुरक्षा का संदेश पहुंचे। राकेश्वर पांडे ने बोनस समझौते के लिए प्रबंधन और कर्मचारियों को धन्यवाद दिया।

सरयू राय ने एनएचएआई को दी सीधी चेतावनी, बोलेः नहीं चेते तो फूटेगा जनाक्रोश

बिभा संवाददाता

जमशेदपुर। जिस एनएच-33 को लेकर कुछ साल पहले आंदोलन की चिंगारी भड़की थी, वही सड़क एक बार फिर धूल, गड्ढों और बदहाली की गिरफ्त में है। मानगो से गुजरने वाले एनएच-33 की हालत देखकर जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने बुधवार को एनएचएआई को सीधे तौर पर चेताया। पारडीह स्थित होटल सिटी इन से बालीगुमा तक सड़क का निरीक्षण करने पहुंचे सरयू राय ने पाया कि सड़क पर सैकड़ों छोटे-छोटे गड्ढे हैं और निमार्णाधीन फ्लाईओवर के कारण पूरे इलाके में धूल का गुबार उड़ रहा है। सड़क की हालत ऐसी है कि गड्ढे भरने के नाम पर डाली गई सामग्री भी वाहन चालकों के लिए परेशानी का कारण बन रही है। सड़क पर उड़ती धूल से राहगीर ही नहीं, बल्कि सड़क किनारे रहने वाले परिवार भी बेहाल हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि धूल घरों के अंदर तक पहुंच रही है और लगातार प्रदूषण के बीच रहना मुश्किल हो गया है।

सरयू राय ने कहा कि एनएच-33 की बदहाली कोई नई बात नहीं है। एक दौर में सड़क की ऐसी ही स्थिति के खिलाफ उनके नेतृत्व में बड़ा आंदोलन हुआ था। उन्होंने याद दिलाया कि रांची स्थित एनएचएआई कार्यालय तक प्रदर्शन हुआ था और तोड़फोड़ की घटनाओं के बाद मुकदमा भी चला था। आज फिर एनएच-33 उसी स्थिति की ओर बढ़ रही है। सवाल यह है कि आखिर एनएचएआई को हर बार सड़क की हालत बिगड़ने के बाद ही क्यों जागना पड़ता है।

सरयू राय ने बताया कि उन्होंने मौके पर एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर से बात की। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने बताया कि उन्होंने अभी दो दिन पहले ही पदभार संभाला है। विधायक ने उन्हें साफ कहा कि जिम्मेदारी संभालने के साथ ही सबसे पहले सड़क पर उड़ रही धूल को रोकने की व्यवस्था करें। लगातार पानी का छिड़काव कराएं, ताकि लोगों को तत्काल राहत मिल सके। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने पानी का नियमित छिड़काव कराने पर सहमति जताई।

सरयू राय ने कहा कि बरसात खत्म हो चुकी है और दशहरा सामने है। ऐसे में लोगों को गड्ढों और धूल के बीच पूजा का मौसम बिताने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। उन्होंने एनएचएआई से स्पष्ट कहा कि केवल गड्ढों में मिट्टी या अन्य सामग्री डालकर खानापूर्ति न की जाए, बल्कि सड़क की बाकायदा पिचिंग कराई जाए। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने आश्वासन दिया कि दो-तीन दिनों में सड़क निर्माण का काम शुरू कराया जाएगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि सड़क लंबी होने के कारण काम पूरा होने में समय लगेगा।

नरकोपी में महिला की हत्या मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित

डीएसपी दीपक कुमार के नेतृत्व में पांच सदस्यीय टीम, नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश

बिभा संवाददाता

बेड़ो। नरकोपी थाना क्षेत्र के मंदरो गांव में 29 सितंबर की शाम महिला की हत्या एवं उसकी बेटी को गंभीर रूप से घायल किए जाने के मामले की जांच के लिए पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है। वरीय पुलिस अधीक्षक, रांची के कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार, डीएसपी बेड़ो दीपक कुमार के नेतृत्व में पांच सदस्यीय विशेष जांच दल गठित किया गया है।

पुलिस के अनुसार, मंदरो निवासी इम्तियाज अंसारी ने प्राथमिकी दर्ज कराई है कि 29 सितंबर को शाम करीब सात बजे वह अपने घर के बाहर सड़क पर था। इसी दौरान अपराधकर्मी उसके घर में घुसे और उसकी मां हकीमन खातून तथा छोटी बहन अफसाना प्रवीण पर हमला कर दिया। घटना में हकीमन खातून की मौत हो गई, जबकि अफसाना प्रवीण गंभीर रूप से घायल हो गईं। घायल का इलाज रिम्स, रांची में चल रहा है।

मामले को लेकर नरकोपी थाना कांड संख्या 25/26, दिनांक 30 सितंबर 2026 को भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

घटना की गंभीरता को देखते हुए गठित एसआईटी में पुलिस निरीक्षक उत्तम कुमार उपाध्याय, बेड़ो थाना प्रभारी मो. कफिल अहमद, लापुंग थाना प्रभारी गोविंद कुमार, नरकोपी थाना प्रभारी शैलेन्द्र टूडू तथा तकनीकी शाखा के सहायक अवर निरीक्षक बलेन्द्र कुमार को शामिल किया गया है।

आदेश में टीम को आपसी समन्वय के साथ अनुसंधान, साक्ष्य संकलन एवं घटना में शामिल नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। डीएसपी बेड़ो को प्रतिदिन एसआईटी द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा कर वरीय पुलिस अधीक्षक, रांची को अवगत कराने का निर्देश भी दिया गया है।

पुलिस के अनुसार, मामले में अनुसंधान जारी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम कार्रवाई कर रही है।

डीएवी विवेकानंद पब्लिक स्कूल बेड़ो में 'विकसित भारत' पर चित्रकला व भाषण प्रतियोगिता, विजेता पुरस्कृत

बिभा संवाददाता

बेड़ो। डीएवी विवेकानंद पब्लिक स्कूल, बेड़ो के प्रांगण में 'विकसित भारत कैसा हो' विषय पर चित्रकला एवं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर अपनी रचनात्मकता और विचारों के माध्यम से विकसित भारत की परिकल्पना को प्रस्तुत किया।

चित्रकला के माध्यम से विद्यार्थियों ने देश के उज्ज्वल भविष्य के सुंदर चित्र उकेरे, वहीं भाषण प्रतियोगिता में शिक्षा, तकनीक, पर्यावरण संरक्षण, स्वावलंबन और विकास जैसे अहम मुद्दों पर प्रभावशाली विचार रखे।

भाषण प्रतियोगिता में भावेश कुमार ने प्रथम, कृति रानी ने द्वितीय और अनुराग सिंह ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं चित्रकला प्रतियोगिता में दिव्यांका शाह प्रथम, अदिति कुमारी द्वितीय और श्रेयांश जायसवाल तृतीय स्थान पर रहे। कार्यक्रम के संयोजक सह भाजपा मीडिया प्रभारी रंजन गुप्ता, प्रधानाध्यापक कैलाश कुमार एवं प्रबंधक श्रवण कुमार ने विजेता प्रतिभागियों को मेडल व प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया।

एसआईआर के विरोध में झामुमो का प्रदर्शन, सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग

बिभा संवाददाता

रांची। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर झारखंड में सियासी हलचल तेज हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने बुधवार को रांची में लोकभवन के समक्ष प्रदर्शन कर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की। पार्टी ने एसआईआर की प्रक्रिया और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।

झामुमो रांची जिला एवं महानगर समिति के आह्वान पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहले रांची विश्वविद्यालय फुटबॉल मैदान में जुटे। इसके बाद कार्यकताओं ने लोकभवन की ओर मार्च किया। प्रदर्शन के दौरान कुछ कार्यकर्ता ऊंट पर सवार होकर भी पहुंचे। इस दौरान लोकतंत्र की हत्या बंद करो, चुनाव आयोग जवाब दो और एसआईआर रद्द करो जैसे नारे लगाए गए।

राज्यसभा सांसद महुआ माजी ने दावा किया कि बांग्ला भाषी नागरिकों को दस्तावेजों के नाम पर उलझाकर उनके मताधिकार को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने चुनाव आयोग से एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की।

विधायक अमित महतो ने चुनाव आयोग की निर्णय प्रक्रिया को लेकर सामने आई कथित आपत्तियों का मुद्दा उठाते हुए दावा किया कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में विभिन्न फैसलों को लेकर 14 बार लिखित आपत्तियां दर्ज कराई हैं।

झामुमो रांची महानगर के संयोजक प्रमुख मुश्ताक आलम ने आरोप लगाया कि एसआईआर की प्रक्रिया के नाम पर रांची के अलावा संथाल परगना, पूर्वी सिंहभूम और कोयलांचल जैसे क्षेत्रों में लोगों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया में पारदर्शिता और वास्तविक मतदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा की मांग कर रही है।

झामुमो ने मांग की कि मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी हो और किसी वास्तविक मतदाता का नाम उचित सत्यापन तथा अपना पक्ष रखने का अवसर दिए बिना नहीं हटाया जाए। पार्टी ने चेतावनी दी कि मांगों पर कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।

प्रदर्शन में राज्यसभा सांसद महुआ माजी, विधायक अमित महतो, मुश्ताक आलम, अंतु तिर्की सहित खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा और अन्य जिलों से आए झामुमो कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी शामिल हुए।

चेंबर ने स्पीकर से मुलाकात कर व्यापारिक विकास के लिए सौंपा ज्ञापन

बिभा संवाददाता

रांची। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रबीन्द्र नाथ महतो से बुधवार को उनके कार्यालय कक्ष में फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष तुलसी पटेल के नेतृत्व में चेंबर के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की।

इस अवसर पर चेंबर के उपाध्यक्ष विकास विजयवर्गीय, कोषाध्यक्ष नवजोत अलंग, संयुक्त सचिव अमित शर्मा और संयुक्त सचिव पूजा ढाढा उपस्थित थीं।

मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने स्पीकर को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका अभिनंदन किया।

इसके बाद राज्य के औद्योगिक और व्यापारिक विकास को गति देने के उद्देश्य से एक ज्ञापन भी सौंपा।

ज्ञापन में मुख्य रूप से झारखंड के नगर निकायों में होल्डिंग टैक्स की दरों, राज्यो की खासमहल से अच्छादित भूमि, व्यापारिक संस्थान प्रतिष्ठान की सुरक्षा इसके अलावा ट्रेड लाइसेंस व्यवस्था की समीक्षा सहित अन्य मुद्दों पर प्रस्ताव दिए गए हैं। स्पीकर ने ज्ञापन पर सकारात्मक रुख व्यक्त करते हुए कहा कि इस पर विधिसम्मत करवाई के लिए वे सरकार को प्रेषित कर देंगे।

संक्षिप्त खबरें

मुख्यमंत्री ने अनुसेवक के सेवानिवृत्ति पर दी शुभकामनाएं

रांची(बिभा)। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में पदस्थापित अनुसेवक अंगद महतो के सेवानिवृत्त होने पर उन्हें भावभीनी विदाई दी और उनके उज्जवल भविष्य एवं उत्तम स्वास्थ्य की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अनुसेवक को शॉल ओढ़ाकर, स्मृति चिन्ह एवं उपहार भेंट कर सम्मानित किया। मौके पर अंगद महतो ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के सरल और संवेदनशील स्वभाव के कारण सेवाकाल के दौरान हमेशा एक सुगम और आत्मीय माहौल मिला, जिसे वे जीवन भर याद रखेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे, जिन्होंने अंगद महतो को उनके सुखद भविष्य के लिए बधाई दी।

मतदाता साक्षरता क्लब का शुभारंभ

रांची(बिभा) : झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, रांची में बुधवार को जागरूक मतदाता, सशक्त लोकतंत्र विषय पर मतदाता साक्षरता क्लब का शुभारंभ विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ० हेमेन्द्र कुमार भगत द्वारा किया गया। भारत निर्वाचन आयोग के स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत स्थापित इस क्लब का उद्देश्य युवाओं एवं भावी मतदाताओं में मताधिकार, निर्वाचन प्रक्रिया एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूकता विकसित करना है। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों एवं उपस्थित सदस्यों ने जागरूक, जिम्मेदार एवं नैतिक मतदाता वनने की शपथ ली। इस अवसर पर डॉ. अलका सिंह को क्लब की नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया। कार्यक्रम में डॉ. कृति, संकाय सदस्यगण एवं छात्र-छात्राएँ उपस्थित रहे। मतदाता साक्षरता क्लब युवाओं में निर्वाचन संबंधी जागरूकता बढ़ाने, मतदान के महत्व को समझाने तथा लोकतांत्रिक भागीदारी को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

विधानसभा सचिवालय में सुरेन्द्र कुमार को भावभीनी विदाई

रांची(बिभा)। झारखण्ड विधानसभा सचिवालय में बुधवार को विदाई समारोह का आयोजन कर विधानसभा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी सुरेन्द्र कुमार को भावभीनी विदाई दी गई। विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि सुरेन्द्र कुमार ने 13 फरवरी 1990 को बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग में सरकारी सेवक के रूप में अपने सेवाकाल की शुरूआत की थी। स्वास्थ्य विभाग में सेवा देने के बाद उन्होंने एक अक्टूबर 2007 को झारखण्ड विधानसभा सचिवालय में सहायक के पद पर योगदान दिया। अपनी योग्यता, कार्यदक्षता तथा सौहार्दपूर्ण एवं हंसमुख स्वभाव के कारण सुरेन्द्र कुमार ने विधानसभा के सभी पदाधिकारी और कर्मियों के बीच अपना विशिष्ट स्थान बनाया। विदाई समारोह के दौरान अधिकारी-कर्मचारियों ने उनके सेवानिवृत्ति के उपरांत स्वस्थ, दीघार्यु एवं सुखमय जीवन की कामना की। इस अवसर पर विधानसभा सचिवालय के प्रभारी सचिव रंजीत कुमार ने कहा कि किसी भी संस्थान की कार्यप्रणाली को सुचारु रूप से संचालित करने में कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सुरेन्द्र कुमार ने अपने सेवाकाल के दौरान सौंपे गए दायित्वों का निष्ठा एवं जिम्मेदारी के साथ निर्वहन किया है। उन्होंने उनके स्वस्थ एवं सुखमय जीवन की कामना की। समारोह में मुख्य रूप से विधानसभा सचिवालय के प्रभारी सचिव रंजीत कुमार सहित पदाधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद थे।

गांधी जयंती पर बंद रहेंगी मांस-मछली की दुकानें

रांची(बिभा)। गांधी जयंती के अवसर पर 02 अक्टूबर को नगर निगम क्षेत्र के सभी मांस, मछली की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। इस दौरान इनकी खरीद-बिक्री पर भी रोक रहेगी। नगर निगम के अपर नगर आयुक्त की ओर से बुधवार को जारी निर्देश में कहा गया है कि 02 अक्टूबर को मांस, मछली या मुर्गा की बिक्री करते हुए कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निगम ने संबंधित दुकानदारों से आदेश का पालन सुनिश्चित करने को कहा है।

झारखंड में 2 से 7 अक्टूबर तक मनेगा 72वां वन्यजीव सप्ताह, होंगे कई आयोजन

बिभा संवाददाता

रांची। झारखंड में 02 से 07 अक्टूबर तक 72वां वन्यजीव सप्ताह मनाया जाएगा। इस दौरान वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से राज्यभर में प्रभात फेरी, वॉकथॉन, बर्ड वॉचिंग और विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य आम लोगों व युवाओं को वन्यजीवों और उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण से जोड़ना है।

सप्ताह की शुरूआत 02 अक्टूबर को डोरंडा स्थित पलाश हॉल में राज्य स्तरीय उद्घाटन, प्रभात फेरी और वॉकथॉन के साथ होगी। 3 अक्टूबर को संरक्षित क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान, शैक्षणिक भ्रमण और बर्ड वॉचिंग कराई जाएगी। 04 अक्टूबर को प्रधान मुख्य वन संरक्षक रांची में 10 किलोमीटर वॉकथॉन की शुरूआत करेंगे। इसके बाद 5 अक्टूबर को जिला स्तर पर स्कूली बच्चों और युवाओं के लिए पेंटिंग, ड्राइंग और निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। कार्यक्रम के तहत 6 अक्टूबर को होटल बीएनआर चाणक्य में अंतर-एजेंसी समन्वय बैठक बुलाई गई है। इसमें वन्यजीव अपराधों पर रोक लगाने और रेल व बिजली लाइनों से होने वाली दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए पुलिस, रेलवे, विद्युत तथा पशुपालन विभाग के साथ रणनीति बनेगी।

इसी दिन मानव-वन्यजीव संघर्ष कम करने के उद्देश्य से कॉरिडोर संरक्षण पर कार्यशाला और फोटोग्राफी प्रदर्शनी भी आयोजित होगी। 7 अक्टूबर को समापन समारोह के साथ सप्ताह भर चलने वाले इन अभियानों का समापन होगा। मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) संजीव कुमार ने आम नागरिकों, विद्यार्थियों, पर्यावरण प्रेमियों और स्वयंसेवी संस्थाओं से इन आयोजनों में सक्रिय रूप से शामिल होने का आग्रह किया है।

सेवानिवृत्ति के दिन छह शिक्षकों को मिले सभी रिटायरमेंट बेनिफिट

बिभा संवाददाता

रांची। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को समाहरणालय सभागार में पेंशन दरबार सह सेवानिवृत्ति सम्मान समारोह आयोजित किया गया।

इस दौरान सेवानिवृत्त होने वाले छह शिक्षकों को सम्मानपूर्वक विदाई दी गई और सेवानिवृत्ति के दिन ही सभी रिटायरमेंट बेनिफिट प्रदान किए गए।

इस अवसर पर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने शिक्षकों के सेवाकाल और योगदान की सराहना करते हुए कहा कि शिक्षक बच्चों की शिक्षा के साथ उनके व्यक्तित्व निर्माण और बेहतर समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने सभी सेवानिवृत्त शिक्षकों को स्वस्थ एवं सुखद जीवन की शुभकामनाएं दीं।

समारोह में राजकीय मध्य विद्यालय बुढ़मू के प्रधानाध्यापक प्रदीप भगत, उत्क्रमित उच्च विद्यालय उरुगुट्ठ, कांके के सहायक शिक्षक पोखराज प्रसाद सिन्हा, राजकीय मध्य विद्यालय बीआईटी मेसरा, कांके की सहायक शिक्षिका पैशेंस तिर्की, राजकीय मध्य विद्यालय सिमलिया, रातू की सहायक शिक्षिका गीता कुमारी, राजकीय मध्य विद्यालय हेहल, रातू की सहायक शिक्षिका संगीता रानी और राजकीय मध्य विद्यालय हिन्दू यूनाइटेड, रांची-2 की सहायक शिक्षिका नूर बाखला को सम्मानित किया गया।

जिला प्रशासन के अनुसार, उपायुक्त के निर्देश पर जनवरी 2025 से सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के दिन ही सभी देय लाभ उपलब्ध कराने की व्यवस्था लागू है। यह पेंशन दरबार-सह-सेवानिवृत्ति सम्मान समारोह का 21वां संस्करण था।

समारोह में जिला शिक्षा अधीक्षक बादल राज सहित शिक्षा विभाग के पदाधिकारी एवं कर्मी मौजूद थे।

सीसीएल ने 84 सेवानिवृत्त कर्मियों को दी गई विदाई

बिभा संवाददाता

रांची। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) मुख्यालय रांची में बुधवार को सम्मान समारोह आयोजित कर सितंबर 2026 में सेवानिवृत्त होनेवाले कर्मियों को सम्मानपूर्वक विदाई दी गई। मुख्यालय से सेवानिवृत्त आठ कर्मियों समेत सीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों से 84 कर्मियों को उनके-अपने कार्यक्रमों में सम्मानित किया गया।

मुख्यालय से सेवानिवृत्त होनेवालों में महाप्रबंधक (ईएंडएम) सुचंद्रा सिन्हा, महाप्रबंधक (ईएंडटी) संतोष कुमार सिंह, मुख्य प्रबंधक (वित्त) रंधीर कुमार सिंह, मुख्य प्रबंधक (मानव संसाधन) गौतम चौधरी, प्रबंधक (खेल) आदिल हुसैन, ओएस ग्रेड-ए1 अनिल कुमार सहनी, मुख्य फार्मासिस्ट कमलेश पंडित और चपरासी मोहन तांती शामिल थे।

इस अवसर पर सीएमडी निलेंदु कुमार सिंह ने सेवानिवृत्त कर्मियों के वर्षों के अनुभव और समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि उनके योगदान ने सीसीएल की कार्य संस्कृति और प्रगति को मजबूत किया है। उन्होंने सभी को नई जीवन-यात्रा के लिए शुभकामनाएं दीं। सभी कर्मियों को शॉल, पुष्पगुच्छ और स्मृति-चिह्न भेंट कर सम्मानित किया गया। मौके पर सेवानिवृत्त कर्मियों के सेवाकाल के अनुभवों और स्मृतियों पर आधारित लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई।

समारोह में सीसीएल के सीएमडी निलेंदु कुमार सिंह, निदेशक (वित्त) पवन कुमार मिश्रा, निदेशक (मानव संसाधन) हर्ष नाथ मिश्र और मुख्य सतर्कता अधिकारी पंकज कुमार सहित विभिन्न विभागों के महाप्रबंधक, विभागाध्यक्ष, अधिकारी, कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मियों के परिजन मौजूद थे।

सीसीएल एनके क्षेत्र में दो दिवसीय अंतर क्षेत्रीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता संपन्न, एनके क्षेत्र बना ओवरऑल चैंपियन

बिभा संवाददाता

रांची : सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) के एनके क्षेत्र में आयोजित दो दिवसीय अंतर क्षेत्रीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता का भव्य समापन हुआ। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सीसीएल के निदेशक (मानव संसाधन) हर्ष नाथ मिश्र उपस्थित रहे, जिन्होंने विजेता टीमों को पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन किया।

समारोह को संबोधित करते हुए निदेशक (एचआर) हर्ष नाथ मिश्र ने कहा कि कला और संस्कृति हमारी परंपराओं व सांस्कृतिक विरासत को संजोने का सशक्त माध्यम हैं। कोयला उद्योग में ऐसे आयोजनों से कोल कर्मियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है और आपसी सहयोग व जुड़ाव मजबूत होता है।

प्रतियोगिता का शुभारंभ एनके क्षेत्र के महाप्रबंधक अमिताभ कुमार तिवारी द्वारा किया गया था। दो दिनों तक चले इस आयोजन में प्रतिभागियों ने भजन, गजल, रवींद्र संगीत, लोकगीत, कथक, ओडिसी, कव्वाली, वाद्य संगीत और लोक नृत्य जैसी विविध विधाओं में मनमोहक प्रस्तुतियां देकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर अंतर क्षेत्रीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता में एनके क्षेत्र ने ओवरऑल प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि पिपरवार क्षेत्र द्वितीय और हजारीबाग क्षेत्र तृतीय स्थान पर रहा। इस अवसर पर सीसीएल के स्पोर्ट्स मैनेजर आदिल हुसैन, वरीय अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे।

मोरहाबादी में सात दिवसीय जेसीआई एक्सपो उत्सव की शुरूआत आज से, लगेंगे देश-विदेश के 400 स्टॉल्स

बिभा संवाददाता

रांची। युवा सामाजिक और व्यापारिक संगठन जेसीआई (जुनियर चेंबर इंटरनेशनल) के बहुप्रतीक्षित आयोजन 'एक्सपो उत्सव 2026' की शुरूआत एक अक्टूबरब से होगी। 07 अक्टूबर तक चलनेवाला यह उत्सव रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित होगी। इस वर्ष इस बहुप्रतीक्षित व्यापार मेले की 29 वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस मेले में देश-विदेश के कई स्टॉल लगते हैं।

यह जानकारी बुधवार को एक्सपो के चीफ कोऑर्डिनेटर जेसी एचजीएफ सीए प्रशांत पाटोदिया ने प्रेस वार्ता में दी।

उन्होंने बताया की सात दिनों के इस उत्सव में कुल 400 स्टॉल्स देश के वभिन्न शहरों से लगेंगे, जिसमे बड़े ब्रांड्स, स्टार्ट अप्स, ऑटोमोबाइल्स, ड्राई फ्रूट्स के स्टॉल्स लगेंगे। साथ ही एक्ससपो के दौरान महिलाओं के लिए एक समर्पित पिंक हेंगर लगाया गया है, जिसमें सिर्फ महिला उद्यमियों को स्टाल्स लगाए जा रहे हैं। प्रशांत पाटोदिया ने बताया कि एक्सपो में बच्चों के लिए एम्यूजमेंट पार्क है, जिसमें तरह तरह के झूले लगे हैं।

एक्सपो के दौरान एक्सपपो परिसर में प्रतिदिन प्रतियोगिताएं होंगी। गुरुवार को बच्चों के लिए जूनियर मास्टरशेफ प्रतियोगिता आयोजित की जायेगी, जिसमें बच्चों की ओर से कई प्रकार के व्यंजन बनाये जाएंगे और पुरस्कृत किये जाएंगे। वहीं दो अक्टूबर को चित्रकला प्रतियोगिता, ट्रेसर हंट और तम्बोला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। तीन अक्टूबर को डॉग शो और वौइस् ऑफ एक्सपो, चार अक्टूबर को एक्सपो टैंक और डांस प्रतियोगिता एवं अंतिम दिन सात अक्टूबर को योगा प्रतियोगिता तथा बुटिक्स एक्सपो फैशन शो का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस बार क्यूआर कोड के मदद से एक्सपो के दौरान जो इवेंट्स हो रहे हैं, उसमें लोग रजिस्टर कर सकते हैं और एंट्री टिकट भी बुक कर सकते हैं।

पाटोदिया ने बताया कि इस बार रांचीवासियों के लिए तीन अक्टूबर को नाइट मार्केट का आयोजन किया जा रहा है। इसमें रात्रि 09 बजे से रात के 12 बजे तक सभी स्टाल्स खुले रहेंगे और लाइव बैंड भी होगा। वहीं छह अक्टूबर को भजन जैमिंग का आयोजन होगा, जिसमें बाहर से आये कलाकार मधुर भजन प्रस्तुत करेंगे।

एक्सपो उत्सव 2026' के इस संस्करण का मुख्य स्पांसर पंचरत्न स्काईलाइन है, जबकि आयोजन के पावर्ड टैंगो, अल्पाइन और गृहस्थी हैं। वहीं आयोजन को सफल बनाने के लिए रांची कई बड़े ब्रांड्स सहयोगी के रूप में जुड़े हैं। इनमें होटल चाणक्य (हॉस्पिटैलिटी पार्टनर), मोशन (एजुकेशन पार्टनर), बुद्धा टोयोटा (ऑटोमोबाइल पार्टनर), श्री अलंकार (ज्वेलरी पार्टनर), श्नाइडर इलेक्ट्रिक (इलेक्ट्रिक पार्टनर), प्रभुजी (फूड पार्टनर), वॉव डिटेलिंग (डिटेलिंग पार्टनर), बागला (सिक्योरिटी पार्टनर) बलीफिया (फोटोग्राफी पार्टनर), एनटीपीसी (माइनिंग पार्टनर सहित अन्य हैं। मौके पर जेसीआई के संयोजक जेसी सिद्धार्थ चौधरी, रांची चैप्टर के मीडिया प्रभारी जेसी रवि सामोता, अध्यक्ष सीए अभिषेक जैन, सचिव जेसी साकेत अग्रवाल, को-ऑर्डिनेटर्स जेसी सौरभ जालान, जेसी राहुल टिबरेवाल, जेसी सौरव नारेडी, जेसी सीए दीपक पटेल सहित अन्य मौजूद थे।

पूर्व मध्य रेल
खुली ई-निविदा सूचना
विविध वैद्युतिक कार्य हेतु (विद्युत सामान्य विभाग)
मंडल रेल प्रबंधक (विद्युत) पूर्व मध्य रेल, धनबाद द्वारा भारत के राष्ट्रपति की तरफ से निम्नलिखित कार्यो के निष्पादन के लिए ई–निविदा आमंत्रित की जाती है:–
ई–निविदा सं.– ईएल/22/खुली/2026–27
1. कार्य का नाम, स्थान एवं समापन अवधि: SSE/PTRU के अधिकार क्षेत्र में लगे विंडो टाइप एयर कंडीशनर, स्प्लिट टाइप एयर कंडीशनर, वॉटर कूलर और रेफ्रिजरेटर मशीनों के लिए तीन साल का व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध। (कार्य समापन अवधि– 36 माह) 2. कार्य के लिए प्राक्कलित राशि: रू. 54,05,490.69/– 3. बिड सिक्योरिटी: रू. 1,08,100.00/–
ई–निविदा सं.– ईएल/23/खुली/2026–27
1. कार्य का नाम, स्थान एवं समापन अवधि: धनबाद डिवीजन में अलग–अलग जगहों पर यात्रियों और स्टाफ की सुरक्षा के लिए हाई मास्ट, लाइट पोस्ट, वॉटर कूलर और दूसरे इलेक्ट्रिकल सामानों के लिए RCCB/ELCB की व्यवस्था। (कार्य समापन अवधि– 12 माह) 2 . कार्य के लिए प्राक्कलित राशि: 1,18,34,964.32/– 3.. बिड सिक्योरिटी : रू. 2,36,700.00/– बिड मूल्यांकन प्रणाली: एक पैकेट प्रणाली। ई–निविदा बंद होने एवं खुलने की तिथि एवं समय: ई–निविदा बंद होने की तिथि दिनांक 16.10.2026 को 11:00 बजे। ई–निविदा खुलने की तिथि दिनांक 16.10.2026 को 11.30 बजे के बाद। वेबसाइट का विवरण www.ireps.gov.in ई–निविदा के तहत मैन्युअल प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
वरीय मंडल विद्युत अभियंता (सा.)/पूर्व मध्य रेल, धनबाद
पीआर/1023/डीएचएन/ईएलईसीटी/टी/26–27/44

साइबर अपराधियों को अवैध सिम बेचने वाले दो पीओएस एजेंट गिरफ्तार

बिभा संवाददाता

चंदनकियारी (बोकारो)। साइबर अपराधियों को अवैध तरीके से सिम कार्ड उपलब्ध कराने के मामले में बरमसिया ओपी पुलिस और चंदनकियारी थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने दो पीओएस एजेंटों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में प्रदीप दास (27), पिता पांडव दास, निवासी बोरियाडीह दास टोला, थाना चंदनकियारी तथा मुकेश गोप (20), पिता नीतीश गोप, निवासी गम्हरिया, थाना चंदनकियारी शामिल हैं। दोनों पर साइबर अपराधियों को नियमों का उल्लंघन

कर सिम उपलब्ध कराने का आरोप है।

पुलिस के अनुसार, 29 सितंबर 2026 को बरमसिया ओपी को वरीय पदाधिकारी से सूचना मिली थी कि पीओएस एजेंट प्रदीप दास ने जुलाई से अगस्त के बीच 140 से अधिक सिम, जबकि पीओएस एजेंट मुकेश गोप ने 42 सिम साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराए हैं। इन सिम का इस्तेमाल साइबर अपराध, वित्तीय धोखाधड़ी और अन्य आपराधिक गतिविधियों में किए जाने की सूचना थी।

सूचना के बाद बरमसिया ओपी प्रभारी और चंदनकियारी थाना प्रभारी के नेतृत्व में जांच टीम गठित की गई। पुलिस ने दोनों पीओएस एजेंटों से पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में दोनों ने बताया कि वे दूसरे लोगों के आधार कार्ड और फिंगरप्रिंट लेकर सिम एक्टिवेट करते थे और उन्हें पमित माहथा निवासी साबड़ा, थाना सियालजोरी, बोकारो, राहुल कुमार निवासी देवघर तथा विवेक चौधरी निवासी संथालडीह, पश्चिम बंगाल को उपलब्ध कराते थे। इसके बदले प्रत्येक सिम के लिए 800 रुपये मिलने की बात सामने आई है।

पुलिस के अनुसार, इन सिम का इस्तेमाल फर्जी अकाउंट बनाने और फोन के माध्यम से लोगों से ठगी करने में किया जाता था। ठगी से प्राप्त रकम में कथित तौर पर सभी को हिस्सा मिलता था।

पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से सैमसंग गैलेक्सी ए 17 5जी मोबाइल, दो एयरटेल सिम कार्ड तथा रियल मी 12एक्स5जी मोबाइल बरामद किया है। रियलमी मोबाइल में एयरटेल और जियो के सिम लगे हुए थे।

इस मामले में साइबर थाना कांड संख्या 39/2026, दिनांक 29 सितंबर 2026 दर्ज किया गया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 111 बीएनएस, आईटी एक्ट की धारा 66(सी), 66(ओ) तथा टेलीकॉम एक्ट की धारा 42(3)(ई) के तहत कार्रवाई की है। छापेमारी दल में बरमसिया ओपी प्रभारी पुअनि शैलेन्द्र कुमार, चंदनकियारी थाना प्रभारी पुअनि अमित कुमार राय, आरक्षी-302 मनोज कुमार मिश्रा और आरक्षी-172 सचिन बेसरा शामिल थे।

पुलिस का कहना है कि साइबर अपराध पर कार्रवाई के साथ-साथ साइबर अपराधियों को अवैध तरीके से सिम उपलब्ध कराने वालों के खिलाफ भी टेलीकॉम एक्ट के तहत कार्रवाई जारी है।

चंद्रपुरा हत्याकांडः मेदांता में इलाजरत रोहित ने तोड़ा दम

मां-बाप के बाद बेटे की भी मौत

बिभा संवाददाता

बोकारो. चंद्रपुरा डीवीसी कॉलोनी के पश्चिमपल्ली स्थित क्वार्टर में 17 सितंबर को हुई गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल रोहित सिन्हा की बुधवार सुबह रांची के मेदांता अस्पताल में मौत हो गयी. इसके साथ ही इस गोलीकांड में मरने वालों की संख्या तीन हो गयी. घटना में रोहित के पिता नरेश सिन्हा और मां रेणु देवी की मौके पर ही मौत हो गयी थी. रोहित का पिछले 13 दिनों से रांची में इलाज चल रहा था.

गर्दन में फंसी गोली नहीं निकाली जा सकी

गोलीबारी में रोहित को चार से अधिक गोलियां लगी थीं. इलाज के दौरान सिर में फंसी गोली निकाल ली गयी थी. कमर और जांघ में लगी गोलियां भी चिकित्सकों ने निकाल दी थीं. हालांकि, गर्दन में फंसी गोली को नहीं निकाला जा सका. गंभीर स्थिति में उसका इलाज जारी था, इसी बीच बुधवार को उसकी मौत हो गयी.

17 सितंबर को घर में घुसकर हुई थी फायरिंग

17 सितंबर की देर शाम पश्चिमपल्ली स्थित क्वार्टर एच/एम-14 में अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की थी. इसमें नरेश सिन्हा और उनकी पत्नी रेणु देवी की मौत हो गयी, जबकि उनका बेटा रोहित गंभीर रूप से घायल हो गया था. प्रारंभिक जांच में पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए थे और मामले की वजह व हमलावरों की पहचान के लिए अलग-अलग पहलुओं से जांच शुरू की थी.

घटना के बाद रोहित को पहले चंद्रपुरा अस्पताल ले जाया गया. गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बोकारो जनरल अस्पताल रेफर किया गया. अगले दिन बेहतर इलाज के लिए रांची के मेदांता अस्पताल भेजा गया था. अब उसकी मौत के बाद पुलिस के सामने मामले की जांच की चुनौती और बढ़ गयी है.

13वें दिन भी हत्याकांड का खुलासा नहीं

इधर, हत्याकांड के 13वें दिन तक पुलिस हमलावरों की पहचान और घटना के कारण का खुलासा नहीं कर सकी थी. पुलिस और एसआइटी अलग-अलग पहलुओं से जांच कर रही थी. जांच के दौरान घटनास्थल से मिले साक्ष्य, दस्तावेज और अन्य सुरागों को खंगाला जा रहा था.

पुलिस को उम्मीद थी कि रोहित के स्वस्थ होने और बयान देने की स्थिति में आने पर घटना से जुड़े महत्वपूर्ण सुराग मिल सकते हैं. उसकी मौत के बाद यह संभावना भी खत्म हो गयी है. अब पुलिस को घटनास्थल से मिले साक्ष्यों, तकनीकी जांच और अन्य उपलब्ध सुरागों के आधार पर ही हत्याकांड की कड़ियां जोड़नी होंगी.

संक्षिप्त खबरें

तुपकाडीह में ट्रक ने वेल्डिंग मिस्त्री को कुचला, मौत

बोकारो(बिभा)। बुधवार को दोपहर के समय एक कोयला लदे ट्रक ने तुपकाडीह के वेल्डिंग का काम करने वाले मिस्त्री को सिनेमा हॉल के समीप बुरी तरह से कुचल दिया। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने उसे बोकारो जेनरल अस्पताल ले गए जहां उसकी मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने जैनामोड़ फुसरो मेनरोड को जाम कर दिया। स्तिथि से निबटने के लिए जरीडीह थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। बताया जाता है कि 40 बर्षीय हिदायतुल्लाह अंसारी नमाज पढ़ने के बाद अपने घर आ रहा था इसीबीच घटना घटी।ग्रामीणों ने बताया कि तेज रफ्तार ट्रक हिदायतुल्लाह को कुचलने के बाद भागने लगा जिसे दो युवकों ने बाइक से पीछा कर पकड़ा। गाड़ी खलासी चला रहा था जो पकड़ा गया लेकिन चालक फरार हो गया। रोड जाम होने के कारण भारी वाहन , स्कूलों की बसें , बिहार , बंगाल से आने जाने वाली बसें घंटों तक रुकी रहीं।

लोन विवाद में युवक पर चाकू व अस्तूरे से जानलेवा हमला, हालत गंभीर

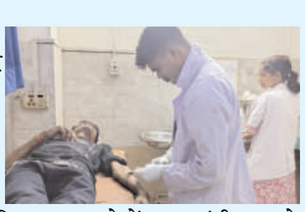

बोकारो (बिभा): बोकारो स्टील सिटी थाना क्षेत्र के सेक्टर 1उ में मंगलवार की देर शाम लोन के लेनदेन को लेकर हुई रंजिश में तीन अपराधियों ने एक युवक पर अस्तूरे और चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे पुलिस की मदद से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार, सेक्टर 1सी निवासी करण राम ने किसी व्यक्ति से लोन ले रखा था। मंगलवार शाम करीब तीन अज्ञात युवकों ने फोन करके करण को उसके घर के बाहर बुलाया। करण जैसे ही घर से बाहर निकला, पहले से घात लगाए तीनों युवकों ने उस पर अस्तूरे और चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले में करण राम के गर्दन और दोनों हाथों पर गहरे जख्म आए हैं। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही बोकारो स्टील सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जख्मी युवक को मेडिकल प्रतिवेदन जारी कर तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भेजा। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है और आरोपियों की पहचान के लिए कॉल डिटेल्स व आसपास के क्षेत्रों की पड़ताल कर रही है।

गंभीर औद्योगिक अशांति को न्योता दे रहा है वर्तमान बीएसएल प्रबंधनः कुमार अमित

बोकारो(बिभा)। भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य और भारतीय उद्योग मजदूर संघ के महामंत्री कुमार अमित ने वर्तमान बीएसएल प्रबंधन के रवैये पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि प्रबंधन आत्ममुग्धता में लीन है और अपने ही कार्य शैली से सभी स्टेकहोल्डर्स को एक साथ चुनौती दे रहा है। श्री अमित ने कहा कि एक ओर प्रबंधन सेक्टर-12 के क्षतिग्रस्त ब्लॉक के नाम पर अपने ही नियमित कर्मचारियों को जबरन गैर-पसंदीदा आवासों में शिफ्ट कर रहा है, वहीं दूसरी ओर इसी प्लांट में अपनी पूरी जवानी खपाने वाले सैकड़ों सेवानिवृत्त कर्मियों को परिवार सहित सड़क पर उतरने को मजबूर कर दिया है। प्रबंधन की कार्यशैलियों ने विस्थापित अप्रेंटिसों को भी उनके हक के लिए बार-बार सड़क पर उतरने को विवश किया है। 39 माह के बकाया एरियर को रोककर प्रबंधन ने अपने नियमित कर्मचारियों को भी अपने विरोध में खड़ा कर लिया है। इतना ही नहीं, प्लॉटधारियों की दुकानों को बिना किसी ठोस कारण के तोड़ा जा रहा है, जिससे बोकारो के व्यापारी वर्ग में भी भारी आक्रोश है। कर्मचारियों के छोटे-मोटे निर्माण को नियमों का हवाला देकर तोड़ा जा रहा है, वहीं अधिकारियों/कर्मचारियों को जबरन रिटायरमेंट का भय दिखाया जा रहा है। ठेका श्रमिकों के मामले में भी प्रबंधन का दोहरा चरित्र सामने आ रहा है। जो ठेका कर्मी 'कट मनी' नहीं लौटा रहे हैं, उन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है, जबकि विस्थापितों के मुद्दों पर कोई सार्थक वार्ता नहीं हो रही है। श्री अमित ने आरोप लगाया कि वर्तमान प्रबंधन कुछ चुनिंदा मजदूर संगठनों के साथ साठ-गांठ कर बैठक का कोरम पूरा दिखाकर मंत्रालय को दिग्भ्रमित कर रहा है। वर्तमान प्रबंधन अपने इस रवैये के कारण कर्मचारियों, रिटायर्ड कर्मचारियों, ठेका मजदूरों, विस्थापितों, अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं, प्लॉटधारियों, व्यापारियों, ठेकेदारों सहित सभी स्टेकहोल्डर्स को एक साथ चुनौती दे रहा है। प्रबंधन की जिम्मेदारी है कि संवाद का द्वार खुला रखे और बेहतर औद्योगिक संबंध कायम करे। श्री अमित ने कहा। उन्होंने कहा कि बोकारो के हजारों लोगों ने अपने प्रिय प्रधानमंत्री को पोस्टकार्ड लिखकर स्थगित विस्तारीकरण को फिर से बोकारो की धरती पर लाया है। यदि इसी प्रकार औद्योगिक अशांति बढ़ती रही तो राष्ट्रीय इस्पात नीति-2017 के तहत बोकारो का प्रस्तावित विस्तारीकरण प्रभावित होगा, जो न केवल बोकारो के लिए, बल्कि प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने पर भी कुठाराघात होगा।

बोकारो में सेक्टर-12 के आवास खाली कराने के आदेश पर भड़के कर्मी, ईडी आवास का किया घेराव

बिभा संवाददाता

बोकारोः बीएसएल (बोकारो स्टील प्लांट) प्रबंधन द्वारा सेक्टर-12 के आवासों को खाली कराने के आदेश के खिलाफ कर्मचारियों का आक्रोश फूट पड़ा है। बुधवार को 'आवास बचाओ संघर्ष मोर्चा', पूर्व कर्मचारियों और लाइसेंसधारी कर्मियों ने एकजुट होकर बीएसएल के अधिशासी निदेशक (ईडी) के आवास का घेराव किया। प्रदर्शन के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए प्रबंधन ने ईडी आवास के आसपास दो लेयर की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी है।

क्या है पूरा मामला?

बीएसएल प्रबंधन ने सेक्टर-12 स्थित कई आवासों को अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों और लाइसेंसधारियों को आवंटित किया था। हाल ही में प्रबंधन ने इन भवनों की स्थिति को अत्यंत जर्जर बताते हुए इन्हें 'असुरक्षित क्षेत्र' घोषित कर दिया और खाली करने का नोटिस जारी कर दिया। हालांकि, प्रबंधन की ओर से प्रभावित कर्मियों को सेक्टर-8 और सेक्टर-11 में वैकल्पिक आवास देने की बात कही गई है।

आवासधारकों का विरोध और आरोप

प्रदर्शन कर रहे आवासधारकों का कहना है कि प्रबंधन द्वारा विकल्प के रूप में दिए जा रहे मकानों की स्थिति सेक्टर-12 के आवासों से भी ज्यादा जर्जर है।

भाजपा नेत्री एंजेला सिंह ने प्रबंधन के रुख को तानाशाही करार देते हुए कहा, ₹या तो कर्मियों को बेहतर स्थिति वाले आवास आवंटित किए जाएं या फिर सेक्टर-12 के वर्तमान आवासों की ही मरम्मत कराई जाए। जब तक ठोस समाधान नहीं निकलता, कोई भी आवास खाली नहीं किया जाएगा।₹

वहीं, स्थानीय निवासी पम्मी कुमारी ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा, ₹हम किसी कीमत पर अपने मकान खाली नहीं करेंगे। ईडी मैडम को यह मनमाना फरमान वापस लेना होगा, वरना हमारा आंदोलन यहीं जारी रहेगा।₹

फिलहाल, एक ओर जहां बीएसएल प्रबंधन हर हाल में जर्जर मकानों को खाली कराने पर अड़ा हुआ है, वहीं दूसरी ओर आवासधारक और उनके परिजन आर-पार की लड़ाई के मूड में हैं। इस गतिरोध के कारण क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है।

बीएसएल के ईडी आवास के घेराव के दौरान बवाल, आंदोलनकारियों और पुलिस में झड़प

महिला प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग का आरोप, एक महिला की तबीयत बिगड़ी; बीजीएच में भर्ती

बिभा संवाददाता

बोकारो। बोकारो स्टील प्लांट में आवास आवंटन से जुड़े विवाद को लेकर बुधवार को सेक्टर-4 स्थित अधिशासी निदेशक (ईडी) के आवास के बाहर प्रदर्शन के दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो गई। आवास का घेराव कर रहे आंदोलनकारियों और पुलिस व सुरक्षा कर्मियों के बीच तीखी झड़प हो गई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए बल प्रयोग किए जाने का आरोप है। घटना में महिला आंदोलनकारियों के साथ धक्का-मुक्की और हाथापाई की बात सामने आई है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आंदोलनकारी अपनी मांगों को लेकर ईडी आवास के बाहर जुटे थे। पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने का प्रयास किया। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच कहासुनी बढ़ गई और देखते ही देखते स्थिति झड़प में बदल गई। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों को हटाने के दौरान महिला आंदोलनकारियों पर भी बल प्रयोग किया गया।

मारपीट का वीडियो वायरल

घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें महिला प्रदर्शनकारियों के साथ धक्का-मुक्की और कथित मारपीट के दृश्य दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद मामले को लेकर स्थानीय लोगों और कर्मचारियों में नाराजगी की चर्चा है। हालांकि, वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है।

एक महिला की तबीयत बिगड़ी झड़प और धक्का-मुक्की के दौरान एक महिला आंदोलनकारी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। आनन-फानन में उन्हें इलाज के लिए बोकारो जनरल अस्पताल (बीजीएच) ले जाया गया, जहां उन्हें भर्ती कर उपचार किया जा रहा है।

डीवीसी कॉलोनी में दिनदहाड़े चोरी का खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार

बिभा संवाददाता

चंद्रपुरा। डीवीसी कॉलोनी में दिनदहाड़े हुई चोरी की घटना का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर उद्भेदन करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से चोरी के कुछ सामान और 5,500 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। मामले में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है।

पुलिस के अनुसार, 29 सितंबर 2026 को दिन के समय क्वार्टर संख्या एफ/डी-05, डीवीसी कॉलोनी, चंद्रपुरा में चोरी की घटना हुई थी। मामले को लेकर चंद्रपुरा थाना कांड संख्या 112/2026, धारा 331(3)/305 बीएनएस के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। घटना के शीघ्र उद्भेदन के लिए पुलिस टीम गठित की गई।

जांच के दौरान अज्ञात चोरों की तलाश में छापेमारी करते हुए पुलिस ने कमला माता मंदिर पहाड़ी के

पास से बिरसाबस्ती निवासी रोहित कुमार (26), पिता अर्जुन यादव और विजय कुमार (22), पिता संजू बाउरी को गिरफ्तार किया।

पुलिस ने आरोपियों के पास से दो जोड़ी चांदी जैसी पायल, तीन चांदी जैसे सिक्के बरामद किए। इसके अलावा रोहित कुमार की दाहिनी जेब से 3,000 रुपये और विजय कुमार की दाहिनी जेब से 2,500 रुपये नकद बरामद किए गए।

पुलिस के अनुसार, रोहित कुमार के खिलाफ चंद्रपुरा थाना में वर्ष 2024 में चोरी से संबंधित दो मामले दर्ज हैं। इनमें कांड संख्या 48/2024, धारा 457/380 भादवि तथा कांड संख्या 49/2024, धारा 457/380 भादवि शामिल हैं।

वहीं विजय कुमार के खिलाफ चंद्रपुरा थाना कांड संख्या 130/2024, धारा 317(5)/3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज है।

छापेमारी दल में चंद्रपुरा थाना प्रभारी पु.अ.नि. श्रीनिवास कुमार सिंह, दुग्धा थाना प्रभारी पु.अ.नि. अमन कुमार, चंद्रपुरा थाना के पु.अ.नि. कुंदन कुमार पासवान, पु.अ.नि. प्रवीण महतो तथा चंद्रपुरा थाना रिजर्व गार्ड शामिल थे।

45 से अधिक लंबित मांगों को लेकर बीएकेएस ने किया प्रदर्शन

एसएमएस न्यू विभाग के सीजीएम कार्यालय के समक्ष कर्मचारियों ने जताया विरोध, आंदोलन के अगले चरण में आमरण अनशन व मौन जुलूस का ऐलान

बिभा संवाददाता

बोकारो। सेल कॉर्पोरेट स्तर पर लंबित कर्मचारियों की मांगों और विभिन्न मुद्दों के समाधान की मांग को लेकर बीएसएल अनाधिशासी कर्मचारी संघ (इअङर) ने अपने द्वितीय चरण के आंदोलन के तहत एसएमएस न्यू विभाग के मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम) कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में विभाग के बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने हिस्सा लिया।

यूनियन का कहना है कि बीएसएल कर्मचारियों से जुड़े 45 से अधिक मुद्दे सेल कॉर्पोरेट स्तर पर, जबकि 60 से अधिक मामले बोकारो इस्पात संयंत्र स्तर पर लंबित हैं। वेज रिवीजन-2017, एरियर, बोनस फॉर्मूला, एनजेसीएस में सुधार और ग्रेच्युटी सहित विभिन्न मांगों को लेकर बीएकेएस समेत कई यूनियनों की ओर से अलग-अलग न्यायालयों में मामले भी दायर किए गए हैं।

प्रदर्शन के दौरान यूनियन नेताओं ने कहा कि कर्मचारियों से जुड़ी कई सुविधाएं या तो बंद हैं या लंबे समय से उनमें संशोधन नहीं हुआ है। इससे कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। यूनियन ने लंबित मांगों के शीघ्र समाधान की मांग की। सभा को संबोधित करते हुए यूनियन के कोषाध्यक्ष राहुल प्रसाद साव ने कर्मचारियों से आंदोलन के अगले चरण में प्रस्तावित आमरण अनशन और मौन जुलूस को समर्थन देने की अपील की। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की मांगों के समाधान के लिए अब निर्णायक आंदोलन की जरूरत है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस्पात मंत्रालय से लेकर सरकार तक की निष्क्रियता के कारण प्रबंधन के स्तर पर कर्मचारियों की मांगें लंबे समय से लंबित हैं।

बोनस सब कमेटी को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कमेटी के गठन और प्रतिनिधित्व को लेकर कर्मचारियों के बीच असंतोष है। प्रदर्शन के दौरान महासचिव हरिओम, अध्यक्ष दिलीप कुमार, उपाध्यक्ष कृष्ण रजवार, उपमहासचिव माणिक मुंडा, उपकोषाध्यक्ष देवेंद्र कुमार सहित यूनियन कार्यकारिणी के सदस्यों ने भी अपने विचार रखे।

यूनियन के विभागीय प्रतिनिधि अजय कुमार ने कहा कि प्रस्ताव और फॉर्मूला प्रबंधन की ओर से तय किए जा रहे हैं तथा प्रतिनिधित्व की व्यवस्था में भी बदलाव की जरूरत है। उन्होंने कहा कि एनजेसीएस से लेकर सेल कॉर्पोरेट स्तर तक व्यापक बदलाव के लिए कर्मचारियों को आंदोलन का रास्ता अपनाना होगा।

डैमेज क्वार्टरों के बदले शानदार ढंग से रिपेयर और रेनोवेट क्वार्टर देगा बीएसएल

बिभा संवाददाता

बोकारो। सेक्टर-12 के जिन 149 ब्लॉक्स के 1242 आवासों को एनआईटी पटना के विशेषज्ञों ने स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्वे के बाद खतरनाक और असुरक्षित घोषित किया था, उन्हें खाली कराकर सुरक्षित जगह पर बसाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। विशेषज्ञों का साफ कहना है कि ये मकान अब सिर्फ मामूली मरम्मत के सहारे टिकने वाले नहीं हैं, इसलिए यहाँ रहना किसी बड़े जोखिम से कम नहीं है।

प्रबंधन ने वैद्य अवसधारियों की सहूलियत और सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए चरणबद्ध तरीके से सभी वैध कब्जाधारियों को दूसरे वैकल्पिक आवास आवंटित कर दिए हैं। हालांकि, सार्वजनिक और व्यक्तिगत नोटिस जारी किए जाने के बाद भी उम्मीद के मुताबिक लोगों ने शिफ्टिंग में गति नहीं दिखाई है। इस पर बीएसएल के सीओसी मणिकांत धान ने स्थिति साफ करते हुए कहा है कि नए आवंटित आवासों को प्राथमिकता के आधार पर शानदार ढंग से रिपेयर और रेनोवेट कराया जा रहा है, ताकि आपको रहने में कोई असुविधा न हो। कई नव-आवंटित मकान तो पूरी तरह बनकर तैयार हैं और उनके ताले खुलते ही आपका नया घर आपका स्वागत करने को तैयार है। बीएसएल प्रबंधन ने एक बार फिर सभी प्रभावित परिवारों से अपील की है कि वे किसी भी संशय या शंका के समाधान के लिए उचित फोरम पर बातचीत का रास्ता अपनाएं और प्रबंधन का सहयोग करें। हादसों का इंतजार करने के बजाय, नए और सुरक्षित घर में जितनी जल्दी हो सके शिफ्ट होकर अपनों के जीवन को सुरक्षित बनाएं।

सांसद कालीचरण सिंह की अध्यक्षता में दिशा की बैठक संपन्न: विकास योजनाओं में तेजी और स्थानीय युवाओं को रोजगार देने पर जोर

बिभा संवाददाता

लातेहारः सांसद,चतरा लोकसभा क्षेत्र, कालीचरण सिंह की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोआर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमिटी(डीडीसीएमसी) दिशा की समीक्षात्मक बैठक का आयोजन समाहरणालय सभागार में किया गया।

बैठक के दौरान पूर्व में हुए दिशा की बैठक में दिए गए निदेर्शों के आलोक में हुए कार्यों की अनुपालन प्रतिवेदन की बिंदुवार समीक्षा की गई। विभिन्न विभागों द्वारा पूर्व में दिए गए निदेर्शों के आलोक में की गई कार्रवाई, प्रगति एवं लंबित मामलों की जानकारी ली गई। अनुपालन प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि बालुमाथ के पंचायत मारंगलोईया के ग्राम विशुनपुर में अवस्थित बोरिंग जिसमें सालोभर जल की उपलब्धता मात्र 1एचपी लगभग रहता है।

लघु सिंचाई प्रमंडल से संबंधित मामले पर चर्चा करते हुए सांसद द्वारा आवश्यक जांच कराते हुए वस्तुस्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया गया। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, लातेहार को कमिटी गठित कर स्थल जांच एवं मामले की विस्तृत जांच कराने का निर्देश दिया गया। उन्होंने जांच के दौरान योजना की व्यवहार्यता, स्थल की स्थिति एवं सिंचाई सुविधा से संबंधित सभी बिंदुओं का समुचित परीक्षण करते हुए जांच प्रतिवेदन समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

विद्युत आपूर्ति की समीक्षा के दौरान ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विद्युत व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने तथा विद्युत बाधित होने की स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। वहीं शिक्षा से संबंधित मामलों में विद्यालयों में पाठ्य-पुस्तकों की उपलब्धता एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। पथ निर्माण से संबंधित समीक्षा में कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, लातेहार को लातेहार से बालुमाथ पथ तथा अन्य पथों में अनावश्यक एवं अनुपयोगी स्पीड ब्रेकर को हटाने तथा सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। जिले में संचालित विभिन्न खनन कंपनियों में स्थानीय युवक-युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराने से संबंधित कार्रवाई की भी समीक्षा की गई। जिला नियोजन पदाधिकारी द्वारा खनन कंपनियों से प्राप्त पत्राचार एवं स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु की जा रही कार्रवाई की जानकारी दी गई। माननीय सांसद द्वारा खनन कंपनियों के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया कि स्थानीय लोगों, विशेषकर योग्य युवक-युवतियों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिले में संचालित कंपनियों में उपलब्ध रोजगार के अवसरों का लाभ स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर मिलना चाहिए।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को खनन कंपनियों के साथ समन्वय स्थापित कर रोजगार मेला एवं भर्ती कैंप के माध्यम से स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोड़ने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही कंपनियों में उपलब्ध रोजगार के अवसरों की जानकारी जिला प्रशासन को उपलब्ध कराने को कहा गया, ताकि योग्य स्थानीय अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिल सके।

बैठक में भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामलों की भी समीक्षा की गई तथा लंबित मामलों में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। साथ ही ग्रामीण विकास, राष्ट्रीय राजमार्ग, विद्युत विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सामाजिक सुरक्षा, वन, दूरसंचार, बैंकिंग, आवास, मनरेगा, जल संसाधन एवं अन्य विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की गई। संबंधित विभागों के पदाधिकारियों ने योजनाओं की अद्यतन स्थिति, उपलब्धियों एवं लंबित कार्यों की जानकारी प्रस्तुत की। सांसद कालीचरण सिंह ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन एवं विभागों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी विभागों को विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में गति लाने, लंबित कार्यों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने तथा गुणवत्ता के साथ कार्य संपादित करने का निर्देश दिया। उन्होंने जनहित से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करने तथा विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर बल दिया।इस दौरान सांसद ने कहा कि स्थानीय विधायक एवं जनप्रतिनिधियों के द्वारा उठाये गए जनहित के मुद्दों पर संवेदनशील होकर कार्य करें तथा जनहित में योजना विलंब न हो और गुणवत्तापूर्ण कार्य हो, योजनाओं का कियान्वयन ससमय हो इसे विभागीय पदाधिकारी सुनिश्चित करें। उपायुक्त संदीप कुमार ने सांसद को आश्वस्त किया कि बैठक में प्राप्त सुझावों एवं निदेर्शों के अनुरूप सभी विभागों द्वारा आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी तथा योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए नियमित अनुश्रवण किया जाएगा। बैठक में राज्य सभा सांसद बैद्यनाथ राम, विधायक, लातेहार, प्रकाश राम, विधायक, मनिका रामचन्द्र सिंह, उपायुक्त संदीप कुमार , पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव , उप निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, उत्तरी प्रमंडल कुमार आशीष, उप निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, दक्षिणी प्रमंडल ब्रजेश कांत जेना, जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रवेश अग्रवाल, जिला परिषद अध्यक्ष पूनम देवी, उप विकास आयुक्त सैय्यद रियाज अहमद, नगर पंचायत अध्यक्ष महेश सिंह, अपर समाहर्ता सलमान जफर खिजरी, अनुमंडल पदाधिकारी लातेहार, अनुमंडल पदाधिकारी महुआडांड़, सांसद प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि, जिला स्तरीय पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी,सभी अंचलाधिकारी सहित अन्य उपस्थित थे।

सीओ से कथित दुर्व्यवहार मामले में कार्रवाई नहीं होने पर झासा ने जताई नाराजगी

1 अक्टूबर को काला बिल्ला लगाकर विरोध, 5 अक्टूबर तक कार्रवाई नहीं हुई तो चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी

बिभा संवाददाता

हजारीबाग। सदर अंचलाधिकारी सह खास महाल पदाधिकारी आशुतोष कुमार के साथ 18 सितंबर को हुई कथित अभद्रता के मामले में अब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं होने पर झारखंड राज्य प्रशासनिक सेवा संघ (झासा), हजारीबाग जिला इकाई ने नाराजगी जताई है। संघ का कहना है कि घटना के 12 दिन बाद भी प्राथमिकी दर्ज नहीं होना प्रशासनिक अधिकारियों के मनोबल और प्रशासनिक व्यवस्था की छवि को प्रभावित करने वाला है। घटना को लेकर संघ की ओर से पहले भी कार्रवाई की मांग की गई थी।

जिला इकाई की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 1 अक्टूबर 2026 को हजारीबाग जिले के सभी झारखंड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी काला बिल्ला लगाकर सांकेतिक विरोध दर्ज करते हुए कार्य करेंगे। संघ ने अपनी राज्य कार्यकारिणी से इस विरोध को राज्यव्यापी समर्थन देने और अन्य जिलों के पदाधिकारियों को भी काला बिल्ला लगाकर विरोध दर्ज कराने के लिए निर्देशित करने का अनुरोध किया है। इससे पूर्व बुधवार को जिले के वरीय पदाधिकारी पुलिस अधीक्षक और उपायुक्त से मिलकर त्वरित कार्रवाई की मांग को लेकर पुनः ज्ञापन सोपा गया। वहीं, 5 अक्टूबर तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं होने पर केंद्रीय कार्यकारिणी के साथ समन्वय स्थापित कर आगे की रणनीति तय की जाएगी। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि यदि 5 अक्टूबर तक ठोस कार्रवाई नहीं होती है, तो झारखंड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी राज्य कार्यकारिणी के साथ समन्वय कर चरणबद्ध आंदोलन करने को बाध्य होंगे। संघ ने अन्य जिला इकाइयों से भी इस आंदोलन में समर्थन की अपेक्षा की है।

हजारीबाग में यातायात पुलिस का सख्त अभियान

दो दिनों में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर 385 वाहन चालकों का कटा चालान, 10 वाहन क्रेन से जब्त

बिभा संवाददाता

हजारीबाग : पुलिस अधीक्षक अमन कुमार के निर्देश पर हजारीबाग जिला मुख्यालय में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 28 और 29 सितंबर को एक विशेष वाहन चेकिंग और जागरूकता अभियान चलाया गया। डीएसपी सीसीआर मो अयातुल्लाह के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने शहर के प्रमुख चौक-चौराहों पर औचक निरीक्षण किया।इस अभियान के दौरान शहर के इंद्रपुरी चौक, डॉ. गली, आनंद चौक, कांग्रेस चौक, गुरु गोविंद सिंह रोड, पैगोडा चौक, मेन रोड, झंडा चौक, खाजा चौक, सांसद महोदय मोड़, सुंदरी मार्केट, पंच मंदिर चौक, छोटी ग्वालटोली, सुजात चौक, सरदार चौक और वंशीलाल चौक जैसे व्यस्त इलाकों को कवर किया गया।अभियान मे बिना हेलमेट 103 मामले ट्रिपल लोडिंग के 33 मामले,मोबाइल का उपयोग करते हुए वाहन चलाने के 10 मामले,नो पार्किंग जोन में 239 ऑटो, टोटो व अन्य वाहन पकड़े गए। क्रैन द्वारा 10 वाहन उठाये गए।पुलिस ने नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें टो मशीन (छोटा क्रेन) के जरिए उठाया और चालान काटा। यातायात थाना प्रभारी अनुप कुमार ने वाहन चालकों को सख्त चेतावनी दी है कि नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। प्रशासन की इस कार्रवाई से शहर के वाहन चालकों में हड़कंप मच गया है।

संक्षिप्त खबरें

नवनिर्मित कम्पोजिट कंट्रोल भवन का सांसद ने कि किया उद्घाटन

लातेहार(बिभा): प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना डीएमएफटी मद के तहत अनुमंडल परिसर स्थित नवनिर्मित कम्पोजिट कंट्रोल भवन का विधिवत उद्घाटन चतरा सांसद, कालीचरण सिंह, राज्यसभा सांसद बैद्यनाथ राम, विधायक प्रकाश राम, मनिका रामचंद्र सिंह , उपायुक्त संदीप कुमार, पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव, जिला परिषद अध्यक्ष पूनम देवी, उप विकास आयुक्त सैय्यद रियाज अहमद एवं गणमान्य द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। उद्घाटन के पश्चात सांसद, विधायक गण, जनप्रतिनिधियों एवं उपायुक्त ने नवनिर्मित कंट्रोल भवन का अवलोकन किया तथा वहां उपलब्ध सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं की जानकारी ली। कंट्रोल रूम के माध्यम से प्रशासनिक गतिविधियों की निगरानी, सूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान एवं विभिन्न कार्यों के प्रभावी समन्वय में सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर उपस्थित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को कंट्रोल रूम का सुचारू एवं प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।मौके पर जिला प्रशासन के संबंधित पदाधिकारी, कर्मी एवं अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।

बनहरदी में पीवीयूएनएल कोल ब्लॉक को लेकर ग्राम सभा संपन्न, वनाधिकार अधिनियम पर हुई चर्चा

लातेहार/चंदवा (बिभा)। प्रस्तावित पीवीयूएनएल बनहरदी कोल ब्लॉक के संबंध में बुधवार को वनाधिकार अधिनियम के तहत अनापत्ति प्रमाण-पत्र से जुड़े विषय पर ग्राम बनहरदी में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। ग्राम सभा का आयोजन चंदवा अंचलाधिकारी के नेतृत्व में किया गया। ग्राम सभा में बनहरदी गांव के ग्रामीणों के अलावा ग्राम प्रधान, मुखिया एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस दौरान चंदवा अंचलाधिकारी ने ग्रामीणों को वनाधिकार अधिनियम के प्रावधानों, प्रक्रिया एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र से संबंधित विषयों की विस्तार से जानकारी दी। ग्राम सभा के दौरान ग्रामीणों को अपनी बात रखने का अवसर दिया गया। ग्रामीणों ने अपने-अपने विचार एवं सुझाव ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत किए। वहीं संबंधित अधिकारियों ने ग्रामीणों की बातों को सुना और आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई।कार्यक्रम में चंदवा अंचल के संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी तथा पीवीयूएनएल के अधिकारी भी मौजूद रहे। ग्राम सभा की पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। ग्रामीणों ने अंचलाधिकारी द्वारा दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक सुना और ग्राम सभा में सक्रिय रूप से भाग लिया। ग्राम सभा के शांतिपूर्ण आयोजन में स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं ग्रामीणों का महत्वपूर्ण सहयोग रहा।

हत्या और साक्ष्य छुपाने के आरोपी को आजीवन कारावास एवं जुर्माना

लातेहार(बिभा) : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेषनाथ सिंह की अदालत ने सत्रवाद संख्या 146/24 की सुनवाई करते हुए आरोपी संतोष उराव को हत्या एवं शव को छुपाने का आरोप साबित पाया. जिला अभियोजन पदाधिकारी समित प्रकाश के अनुसार मामले की प्राथमिकी सूचक दिनेश सिंह ने लातेहार थाना कांड संख्या 24/24 दर्ज कराया था.सूचक दिनेश सिंह ने प्राथमिकी में बताया था कि अभियुक्त संतोष उरांव महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार कर रहा था. जिसको लेकर उपेंद्र सिंह विरोध किया था. आरोपी ने उपेंद्र सिंह को टारगेट करते हुए उसकी हत्या कर दिया यह बात घरवालों को तब पता चला जब 14 फरवरी 24 से उपेंद्र सिंह घर से गायब हो गया. उसके घर वाले जब खोजबीन किया तो दो दिनों के बाद उसकी लाश मिली. शव मिलने के बाद परिवार के सूचक दिनेश सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था. श्री सिंह की अदालत में मामले के विचारण पूरी होने पर आरोप साबित होने पर आरोपी संतोष उरांव को धारा 302 भादवि के तहत सश्रम आजीवन कारावास एवं 50000 का जुमार्ना भादवि की धारा 201 के तहत शव छुपाने का आरोप सिद्ध होने पर 3 वर्षों का सश्रम कारावास एवं 20000 जुमार्ना की सजा सुनाया।

सिल्ली-मुरी में झारखंड बंद का व्यापक असर, आंदोलनकारियों ने बीडीओ को सौंपा ज्ञापन

बिभा संवाददाता

सिल्लीः झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर बुधवार को झारखंड बंद का असर सिल्ली-मुरी क्षेत्र में पूरी तरह सफल रहा।सुबह से ही आंदोलनकारी सड़कों पर उतर आए और मुख्य मार्गों को जाम कर दिया,जिससे वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और आम जनजीवन प्रभावित हुआ।बंद का नेतृत्व कर रहे झारखंड आंदोलनकारी,किसान और मजदूर एकजुट होकर अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी अनिल कुमार को एक ज्ञापन सौंपा।आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगों में विस्थापितों की कर्जमाफी,उचित मुआवजा, स्थायी रोजगार और पुनर्वास की समुचित व्यवस्था शामिल है।इसके साथ ही उन्होंने विस्थापन आयोग के गठन की मांग को भी प्रमुखता से उठाया।आंदोलनकारियों ने कहा कि जिन्होंने झारखंड राज्य के निर्माण के लिए संघर्ष किया,उन्हें सरकार की ओर से सम्मान पेंशन दी जानी चाहिए। ज्ञापन में झारखंड आंदोलनकारियों के आश्रितों को सरकारी नौकरी में सीधी नियुक्ति देने,26 प्रतिशत खनिज संपदा पर रॉयल्टी का अधिकार देने, सम्मान पेंशन राशि पचास हजार एवं जल जंगल,जमीन की रक्षा की मांग भी शामिल है।साथ ही दिशोम गुरु शिबू सोरेन का नाम गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से अधिसूचित कर झारखंड आंदोलनकारी के रूप में सर्वोच्च सम्मान देने की मांग लंबे समय से की जा रही है। आंदोलनकारियों ने कहा कि इन मांगों को लेकर वे लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है,जिसके कारण उन्हें बंद का आह्वान करना पड़ा।उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर जल्द विचार नहीं किया गया तो 15 नवंबर 2026 से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन और प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे।प्रशासन द्वारा मांगों पर विचार के आश्वासन के बाद बंद को समाप्त किया गया।इस मौके पर लक्ष्मी नारायण महतो,दीनू चौधरी,नरेश चंद्र महतो, जयपाल सिंह ,विशेश्वर महतो, हरिहर महतो,दुर्योधन भोक्ता, शत्रुघ्न महतो,राज किशोर महतो,काबिल अंसारी,प्रकाश महतो,दिनेश कुमार महतो एवं धनीराम महतो समेत सैकड़ो आंदोलनकारी मौजूद रहे।

बड़कागांव थाना का एसपी ने किया निरीक्षण, लंबित कांडों के शीघ्र निष्पादन और फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी का दिया निर्देश

बिभा संवाददाता

हजारीबाग : पुलिस अधीक्षक, हजारीबाग ने बुधवार को बड़कागांव थाना का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाना में अपराध नियंत्रण, विधि-व्यवस्था और लंबित मामलों की स्थिति की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बड़कागांव अमित आनंद, थाना प्रभारी दीपक कुमार सिंह सहित थाना के अन्य पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिसकर्मी उपस्थित थे।

एसपी ने थाना में अपराध नियंत्रण एवं विधि-व्यवस्था से संबंधित विभिन्न संचिकाओं का जायजा लिया और संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने लंबित कांडों, वारंट एवं कुर्की के मामलों की समीक्षा करते हुए इनके शीघ्र निष्पादन का निर्देश दिया।

थाना क्षेत्र में फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने को कहा गया। वहीं, अवैध मादक पदार्थ से जुड़े लंबित मामलों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी को लेकर भी आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। एसपी ने क्षेत्र में नशे के खिलाफ व्यापक जागरूकता अभियान चलाने पर भी जोर दिया।निरीक्षण के दौरान एनटीपीसी एवं अन्य सहयोगी कोल माइंस क्षेत्रों में, जहां खनन और परिवहन का कार्य होता है, लगातार गश्त जारी रखने का निर्देश दिया गया। इसका उद्देश्य लूट, चोरी, डकैती समेत अन्य आपराधिक घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाना है।एसपी ने अवैध बालू, कोयला एवं अन्य प्रकार की तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही क्षेत्र में शांतिपूर्ण विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आम लोगों और जनप्रतिनिधियों के साथ बेहतर समन्वय एवं संबंध बनाए रखने को कहा। उन्होंने थाना में अनुसंधान के लिए लंबित सभी कांडों की समीक्षा कर शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने तथा संगठित अपराध की घटनाओं पर पूर्णतः रोक लगाने के लिए थाना प्रभारी एवं अन्य पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

मंडई खुर्द डंपिंग यार्ड में फिर पहुंचने लगा शहर का कचरा, वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था के बाद माने ग्रामीण

बिभा संवाददाता

हजारीबाग : मंडई खुर्द डंपिंग यार्ड को लेकर ग्रामीणों और नगर निगम के बीच चल रहा विवाद लिखित समझौते के बाद फिलहाल शांत हो गया है। बुधवार से नगर निगम की कचरा गाड़ि जययां फिर मंडई खुर्द के रास्ते डंपिंग यार्ड पहुंचने लगीं। पंचायत भवन में हुई बैठक में ग्रामीणों की मांगों और नगर निगम के आश्वासनों को लिखित रूप दिया गया।समझौते के तहत गांव की मौजूदा सड़क के बजाय वैकल्पिक रास्ता बनाने, डंपिंग यार्ड में कचरा निस्तारण प्लांट जनवरी 2027 तक मशीनरी के साथ शुरू करने, दुर्गंध पर नियंत्रण और ग्रामीणों से जुड़े मामलों को समाप्त करने समेत आठ बिंदुओं पर सहमति बनी है। वैकल्पिक रास्ता बनने तक कचरा वाहनों को गांव के रास्ते से सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही चलाने और धीमी गति रखने की बात कही गई है।ग्रामीणों का कहना है कि करीब आठ फीट चौड़ी सड़क से भारी कचरा वाहनों की आवाजाही और डंपिंग यार्ड की दुर्गंध से लंबे समय से परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया है कि यदि तय समय सीमा में वैकल्पिक रास्ता और कचरा निस्तारण की व्यवस्था शुरू नहीं हुई, तो वे फिर आंदोलन करेंगे। फिलहाल लिखित समझौते के बाद कचरा उठाव शुरू होने से नगर निगम को राहत मिली है, लेकिन अब ग्रामीणों की नजर समझौते में तय कार्यों के समय पर पूरा होने पर है।

मटवारी में सजेगा मां का भव्य दरबार, मैसूर के ललिता पैलेस की दिखेगी झलक

24 वर्षों की आस्था के साथ इस बार कुछ खास करने की तैयारी, 80 फीट ऊंचे पंडाल में विराजेंगी 16 फीट की मां दुर्गा

प्रमोद खण्डेलवाल

हजारीबागः मां दुर्गा की आराधना का पर्व अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन हजारीबाग शहर में दुगार्पूजा की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। शहर के अलग-अलग पूजा पंडालों में कारीगर दिन-रात मेहनत कर भव्य स्वरूप देने में जुटे हैं। हमारे दुगार्पूजा विशेष संस्करण के दूसरे संस्करण में आज पढ़िए मटवारी की शिव शक्ति दुर्गा पूजा समिति की तैयारी और इस वर्ष की खासियत। मटवारी का पूजा मैदान दुगार्पूजा के दौरान हजारीबाग के प्रमुख आकर्षणों में शामिल रहता है। शहर के अलग-अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां मां के दर्शन करने पहुंचते हैं। पूजा-अर्चना के साथ भव्य पंडाल, आकर्षक विद्युत सज्जा, डिजिटल आकर्षण और मेले का आनंद लेने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ती है। इसी लोकप्रियता और वर्षों से चली आ रही परंपरा को आगे बढ़ाते हुए शिव शक्ति दुर्गा पूजा समिति इस बार श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास तैयार कर रही है।

समिति के 24 वर्ष पूरे हो चुके हैं और हर वर्ष की तरह इस बार भी पंडाल की थीम को लेकर विशेष तैयारी की जा रही है। इस वर्ष मटवारी में मैसूर के प्रसिद्ध ललिता पैलेस की झलक देखने को मिलेगी। करीब 80 फीट ऊंचा पंडाल तैयार किया जा रहा है, जिसका निर्माण पिछले करीब दो महीने से लगातार चल रहा है। करीब 18 लाख रुपये की लागत से तैयार हो रहे इस पंडाल को अंतिम रूप देने में कारीगर जुटे हुए हैं। समिति के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह कहते हैं 24 वर्षों से मां दुर्गा की पूजा पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ होती आ रही है। हर वर्ष हमारी कोशिश रहती है कि श्रद्धालुओं को कुछ नया और आकर्षक देखने को मिले। इस बार ललिता पैलेस की थीम पर पंडाल तैयार किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि मां के दर्शन के साथ लोगों को पंडाल भी यादगार लगे। पंडाल के भीतर करीब 16 फीट ऊंची मां दुर्गा की प्रतिमा विराजमान होंगी। प्रतिमा निर्माण पर करीब 4.50 लाख रुपये खर्च किए जा रहे हैं।

सप्तमी, अष्टमी और नवमी को दिन में धूमन आरती का आयोजन किया जाएगा।पारंपरिक ढाक की गूंज के साथ डीजे की व्यवस्था भी रहेगी। आयोजन की अलग-अलग व्यवस्थाओं को संभालने के लिए समिति की 16 लोगों की टीम सक्रिय रहेगी। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी समिति ने विशेष तैयारी की है। करीब 50 सदस्य पहचान पत्र के साथ तैनात रहेंगे।

समिति के सचिव रिंकू वर्मा ने कहा कि मटवारी में पूजा के दौरान शहर के अलग-अलग क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग आते हैं। हमारी प्राथमिकता है कि श्रद्धालुओं को मां के दर्शन में किसी तरह की परेशानी न हो। सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और अन्य व्यवस्थाओं के लिए समिति के सदस्य लगातार सक्रिय रहेंगे।

अब इंतजार उस दिन का है, जब मां दुर्गा का दरबार सजकर तैयार होगा और मैसूर के ललिता पैलेस की भव्यता के बीच मटवारी में आस्था, परंपरा और आकर्षण का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा।

मुरी जंक्शन पर बड़ा हादसा: ट्रैक पार करने के दौरान मालगाड़ी की चपेट में आया युवक, पैर कटा

मुरीः दक्षिण पूर्व रेलवे के मुरी जंक्शन के लाइन नंबर दो पर बुधवार के दिन सुबह लगभग 9 बजे एक व्यक्ति का मालगाड़ी की चपेट में आने से पैर कट गया। गंभीर रूप से जख्मी व्यक्ति का पहचान कुसरुका थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव दरभंगा (बिहार) निवासी राजकिशोर (32) प्लेटफार्म से उतरकर दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए ट्रैक पार कर रहा था इसी क्रम में तेज गति से आ रही मालगाड़ी की चपेट में आने से यह घटना घटी। घटना की सूचना मिलते ही राजकीय रेल थाना और रेलवे सुरक्षा बल के जवान घटनास्थल पर पहुंचकर घायल व्यक्ति को एंबुलेंस के सहारे इलाज हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया जहां प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज हेतु रिम्स भेज दिया गया।

भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी मिलावटखोरी रोकने की व्यवस्था

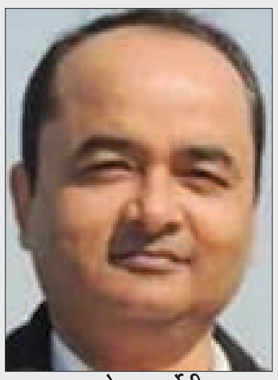

उमेश चतुर्वेदी

महाराष्ट्र की घटनाएं इसलिए सामने आ रही हैं, क्योंकि वहां तेज-तर्रार अधिकारी खाद्य प्रशासन को मिला है। दूसरे इलाकों में ऐसी कार्रवाई नजर नहीं आती। इसका मतलब यह नहीं है कि भारत में मिलावटखोरी बंद हो गई है। इससे शायद ही किसी को इनकार हो कि शुद्ध खाना और दवा प्राप्त करना हर व्यक्ति का अधिकार है।

विडंबना ही कहेंगे कि जिस मिलावटखोरी से हर साल देश में करीब दो लाख लोग मौत की भेंट चढ़ जाते हैं, फिर भी हमारी कानूनी तंत्र इस पर प्रभावी रोक लगाने में नाकाम रहा है। वैसे तो हर साल त्योहारी सीजन के साथ ही मिलावटखोरी की चर्चा तेज हो जाती है। लेकिन इन दिनों इस चर्चा की वजह महाराष्ट्र के तेजतर्रार आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे की कार्रवाई है। मुंढे ने जब से महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी एफडीए के आयुक्त का पद संभाला है, मिलावटखोरों की शामत आ गई है। उन्होंने खाद्य कानूनों और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। महाराष्ट्र एफडीए की टीमों ने शुरूआती 100 दिनों में ही 904 से ज्यादा छापे मारकर 450 से अधिक मिलावटखोरों को गिरफ्तार किया और करोड़ों के मिलावटी खाद्य पदार्थ जब्त किए। इस कार्रवाई से महाराष्ट्र में डिटर्जेंट और रसायनों से बने नकली दूध और ताड़ के तेल से बनने वाले 'एनालॉग पनीर' का रैकेट ध्वस्त हो गया है। नियमों और स्वच्छता मानकों की अनदेखी करने वाले कई नामी फूड चेन्स, बड़े रेस्तराओं आदि के लाइसेंस तक निलंबित या रद्द किए जा चुके हैं।

महाराष्ट्र की घटनाएं इसलिए सामने आ रही हैं, क्योंकि वहां तेज-तर्रार अधिकारी खाद्य प्रशासन को मिला है। दूसरे इलाकों में ऐसी कार्रवाई नजर नहीं आती। इसका मतलब यह नहीं है कि भारत में मिलावटखोरी बंद हो गई है। इससे शायद ही किसी को इनकार हो कि शुद्ध खाना और दवा प्राप्त करना हर व्यक्ति का अधिकार है। ब्रिटेन और अमेरिका में ध्यान रखा जाता है कि उपभोक्ताओं तक वही सामान पहुंचे, जो शुद्ध है। ऐसी व्यवस्था भारत में भी की गई है। 2006 में संसद से पारित खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी एफएसएसएआई का गठन किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत कार्यरत इस संस्था का दायित्व खाद्य पदार्थों के मानकों पर निगाह रखना और उन्हें तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना है। राज्यों की पुलिस, प्रशासन और आपूर्ति अधिकारियों को भी अधिकार है कि वे मिलावटखोरी रोकें। त्योहारी सीजन में ये संस्थाएं कार्रवाइयां करती भी हैं।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, साल 2020 से हर साल करीब एक लाख से अधिक खाद्य नमूनों की जांच की जा रही है। नियमों का उल्लंघन करने पर करीब आठ हजार से ज्यादा खाद्य व्यावसायिक लाइसेंस रद्द भी किए गए हैं। लेकिन देश में इस पर प्रभावी नियंत्रण नहीं लगाया जा सका है। रोक ना लग पाने के पीछे मोटे तौर पर तीन कारण नजर आते हैं। पहला है, मुनाफाखोरी की बढ़ती प्रवृत्ति, दूसरा नैतिकता का क्षरण और तीसरा कारण निश्चित तौर पर प्रशासनिक विफलता और भ्रष्टाचार है।

विनोबा भावे ने करीब आठ दशक पहले लिखे अपने निबंध 'नवयुवकों से दो बातें' में कहा है कि देश में सुराख ही सुराख हैं। उन्होंने राष्ट्ररूपी घड़े में बने इन सुराखों को सदाचार से भरने की अपील की है। कुछ उसी तरह व्यवस्था में अब भी सुराख हैं। हमारे तंत्र के बड़े हिस्से से सदाचार और कर्तव्यपराणयता गायब है। वह राष्ट्र निर्माण के भाव से दूर है। इस वजह से वक्त पर कार्रवाई नहीं होती। कई बार तंत्र को जानकारी होती है कि फलां कारोबारी आटे में पत्थर का सफेद बुरादा मिला रहा है, चावलों में प्लास्टिक के दाने फेंट रहा है, दवाओं के सैंपल में गड़बड़ी कर रहा है, नकली मावे की मिठाई बेच रहा है, जाली शराब बिक रही है। वक्त पर इन गड़बड़ियों की जानकारी होने के बावजूद मुनाफाखोर से मिलने वाली चंद रकम के एवज में वह चुप रह जाता है। भले ही नकली दूध पीने से नागरिक बीमार हो रहा हो या नकली शराब से निर्दोष जान जा रही हो। नैतिकता का क्षरण भी मिलावटखोरी के लिए जिम्मेदार है। नैतिकता की कमी मुनाफाखोर कारोबारी और उत्पादक के साथ तंत्र में भी पैठी हुई है।

सत्ता संभालते वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने तंत्र को चेताया था कि सब चलता है-वाली मानसिकता की अब गुंजाइश नहीं रही। शुरू में इससे ग्रस्त लोगों में भय दिखा, लेकिन अब तंत्र का बड़ा हिस्सा उसी पुराने ढर्रे पर चलता दिखता है, इसलिए मुनाफाखोरों और मिलावटखोरों का डर कम हो चला है। स्वास्थ्य संविधान के समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए इस मामले में केंद्र के साथ राज्य सरकारों को भी कार्रवाई का अधिकार है। ऐसे में तंत्र को प्रभावी और जवाबदेह बनाने के लिए केंद्र और राज्यों की सरकारों को जीरो टालरेंस की नीति अख्तियार करना जरूरी लगता है। तभी मुनाफाखोर, मिलावटखोर और लापरवाह प्रशासनिक तंत्र के पेंच कसे जा सकते हैं।

पड़ोसी देश चीन का मिलावटखोरी रोकने वाला 'फूड सेफ्टी लॉ' दुनिया के सबसे कठोर कानूनों में से एक है। जिसके तहत जानबूझकर खाद्य पदार्थों में खतरनाक मिलावट करने वालों को मृत्युदंड देने का प्रावधान है। चीन में साल 2008 में दूध में मेलामाइन रसायन मिलाने के चर्चित मामले के दोषियों को मौत की सजा दी गई थी। स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाली मिलावटखोरों को इस कानून के तहत आजीवन कारावास के साथ ही भारी आर्थिक जुमार्ने का भी प्रावधान है। चीन में खाद्य नियमों का उल्लंघन करने, घटिया या मानकरहित उत्पाद बेचने और सबूत नष्ट करने वाली कंपनियों और कारोबारियों पर वहां भारी-भरकम जुमार्ना लगाया जाता है। साथ ही व्यवसाय का लाइसेंस रद्द भी किया जाता है।

ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खाद्य सुरक्षा और मिलावटखोरी पर रोक के लिए कड़े कानून हैं। फूड स्टैंडर्ड्स ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड की जवाबदेही है कि वह दोनों देशों के खाद्य मानक तैयार करे। खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने और मिलावटखोरी रोकने के लिए राज्यों के साथ ही स्थानीय निकायों की भी जवाबदेही है। दोनों देशों में खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने, असुरक्षित या मिलावटी भोजन बेचने वाली कंपनियों और निगमों पर भारी जुमार्ने का प्रावधान है। यहां जानबूझकर सार्वजनिक नुकसान या डर फैलाने के इरादे से खाद्य पदार्थों में मिलावट को गंभीर अपराध माना जाता है। ऐसे मामलों में 25 साल तक की जेल हो सकती है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में भी मिलावटखोरी के खिलाफ सख्त और प्रभावी कानून है, जिसे लागू करने की जवाबदेही फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफडीए की है। अमेरिका में मिलावटखोरी पर लगाम के लिए संघीय फूड, ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट है, जो यहां का मुख्य और सबसे बड़ा कानून है। इस कानून के तहत ऐसे खाद्य पदार्थों, दवा या सौंदर्य प्रसाधन को 'मिलावटी' माना जाता है, जो तय मानकों को पूरा नहीं करते या जिसमें हानिकारक पदार्थ मिलाया गया हो। इस कानून के तहत गलत और भ्रामक लेबलिंग पर भी रोक का प्रावधान है। अमेरिका में एक और फूड सेफ्टी मॉडर्नइजेशन एक्ट है, जिसका मकसद मिलावट और संक्रमण को निरोधात्मक कार्रवाई करना है। इन कानूनों के तहत अमेरिका में मिलावटी या दूषित खाद्य पदार्थ और दवाएं बेचना गंभीर अपराध है। इनका उल्लंघन करने वाली कंपनियों और व्यक्तियों पर भारी जुमार्ने, जेल की सजा और उत्पादों को तुरंत नष्ट करने या जब्त करने की व्यवस्था है। अमेरिका की तरह ब्रिटेन में भी खाद्य पदार्थों में मिलावट और धोखाधड़ी रोकने के लिए सख्त कानूनी व्यवस्था है। यहां के फूड सेफ्टी एक्ट के तहत स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भोजन बेचना या तैयार करना गंभीर अपराध है। खाद्य मानकों और मिलावट पर नजर रखने के लिए यहां फूड स्टैंडर्ड एजेंसी है। कुछ इसी अंदाज में हमारे यहां भी कठोर कानून और नियमन की जरूरत है। तभी मिलावटखोरी को रोका जा सकता है और भारतीय नागरिकों को सुरक्षित माहौल मुहैया कराया जा सकता है।

संपादकीय

महिला सुरक्षा का संकट

यह हमारे लोकतंत्र की विडंबना है कि कार्यपालिका की लचर कार्यशैली के चलते गाहे-बगाहे न्यायालय को उन मामलों में हस्तक्षेप करना पड़ता है, जिनका दायित्व निभाना सरकारों का काम है। वैसे कहने को तो पूरे देश में महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा के लिये तमाम कायदे-कानून बनाए गए हैं। लेकिन जब इन कानूनों व योजनाओं को हकीकत में अमलीजामा पहनाने की बात सामने आती है तो जवाबदेही का अंतर साफ नजर आता है। हाल के दिनों में दिल्ली व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में महिलाओं के साथ हुए दुष्कर्म के मामलों पर स्वतः संज्ञान लेकर शीर्ष अदालत ने इस कड़वी हकीकत को उजागर कर दिया। इन मामलों में शीर्ष अदालत ने सिर्फ यही नहीं पूछा कि ये संगीन अपराध क्यों हुए, बल्कि यह भी जानना चाहा कि इन अपराधों को रोकने के लिये बनाया गया सिस्टम क्या हकीकत में कुछ काम करता है? कोर्ट का सवाल था कि क्या वास्तव में आपातकाल में मदद करने वाली हेल्पलाइन तुरंत जवाब देती है? क्या सीसीटीवी कैमरे पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं? क्या महिलाओं के लिये असुरक्षित समझी जाने वाली जगहों को पहचान करके वहां पेट्रोलिंग की जाती है? क्या महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिये बने डेटाबेस, महिलाओं के लिये हेल्प डेस्क और जांच करने में मददगार ट्रैकिंग सिस्टम का कारगर तरीके से प्रयोग हो रहा है? शीर्ष अदालत का यह सवाल तार्किक है कि जब ये सिस्टम फेल हो जाता है तो विफलता के लिये किसी की जवाबदेही तय की जाती है? निस्संदेह, अदालत ने तंत्र की दुखती रग पर हाथ रखा है। सही मायने में ये सवाल हर किसी को परेशान करने वाले हैं। यह हकीकत है कि देश में नये-नये सुरक्षा कार्यक्रमों की घोषणा करने, पोर्टल, हेल्पलाइन और कमेटियां बनाने में तो कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी जाती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी समस्या के निस्तारण के लिये कोई सिस्टम या मैकेनिज्म बना देना ही कर्तव्यों की इतिश्री मान लिया जाए? उल्लेखनीय है कि अक्सर आम लोगों द्वारा शिकायत की जाती रही है कि सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील सड़कों पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं होती, सीसीटीवी कैमरे पूरी तरह से काम नहीं कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर इस बाबत की गई शिकायतें अक्सर फाइलों में उलझकर रह जाती हैं। कहने को ऐसे अपराधों को रोकने वाला सिस्टम फाइलों में तो दर्ज होता है, लेकिन जब वास्तव में किसी व्यक्ति को इसकी जरूरत होती है, तो यह हमेशा की तरह नदारद मिलता है। ऐसे में देश की शीर्ष अदालत द्वारा सुरक्षा उपायों के ऑडिट, व्यवस्था की कमजोरियों की पहचान, किसी घटना के होने पर प्रतिक्रिया देने के समय और कार्यक्षमता के मूल्यांकन पर जोर देना, एक स्वागत योग्य कदम ही कहा जायेगा। सही मायने में ऐसे मामलों में सिर्फ पुलिस को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए।

चिंतन-मनन

कृष्ण हैं परम पुरुष

जीव तथा भगवान की स्वाभाविक स्थिति के विषय में अनेक दार्शनिक ऊहापोह में रहते हैं। जो भगवान कृष्ण को परम पुरुष के रूप में जानता है, वह सारी वस्तुओं का ज्ञाता है। अपूर्ण ज्ञाता परम सत्य के विषय में केवल चिन्तन करता जाता है, जबकि पूर्ण ज्ञाता समय का अपव्यय किये बिना सीधे कृष्णभावनामृत में लग जाता है, अर्थात भगवान की भक्ति करने लगता है। सम्पूर्ण भगवद्गीता में पग-पग पर इस तथ्य पर बल दिया गया है। फिर भी भगवद्गीता के ऐसे अनेक कट्टर भाष्यकार हैं, जो परमेर तथा जीव को एक ही मानते हैं। वैदिक ज्ञान श्रुति कहलाता है, जिसका अर्थ है श्रवण करके सीखना। वास्तव में वैदिक सूचना कृष्ण तथा उनके प्रतिनिधियों जैसे अधिकारियों से ग्रहण करनी चाहिए। यहां कृष्ण ने हर वस्तु का अंतर सुन्दर ढंग से बताया है, अतएव इसी स्त्रोत से सुनना चाहिए। लेकिन केवल सुनना पर्याप्त नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि अधिकारियों से समझे। ऐसा नहीं कि केवल शुष्क चिन्तन ही करता रहे। मनुष्य को विनीत भाव से भगवद्गीता से सुनना चाहिए कि सारे जीव सदैव भगवान के अधीन हैं। जो भी इसे समझ लेता है, वही श्रीकृष्ण के कथनानुसार वेदों के प्रयोजन को समझता है, अन्य कोई नहीं समझता।

भजति शब्द अत्यन्त सार्थक है। कई स्थानों पर भजति का संबंध भगवान की सेवा के अर्थ में व्यक्त हुआ है यदि कोई व्यक्ति पूर्ण कृष्णभावनामृत में रत है, अर्थात भगवान की भक्ति करता है, तो यह समझना चाहिए कि उसने सारा वैदिक ज्ञान समझ लिया है। वैष्णव परंपरा में कहा जाता है कि यदि कोई कृष्ण-भक्ति में लगा रहता है, तो उसे भगवान को जानने के लिए किसी अन्य आध्यात्मिक विधि की आवश्यकता नहीं रहती। वह ज्ञान की समस्त प्रारंभिक विधियों को पार कर चुका होता है। लेकिन यदि कोई लाखों जन्मों तक चिन्तन करने पर भी इस लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाता कि श्रीकृष्ण ही भगवान हैं और उनकी ही शरण ग्रहण करनी चाहिए, तो उसका अनेक जन्मों का चिन्तन व्यर्थ जाता है।

विभिन्न देशों के बीच चल रहे युद्ध का भारत पर प्रभाव

प्रहलाद सबनानी

वैश्विक स्तर पर, विशेष रूप से आर्थिक क्षेत्र में, परिस्थितियां तेजी से रसातल में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। विभिन्न देशों (रूस-यूक्रेन, इजराईल-हम्मास, ईरान-अमेरिका एवं सऊदी अरब-हूथी) के बीच चल रहे युद्ध ने उन देशों के आर्थिक क्षेत्र को भी विपरीत रूप से प्रभावित करना प्रारम्भ कर दिया है, जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में किसी भी प्रकार से नहीं जुड़े हैं। इस श्रेणी के देशों में भारत का नाम सबसे ऊपर उभर कर सामने आ रहा है। दरअसल, भारत अपनी कुल खपत का 85 प्रतिशत से अधिक कच्चा तेल अन्य देशों से आयात करता है। उक्त युद्ध प्रारम्भ होने के बाद से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं एवं यह 100 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर निकल गईं हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यह स्थिति किसी भी कीमत पर उचित नहीं है, क्योंकि भारत को महंगी दरों पर कच्चे तेल का आयात करना पड़ रहा है और इससे महंगे कच्चे तेल के साथ साथ भारत में मुद्रा स्फीति भी आयातित हो रही है। साथ ही, भारत को महंगे कच्चे तेल के आयात का अमेरिकी डॉलर में भुगतान करना होता है, जिससे भारतीय रुपए की कीमत पर अंतरराष्ट्रीय बाजार में दबाव बढ़ता जा रहा है एवं भारतीय रुपए का लगातार अवमूल्यन होता हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीय रुपए के अवमूल्यन से भारत द्वारा आयात किए जाने वाले समस्त उत्पाद महंगे हो जाते हैं।

उक्त वर्णित युद्ध प्रारम्भ होने के पूर्व, भारतीय अर्थव्यवस्था (सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर) वैश्विक स्तर पर अमेरिका, चीन, जर्मनी के पश्चात चौथे स्थान पर पहुंच गई थी। परंतु, अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय रुपए की कीमत में आए परिवर्तन के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक स्तर पर छठे स्थान पर पहुंच गई है, जबकि सकल घरेलू उत्पाद उसी स्तर पर बना रहा है। इसका मुख्य कारण, अंतरराष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी डॉलर का भारतीय रुपए की तुलना में लगातार मजबूत होते जाना है।

जैसे जैसे रूस-यूक्रेन युद्ध और अधिक आक्रामक होता जा रहा है, वैसे वैसे अब यह सम्भावना बलवती होती जा रही है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में गेहूं एवं अन्य खाद्य पदार्थों के दामों में भी भारी वृद्धि देखने में आ सकती है, क्योंकि यूक्रेन गेहूं का बड़ा उत्पादक देश है। यूक्रेन ने रूस के कच्चे तेल को संसाधित कर पेट्रोल एवं डीजल बनाने वाली उत्पादन इकाईयों को भी भारी नुक्सान पहुंचाया है। इससे रूस ने गैस एवं ईंधन की आपूर्ति को यूरोपीयन देशों को स्थगित कर दिया है। सर्दी के मौसम में यूरोपीयन देशों को गैस एवं ईंधन की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। परंतु, इस वर्ष यूरोपीयन देशों को सर्दी के मौसम में गैस एवं ईंधन की आपूर्ति प्रभावित होने वाली है इससे इन देशों के नागरिकों को सबसे अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है।

अमेरिका ने ईरान के साथ युद्ध प्रारम्भ करके विश्व के कई देशों को भारी परेशानी में डाल दिया है। न केवल कच्चा तेल बल्कि फर्टिलाइजर, खाद्य पदार्थ, गैस, आदि की आपूर्ति प्रभावित हुई है। साथ ही, वित्तीय क्षेत्र में भी कई देशों को भारी कठिनाईयों के बीच में धकेल दिया है। यदि यह युद्ध कुछ समय और चलता है, जिसके कि आसार दिखाई दे रहे हैं, तो कई देशों के दिवालिया होने की सम्भावना बनती नजर आ रही है। अमेरिका में मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने के उद्देश्य से यू एस फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में 25 आधार बिंदुओं की बढ़ौतरी की है। अक्टोबर 2026 एवं दिसम्बर 2026 माह में भी पुनः 25 आधार बिंदुओं की वृद्धि की सम्भावना व्यक्त की जा रही है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें उच्च स्तर पर बनी रहने की प्रबल सम्भावना है एवं इसके चलते अमेरिका में भी मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण मुश्किल है। ब्याज दरों में वृद्धि के चलते अमेरिका में यू एस बांड यील्ड में भी लगातार वृद्धि हो रही है एवं यह अपने लगभग उच्चतम स्तर 5.25 प्रतिशत तक पहुंच गई है। बांड यील्ड के उच्च स्तर पर पहुंचने के चलते अमेरिकी निवेशक तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं से अपना निवेश निकाल कर अमेरिकी बांड में निवेश कर रहे हैं क्योंकि अपेक्षाकृत यह सुरक्षित निवेश है एवं ब्याज दर भी अधिक मिल रही है। भारत जैसी तेजी से आगे बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं के लिए यह स्थिति ठीक नहीं है। भारत सहित अन्य विकासशील देशों से निकल रहे विदेशी निवेश से इन देशों की अपनी मुद्रा का अवमूल्यन हो रहा है, जिससे इन देशों में विभिन्न पदार्थों के आयात महंगे हो रहे हैं एवं इन देशों में मुद्रा स्फीति फैलने का खतरा उत्पन्न हो गया है। भारत सहित इन विकासशील देशों को भी मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने के उद्देश्य से ब्याज दरों में वृद्धि करनी होगी। कुल मिलाकर अमेरिका ने ईरान के साथ युद्ध प्रारम्भ कर विश्व के कई देशों के लिए विशेष रूप से आर्थिक क्षेत्र में समस्याएं खड़ी कर दी हैं।

भारत अभी तक तो अपनी आर्थिक सेहत को सम्हाले हुए है, क्योंकि भारत के पास 75,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा भंडार मौजूद है एवं भारत में आर्थिक गतिविधियों में रफ्तार के चलते प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों में वसूली प्रभावी बनी हुई है। परंतु, युद्ध यदि और अधिक लंबे समय तक चलता है तो भारत में भी आर्थिक क्षेत्र में कुछ परेशनियां आ सकती हैं। बहुत सम्भव है कि भारतीय रिजर्व बैंक अपनी अक्टोबर 2026 माह में होने वाली बैठक में रेपो दर में 25 आधार बिंदुओं की वृद्धि करने को मजबूर हो। ब्याज दरों में वृद्धि का सीधा प्रभाव भारत के आर्थिक विकास की गति पर पड़े बिना नहीं रह सकेगा। भारत द्वारा आयात की जाने वाली विभिन्न वस्तुओं की कीमतें यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ रही हैं तो भारत को इन वस्तुओं को उच्च कीमतों पर खरीदने को मजबूर होना पड़ेगा। भारतीय शेयर बाजार भी विपरीत रूप से प्रभावित हो सकता है क्योंकि विदेशी संस्थागत निवेशक भी भारतीय पूंजी बाजार से अपने निवेश को निकाल कर अमेरिकी बांड में अपना निवेश बढ़ा रहे है। इससे भारतीय रुपए पर अतिरिक्त दबाव उत्पन्न होगा और अंतरराष्ट्रीय बाजार में रुपए की कीमत और अधिक कम हो सकती है।

विभिन्न देशों के बीच चल रहे युद्ध के बीच, भारतीय नागरिकों को भी अपने कर्तव्य का निर्वहन करने हेतु आगे आना होगा। इस संदर्भ में केंद्र एवं समस्त राज्य सरकारें तो अपना कार्य पूरी ईमानदारी से सम्पन्न करने का प्रयास कर ही रही हैं, परंतु नागरिकों को भी स्वदेशी अपनाकर एवं विभिन्न उत्पादों का संयम के साथ उपयोग कर अन्य देशों से उत्पादों के आयात को कम करने के प्रयास करने होंगे। भारत में उत्पादित वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देना होगा एवं आयातित वस्तुओं के उपयोग को कम करना होगा ताकि विदेशी मुद्रा को बचाया जा सके। भारतीय नागरिकों द्वारा यदि भारत में उत्पादित वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है तो भारतीय विनिर्माण इकाईयों को विस्तार में जाना होगा एवं इससे भारत में ही रोजगार के नए अवसर निर्मित होंगे। कुल मिलाकर अब अन्य देशों से आयातित वस्तुओं के उपयोग को समाप्त करना होगा, यदि समाप्त नहीं कर सकते हैं तो कम तो करना ही होगा।

हरित ऊर्जा की नई राह पर भारत

विनोद सिंह 'तकियावाला'

ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण-III से 135 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा के संचरण को मिलेगी गति, 50 जी डब्लु एच बैटरी भंडारण से मजबूत होगा देश का बिजली ग्रिड...

भारत की ऊर्जा यात्रा अब केवल बिजली उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं रह गई है,बल्कि देश ऐसी ऊर्जा व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है जिसमें स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन, उसका भंडारण और देश के विभिन्न हिस्सों तक निर्बाध संचरण एक साथ मजबूत हो। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण-III योजना को मंजूरी इसी व्यापक बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम को मजबूत करने के साथ 135 गीगावॉट तक नवीकरणीय ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने की क्षमता विकसित करेगी।भारत में सौर और पवन ऊर्जा की संभावनाएँ लगातार बढ़ रही हैं।देश के अनेक राज्यों में बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएँ स्थापित हो रही हैं, लेकिन इस ऊर्जा का वास्तविक लाभ तभी संभव है जब इसे मजबूत ट्रांसमिशन नेटवर्क के माध्यम से उन क्षेत्रों तक पहुँचाया जा सके जहाँ इसकी आवश्यकता है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण-III इसी चुनौती का समाधान प्रस्तुत करता है। राज्यों के भीतर ट्रांसमिशन व्यवस्था को सुदृढ़ करने से नवीकरणीय ऊर्जा के ग्रिड एकीकरण और पावर इवैक्यूएशन को गति मिलेगी तथा स्वच्छ ऊर्जा को बिजली की मुख्यधारा में अधिक प्रभावी ढंग से शामिल किया जा सकेगा।

इस योजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में 50 गीगावॉट-घंटे की बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम क्षमता का प्रावधान है। नवीकरणीय ऊर्जा की सबसे बड़ी चुनौती उसकी प्रकृति से जुड़ी है। सूर्य की रोशनी हर समय उपलब्ध नहीं होती और हवा की गति भी समान नहीं रहती। ऐसे में सौर और पवन ऊर्जा के उत्पादन में उतार-चढ़ाव स्वाभाविक है। बैटरी आधारित ऊर्जा भंडारण इस चुनौती का महत्वपूर्ण समाधान बन सकता है।जब नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन अधिक होगा, तब अतिरिक्त बिजली को संग्रहित किया जा सकेगा और आवश्यकता के समय उसका उपयोग किया जा सकेगा। इससे ग्रिड में लचीलापन आएगा और बिजली की आपूर्ति को अधिक स्थिर बनाने में मदद मिलेगी।

बीईएसएस की 50 जी डब्लू एच क्षमता केवल ऊर्जा भंडारण का आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह भारत की बदलती ऊर्जा व्यवस्था में एक नए युग की शुरूआत का संकेत भी है। पीक आवर में बिजली की बढ़ती मांग, ग्रिड में संभावित कंजेशन और नवीकरणीय ऊर्जा की अनियमित उपलब्धता जैसी चुनौतियों से निपटने में यह व्यवस्था उपयोगी होगी। विशेष रूप से उस समय जब सौर ऊर्जा उपलब्ध नहीं होती, संग्रहीत ऊर्जा मांग को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण-III को वित्तीय वर्ष 2032-33 तक स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसकी कुल परियोजना लागत 1,86,405 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। इसमें 1,36,378 करोड़ रुपये इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के विकास के लिए और लगभग 50,000 करोड़ रुपये 50 GWh बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए निर्धारित हैं। योजना के अंतर्गत कुल 54,082 करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता का प्रावधान है। यह सहायता इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन शुल्क को कम करने में मदद करेगी, जिसका सीधा संबंध बिजली की लागत से है। इसका अंतिम लाभ बिजली उपभोक्ताओं तक पहुँचने की संभावना है।इस योजना की कार्यान्वयन व्यवस्था भी महत्वपूर्ण है। इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के अंतर्गत आने वाली ग्रीनफील्ड परियोजनाओं को टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से लागू किया जाएगा। वहीं ब्राउनफील्ड अपग्रेडेशन और नेटवर्क को मजबूत करने से जुड़े कार्य कॉस्ट प्लस बेसिस पर किए जाएंगे।राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटीज समग्र कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में भूमिका निभाएँगी,जबकि ट्रांसमिशन सर्विस प्रोवाइडर्स बिल्ड-ओन- ऑपरेट-मेनटेन मॉडल के तहत प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया में भाग लेंगे। इससे परियोजनाओं के निर्माण के साथ उनके दीर्घकालिक संचालन और रखरखाव की व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण-III का महत्व केवल बिजली क्षेत्र तक सीमित नहीं है। इसके प्रभाव ऊर्जा, विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र तक पहुँचेंगे। बड़े पैमाने पर ट्रांसमिशन नेटवर्क के निर्माण से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के निर्माण और उपयोग से घरेलू ऊर्जा भंडारण उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा।इसके साथ ही संचालन, रखरखाव और आधुनिक ग्रिड प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में दीर्घकालिक कुशल रोजगार की संभावनाएँ बढ़ेंगी।यह योजना भारत के दीर्घकालिक ऊर्जा लक्ष्यों से भी जुड़ी हुई है। 2035 तक 900 गीगावॉट स्थापित गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने के लिए केवल उत्पादन क्षमता बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा। उसके साथ मजबूत ट्रांसमिशन नेटवर्क और पर्याप्त ऊर्जा भंडारण क्षमता भी आवश्यक होगी। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण-क्क्क इन दोनों आवश्यकताओं को एक साथ संबोधित करता है। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है।भारत आज एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहा है जहाँ ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय सुरक्षा को अलग- अलग नहीं देखा जा सकता। बढ़ती अर्थव्यवस्था, तेजी से बढ़ता औद्योगिक उत्पादन, शहरीकरण और डिजिटल अर्थव्यवस्था बिजली की मांग को लगातार बढ़ा रहे हैं। ऐसे में देश को ऐसी ऊर्जा व्यवस्था चाहिए जो पर्याप्त होने के साथ स्वच्छ, विश्वसनीय और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप हो। नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार के साथ मजबूत ट्रांसमिशन और ऊर्जा भंडारण इसी दिशा में आधारभूत आवश्यकता बन चुके हैं। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण-III इसी बदलती आवश्यकता के अनुरूप भारत के ऊर्जा ढाँचे को नई दिशा देता दिखाई देता है। 135 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा के संचरण की क्षमता, 50 जी डब्लु एच ऊर्जा भंडारण और 1,86,405 करोड़ रुपये का कुल निवेश देश की ऊर्जा संरचना के व्यापक विस्तार का संकेत है। इसका उद्देश्य केवल आज की बिजली जरूरतों को पूरा करना नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों के लिए ऐसी व्यवस्था तैयार करना है जिसमें स्वच्छ ऊर्जा देश की आर्थिक प्रगति का मजबूत आधार बने।ऊर्जा आत्मनिर्भरता, हरित विकास और दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में भारत की यात्रा अब उत्पादन से आगे बढ़कर संचरण और भंडारण के चरण में पहुँच रही है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण-क्क्क इसी परिवर्तन की महत्वपूर्ण कड़ी है। आने वाले समय में जब देश की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा मांग दोनों तेजी से विस्तार करेंगी, तब मजबूत ग्रिड, पर्याप्त भंडारण और व्यापक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता भारत के विकास की नई ऊर्जा रीढ़ बन सकती है। यही वह आधार है, जिस पर स्वच्छ ऊर्जा से समर्थ, आत्मनिर्भर और पर्यावरण-संतुलित भारत की तस्वीर आकार ले रही है।

संघ लोक सेवा आयोग : योग्यता-आधारित चयन और समावेशिता की एक सदी

बिहान भारत

1 अक्टूबर 2026 को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के सौ साल पूरे हो रहे हैं। इसकी संस्थागत यात्रा 1 अक्टूबर 1926 को शुरू हुई थी, जब भारत का पहला लोक सेवा आयोग बनाया गया था - यह एक सलाहकार संस्था थी जिसके चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति लंदन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट करते थे। इसके बाद की सदी में, आयोग के ढांचे, दर्जे और ज़िम्मेदारियों में बदलाव आए और यह आज एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था बन गया है।

1926 तक का सफर

सरकारी नौकरी में भर्ती 'सिफारिश' के बजाय 'योग्यता' के आधार पर होनी चाहिए - यह सिद्धांत 1855 में औपचारिक रूप से लागू हुआ। तब लंदन में इंडियन सिविल सर्विस (आईसीए) परीक्षा शुरू की गई, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की 'नॉमिनेशन' (नामांकन) वाली व्यवस्था की जगह खुली प्रतियोगिता को अपनाया। हालांकि, ज्यादातर भारतीयों के लिए इसमें शामिल होना लगभग नामुमकिन था। परीक्षा सिर्फ लंदन में और अंग्रेजी भाषा में होती थी। इसमें ग्रीक और लैटिन जैसे विषयों की परीक्षा ली जाती थी - इसलिए नहीं कि बंगाल या पंजाब के किसी जिले का प्रशासन चलाने के लिए इनकी जरूरत थी, बल्कि इसलिए क्योंकि इनसे ब्रिटिश शिक्षा-प्रणाली में पढ़े-लिखे लोगों को फायदा मिलता था।

1862 में, रवींद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई, 21 साल के सत्येंद्रनाथ टैगोर उस परीक्षा में बैठने उद्देश्य से कलकत्ता से इंग्लैंड गए, जिसे उनके अपने देश में देने की इजाजत नहीं थी। उन्होंने 1863 में परीक्षा पास की और 1864 में नौकरी शुरू की - वे ऐसे पहले भारतीय बने जो उस सेवा में शामिल हुए जिसे अंग्रेज ३हेवन-बॉर्न सर्विस३ (स्वर्ग से आई सेवा) कहते थे। उन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी में तीस से ज्यादा सालों तक सेवा की। उनकी सफलता के छह साल बाद, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बिहारी लाल गुप्ता और रमेश चंद्र दत्त ने भी यही राह अपनाई। हालांकि, परीक्षा के लिए अधिकतम उम्र सीमा धीरे-धीरे 23 से घटाकर 19 साल कर दी गई, जिससे भारतीय उम्मीदवारों को तैयारी के लिए बहुत कम समय मिलता था। 1919 तक, 1,255 आईसीएस अधिकारियों में से सिर्फ 78 भारतीय थे।

लगातार राष्ट्रवादी मांगों के कारण धीरे-धीरे बदलाव आए। मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के बाद बने 'गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1919' में एक लोक सेवा आयोग बनाने का प्रावधान किया गया। 1922 में, लंदन के साथ-साथ भारत में भी पहली बार इलाहाबाद में आईसीएस परीक्षा आयोजित की गई। 1928 में भारतीय केंद्र दिल्ली स्थानांतरित हो गया। 1924 में, आर्थर हैमिल्टन ली की अध्यक्षता वाले ली आयोग ने तुरंत एक वैधानिक लोक सेवा आयोग स्थापित करने की सिफारिश की। इसने यह भी प्रस्ताव दिया कि हर 10 नए लोगों में से चार ब्रिटिश हों, चार भारतीय हों और दो भारतीय प्रांतीय सेवाओं से प्रोन्नत होकर आएं - कागज पर तो यह बराबरी का रास्ता था, लेकिन असल में हर भर्ती में 40 प्रतिशत सीटें ब्रिटिश लोगों के लिए पक्की थीं, जो प्रतियोगिता के बजाय जन्म के आधार पर मिलती थीं।

यह आयोग 1919 के एक्ट की धारा 96बी और 96सी के तहत बनाए गए लोक सेवा आयोग (कार्य) नियम, 1926' के अंतर्गत स्थापित किया गया था। यूनाइटेड किंगडम की होम सिविल सर्विस के सदस्य सर रॉस बार्कर इसके पहले चेयरमैन थे, जिनकी सहायता के लिए चार सदस्य थे, और आयोग का कार्यालय दिल्ली के मेटकाफ हाउस में स्थित था। इसकी सीमित शक्तियों के कारण स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने इसकी लगातार आलोचना की। फिर भी, अब भारत में भर्ती करने वाली एक स्थायी संस्था मौजूद थी, जिसका कार्यालय और कर्मचारी भारत में ही थे - इसीलिए आयोग अपने इतिहास की शुरूआत 1926 से मानता है।

सवैधानिक प्रावधान

22 अगस्त 1949 को, संविधान सभा में प्रारूप समिति (ड्राफ्टिंग कमेटी) के चेयरमैन डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों से जुड़े ड्राफ्ट आर्टिकल (मसौदा अनुच्छेद) पेश किए। ये संविधान का भाग क्ष (अनुच्छेद 315-323) बने। 26 नवंबर 1949 को अपने विदाई भाषण में, डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इस बात पर जोर दिया कि सरकारी नियुक्तियों में निष्पक्षता बनाए रखने और नौकरी में धांधली, भाई-भतीजावाद और पक्षपात को रोकने के लिए लोक सेवा आयोगों की आजादी जरूरी है।

अनुच्छेद : यह क्या प्रदान करता है

315 : संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, जिसमें दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त आयोग का प्रावधान है

316 : अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है

317 : सदस्य को हटाने या निलंबित करने का काम केवल राष्ट्रपति के आदेश से, उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद ही किया जा सकता है

318 : सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों पर नियम बनाने की शक्ति

319 : सदस्य का कार्यकाल खत्म होने के बाद पद संभालने पर रोक; अध्यक्ष भारत सरकार या किसी राज्य के तहत आगे किसी नौकरी के लिए अयोग्य होता है

320 : कामः संघ की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाएं आयोजित करना, और भर्ती, पदोन्नति और अनुशासनात्मक मामलों के तरीकों पर सलाह देना

321 : आयोग के कामों का दायरा बढ़ाने के लिए संसद या राज्य विधानमंडल की शक्ति

322 : आयोग का खर्च भारत की संचित निधि से किया जाता है

323 : राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट; जिन मामलों में आयोग की सलाह नहीं मानी गई, उन्हें कारणों सहित संसद के सामने रखा जाता है

आयोग के काम

परीक्षा के जरिए भर्तीः सिविल सेवा, भारतीय वन सेवा, इंजीनियरिंग सेवा, संयुक्त चिकित्सा सेवा, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी, संयुक्त रक्षा सेवा और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) जैसी परीक्षाएं।

चयन के जरिए भर्तीः मंत्रालयों और विभागों द्वारा प्रस्तावित विशेष पदों के लिए साक्षात्कार और भर्ती टेस्ट।

सरकार को सलाहः भर्ती नियमों, विभागीय पदोन्नति समितियों के जरिए पदोन्नति, अखिल भारतीय सेवाओं में शामिल करने और अनुशासनात्मक मामलों पर। 2023-24 में, इसने पदोन्नति के लिए 24,581 अधिकारियों के रिकॉर्ड पर कार्रवाई की और 532 अधिकारियों को अखिल भारतीय सेवाओं में शामिल किया गया।

पुलिस नेतृत्वः 2012-13 से, प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के 22 सितंबर 2006 के आदेश के अनुसार, आयोग राज्यों में पुलिस महानिदेशक/पुलिस बल के प्रमुख के तौर पर नियुक्ति के लिए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की सूची तैयार करता है।

अहम घटनाएं: 1926-2026

शुरूआत: 1926-1949

अहम पड़ाव :

1935 : भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत नियुक्ति की शक्ति गवर्नर-जनरल को सौंपी गई; इसमें एक संघीय पीएससी और प्रांतीय पीएससी का प्रावधान किया गया; और भर्ती, नियुक्ति, पदोन्नति, अनुशासनात्मक मामलों और सेवा नियमों के संबंध में आयोग से परामर्श करना अनिवार्य कर दिया गया।

1937 : इसका नाम बदलकर संघीय लोक सेवा आयोग (1 अप्रैल) कर दिया गया।

1938 : कई सेवाओं के लिए संयुक्त प्रतियोगी परीक्षाएं शुरू हुईं - यानी एकीकृत, बहु-सेवा भर्ती की शुरूआत।

1940 : आईसीएस में पहली बार यूरोपियनों (575) की तुलना में

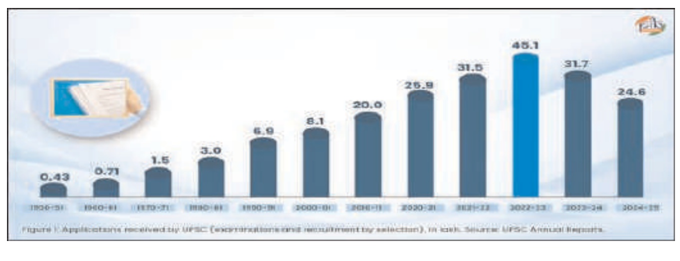

भारतीयों (625) की संख्या अधिक हो गई।

1947 : श्री एच.के. कृपलानी पहले भारतीय अध्यक्ष बने।

आजादी के बाद पहली परीक्षा दिसंबर में आयोजित हुई; आईसीएस की जगह आईएएस ने ले ली।

1948 : संयुक्त परीक्षा के माध्यम से भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों का पहला बैच भर्ती किया गया।

गणराज्य की सेवाओं का विकास: 1950-1979

अहम पड़ाव

1950 : 26 जनवरी को फेडरल पीएससी, संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) बन गया और श्री आर.एन. बनर्जी इसके चेयरमैन बने।

1950- 51 : संविधान के तहत अखिल भारतीय सेवाओं के लिए पहली नियमित भर्तीः आईएएस के लिए 29 और क्ढर के लिए 31 उम्मीदवारों की सिफारिश की गई।

1951 : अखिल भारतीय सेवा अधिनियम लागू किया गया।

1966 : भारतीय वन सेवा को तीसरी अखिल भारतीय सेवा के तौर पर बनाया गया; पहला चयन 1967 में हुआ।

1969 : सिविल सर्विसेज परीक्षा के निबंध और जनरल स्टडीज पेपर के लिए आठवीं अनुसूची की भाषाओं को विकल्प के तौर पर शामिल किया गया।

1976 : स्वर्ण जयंती। पहली बार आवेदनों की संख्या एक लाख के पार पहुंची।

डी.एस. कोठारी कमेटी ने तीन चरणों वाली परीक्षा का प्रस्ताव रखा।

1977 : पहली संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा।

1978 : आयोग ने आवेदनों, उत्तर पुस्तिका और रिकॉर्ड्स को प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल शुरू किया।

1979 : तीन चरणों वाली सिविल सेवा परीक्षा - प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार- शुरू की गई।

मुख्य परीक्षा में आठवीं अनुसूची की भाषाओं को आधिकारिक तौर पर शामिल किया गया; लंदन केंद्र बंद कर दिया गया।

सुधार और आधुनिकीकरण: 1985-2010

अहम पड़ाव

1985 : स्वीकृत संख्या बढ़ाकर एक चेयरमैन और 10 सदस्य कर दी गई।

1988-89 : सतीश चंद्र समिति ने और केंद्र बनाने, 200 नंबर का निबंध, प्रारंभिक परीक्षा में नकारात्मक मार्किंग और साक्षात्कार के लिए ज्यादा नंबर देने की सिफारिश की।

1989 : ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन (ओएमआर) तकनीक शुरू की गई।

1992 : श्रीमती रोज मिलियन बाथेव खारबुली पहली महिला चेयरमैन बनीं।

1993 : सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा में निबंध का पेपर शुरू किया गया; इंटरव्यू के नंबर 250 से बढ़ाकर 300 कर दिए गए।

1994 : मेडिकल साइंस को एक वैकल्पिक विषय के तौर पर जोड़ा गया।

2000 : एसएएमपीईआरए (रअट-ढएफ्अ) कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म (1999-2000) के बाद ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन (ओआरए) व्यवस्था शुरू की गई; 2010 तक, कई परीक्षाओं के लिए आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन हो गए।

2003 : पहली केंद्रीय पुलिस बल (असिस्टेंट कमांडेंट) परीक्षा आयोजित की गई (12 अक्टूबर)।

2005 : नए कार्यालय भवन, ह्यआयोग सचिवालयह्न का उद्घाटन किया गया (22 दिसंबर)।

2009 : राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल ने ह्यशासन और लोक सेवाह्न पर स्थापना दिवस व्याख्यान श्रृंखला का उद्घाटन किया (12 नवंबर); भारतीय कॉर्पोरेट विधि सेवा को सिविल सेवा परीक्षा में जोड़ा गया।

2010 : यूपीएससी ने सार्क (रअअफ्छ) देशों के लोक सेवा आयोग के प्रमुखों के सम्मेलन की मेजबानी की (20-22 नवंबर)।

डिजिटल, पारदर्शी और समावेशी: 2011-2026

अहम पड़ाव

2011 : सिविल सेवा अभिरुचि परीक्षा (सीसैट) शुरू किया गया; सिंगल विंडो सिस्टम (1 सितंबर)।

2013 : सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा का नया ढांचाः सामान्य अध्ययन (जिनमें नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा, और अभिरुचि शामिल हैं) के चार पेपर और एक वैकल्पिक विषय। पहली बार कंप्यूटर-आधारित भर्ती परीक्षाएं। सीएस (प्रारंभिक) परीक्षा के जरिए आईएफओएस की स्क्रीनिंग।

2015 : सीसैट को क्वालिफाइंग पेपर (33 प्रतिशत) बनाया गया।

2017 : इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा तीन चरणों वाली बनी; सवालों पर आपत्तियों के लिए सात दिन की ऑनलाइन विंडो।

2018 : सवाल-आधारित मार्क्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम (1 जून)।

2019 : परीक्षाओं की साल भर निगरानी के लिए खास नियंत्रण कक्ष।

2021 : एनडीए और एनए परीक्षा में पहली बार महिलाओं को शामिल किया गया - एनडीए और एनए परीक्षा (क्क), 2021, 14 नवंबर 2021 को आयोजित हुई।

2022 : सिविल सेवा परीक्षा के तहत मौजूद रेलवे की चार ग्रुप ए सेवाओं को मिलाकर 'भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा' बनाई गई।

2025 और 2026 में हुई गतिविधियां सेक्शन 7 में दी गई हैं।

तथ्य और आंकड़े

आयोग का दायरा

पिछले कुछ वर्षों में यूपीएससी के काम का दायरा और जटिलता काफी बढ़ गई है। परीक्षाओं और चयन के जरिए भर्ती के लिए आवेदन 1950-51 में 42,727 से बढ़कर 2022-23 में 45,10,044 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए - यानी सौ गुना से भी ज्यादा की बढ़ोतरी। उस साल, आयोग ने 15 परीक्षाएं आयोजित कीं (33,51,916 आवेदन) और चयन के जरिए भर्ती के तहत 4,411 पदों के लिए 233 अनुरोध प्राप्त किए (11,58,128 आवेदन)।

आंकड़ों में भागीदारी

महिलाएंः 1949 और 1951 के बीच, भारतीय विदेश सेवा के लिए सिर्फ एक महिला और आईएएस के लिए दो महिलाओं को चुना गया था। 1952 में चुने गए लोगों में महिलाओं की हिस्सेदारी 3.6 प्रतिशत थी और सीएसई 2025 में यह 31.2 प्रतिशत रही, जिसमें उन्होंने टॉप 25 रैंक में से 11 रैंक हासिल कीं।

साक्षात्कार में भारतीय भाषाएंः 1970-71 में, आयोग ने सरकार को बताया कि व्यक्तित्व परीक्षण (पर्सनैलिटी टेस्ट) सिर्फ अंग्रेजी में ही हो सकता है। 1980-81 में स्थिति बदली और अब उम्मीदवार आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए दुभाषिये (इंटरप्रेटर) की मदद से किसी भारतीय भाषा में जवाब दे सकते हैं; 2010-11 में 803 और 2023-24 में 307 उम्मीदवारों ने ऐसा किया।

किस्से-कहानियां

आयोग के सौ सालों के सफर से जुड़ी छोटी-छोटी कहानियां।

जहां 'स्टील फ्रेम' वाला भाषण दिया गया था

सर थॉमस मेटकाफ द्वारा 1835 में बनवाया गया मेटकाफ हाउस इतिहास में एक और वजह से भी अहम है। 21 अप्रैल 1947 को सरदार वल्लभभाई पटेल ने वहां सिविल सर्विस प्रोबेशनर्स के पहले बैच को संबोधित किया था और सिविल सेवा को ३भारत का स्टील फ्रेम३ कहा था। अब हर साल इस तारीख को 'सिविल सेवा दिवस' के तौर पर मनाया जाता है।

महाराजा का ट्रांजिट हाउस

शाहजहां रोड पर स्थित धौलपुर भवन को 1920 में धौलपुर के महाराजा राणा उदयभानु सिंह ने आर्ट डेको शैली में बनवाया था, ताकि दिल्ली आने-जाने के दौरान वे यहां रह सकें। 7 अप्रैल 1949 को धौलपुर रियासत के भारतीय संघ में विलय के बाद, यह इमारत सरकारी संपत्ति बन गई। तीन साल बाद, 1952 में, यह आयोग का स्थायी मुख्यालय बन गया।

अस्सी में से एक

1972 में, किरण बेदी भारतीय पुलिस सेवा के लिए आयोग द्वारा चुनी जाने वाली पहली महिला बनीं; यह एक ऐसी सेवा थी जिसमें पहले कभी कोई महिला अधिकारी नहीं थी। उस साल अस्सी वैकेंसी थीं, जिनमें वह अकेली महिला थीं।

अखबार में फॉर्म

1989 में, जब धीमी डाक सेवा के कारण दूर-दराज के इलाकों तक आवेदन पत्र पहुंचाना मुश्किल हो गया, तो आयोग ने उन्हें सीधे अखबारों में छपवाया। 1984 में, जब भारी बर्फबारी की वजह से कांगड़ा का संपर्क कट गया, तो आयोग ने प्रभावित उम्मीदवारों के लिए आवेदन की समय-सीमा दो हफ़्ते बढ़ा दी।

डाक टिकट पर सूरज

8 नवंबर 1977 को, डाक और तार विभाग ने आयोग की स्वर्ण जयंती के लिए 25 पैसे का डाक टिकट जारी किया। इस पर सूरज बना था - जो निष्पक्षता और सभी के लिए समान अवसर का प्रतीक था - और साथ में राष्ट्रीय तिरंगा भी था। 14 दिसंबर 2001 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई प्लेटिनम जयंती के लिए, डाक विभाग ने एक 'फर्स्ट डे कवर' जारी किया।

क्या आप जानते हैं?

11 नवंबर 2016 को खुला यूपीएससी म्यूजियम आम लोगों के लिए मुफ्त है और हफ्ते के दिनों में सुबह 9:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुला रहता है; आयोग की वेबसाइट पर इसका 360-डिग्री वर्चुअल टूर भी उपलब्ध है।

उम्र सीमा में काफी बदलाव हुए हैं। 1988 में, एक विशेषज्ञ समिति ने सिविल सेवा परीक्षा के लिए उम्र सीमा 21 से 26 साल रखने की सलाह दी थी। सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 32 साल, ओबीसी के लिए 35 साल और एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए 37 साल की उम्र सीमा 2014 में तय की गई थी; साथ ही, दिव्यांग लोगों के लिए इसमें दस साल तक की छूट दी गई और दो अतिरिक्त प्रयास भी दिए गए।

जिन उम्मीदवारों ने सिविल सेवा परीक्षा 2011 में हिस्सा लिया था, उन्हें सीएसई 2015 में एक और प्रयास करने का मौका दिया गया, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो या उन्होंने पहले कितने भी प्रयास क्यों न किए हों।

आयोग ने हमेशा सिर्फ.केंद्र सरकार के लिए ही भर्तियां नहीं की हैं। 1960-61 में, अनुच्छेद 320 के तहत, इसने दिल्ली नगर निगम, कर्मचारी राज्य बीमा निगम और केंद्र शासित प्रदेशों की क्षेत्रीय परिषदों जैसी संस्थाओं के लिए भी भर्तियां करने पर सहमति जताई थी।

दूसरे विश्व युद्ध के दौरान खुली प्रतियोगिता बंद हो गई थी। लंदन में परीक्षा आखिरी बार 1939 में हुई थी; 1940, 1941 और 1942 के लिए अधिकारियों को सीधे मनोनीत किया गया था, और 1943 के बाद ब्रिटिश सिविल सेवा आयोग के जरिए भर्ती पूरी तरह बंद हो गई थी।

संविधान के मसौदे में, जब डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने संविधान सभा में लोक सेवा आयोग से जुड़े प्रावधान पेश किए थे, तो उन्हें अनुच्छेद 284 और 285 का नंबर दिया गया था।

केस स्टडीजः यह सिस्टम कैसे काम करता है

मुंबई में हर सुबह, लगभग 5,000 डब्बेवाले घर का बना खाना (लंच) इकट्ठा करते हैं और उसे लंच के समय तक सही डेस्क तक पहुंचाते हैं। इसके लिए वे सिर्फ डिब्बे के ढक्कन पर चॉक से बने कलर कोड का इस्तेमाल करते हैं। आयोग भी हर साल इसी तरह की एक समस्या को हल करता है, लेकिन इसमें दांव कहीं ज्यादा बड़ा होता हैः सही प्रश्न-पत्र सही समय पर सही उम्मीदवार तक पहुंचना चाहिए, और फिर हर जवाब को सिर्फ.उसकी मेरिट के आधार पर जांचा जाना चाहिए। नीचे दी गई केस स्टडीज बताती हैं कि यह कैसे होता है।

केस स्टडी 1: सही उम्मीदवार तक सही पेपर पहुंचाना

उम्मीदवार सिर्फ.एक चुनाव करता हैः शहर का। उस शहर के अंदर, सिस्टम परीक्षा केंद्र और कमरे का आवंटन करता है, ताकि परीक्षा के दिन तक हर उम्मीदवार का एक खास पता - शहर, केंद्र, कमरा, उम्मीदवार - तय हो जाए, जिसकी जानकारी पहले सिर्फ. सिस्टम को होती है। एक ही कमरे में बैठे उम्मीदवार अलग-अलग पेपर लिख रहे हो सकते हैं - अकेले सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में, उम्मीदवार 48 वैकल्पिक विषयों में से चुनाव करते हैं - इसलिए हर सीलबंद पैकेट में ठीक वही पेपर होने चाहिए जिनकी उस केंद्र पर जरूरत है, और उन्हें कमरे के हिसाब से अलग-अलग किया गया हो।

केस स्टडी 2: ऐसा पेपर तैयार करना जिसे किसी ने न देखा हो

प्रश्न पत्र उन प्रश्न-बैंकों से बनाए जाते हैं जिन्हें शैक्षणिक विशेषज्ञ तैयार करते हैं। ये विशेषज्ञ पूरी गोपनीयता के साथ और बिना अपनी पहचान उजागर किए काम करते हैं। कोई एक एक्सपर्ट पूरा पेपर नहीं बनाता, और न ही किसी विशेषज्ञ को यह पता होता है कि कौन से सवाल इस्तेमाल किए जाएंगे या कब। पेपर बनाते समय, आयोग यह पक्का करता है कि इसमें पूरा सिलेबस कवर हो, कठिनाई का स्तर संतुलित हो और कोई भी सवाल पहले की किसी यूपीएससी परीक्षा में न पूछा गया हो।

यह पूरी व्यवस्था 'जरूरत के हिसाब से जानकारी' के सिद्धांत पर टिकी हैः किसी भी एक व्यक्ति को - यहां तक कि चेयरमैन को भी - पूरी जानकारी नहीं होती।

केस स्टडी 3: परीक्षा भवन को सुरक्षित बनाना

नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन के साथ मिलकर, आयोग ने 14 सितंबर 2025 को एनडीए & एनए (क्क) और सीडीएस (क्क) परीक्षाओं के दौरान गुरुग्राम के कुछ चुने हुए केंद्रों पर एआई-आधारित फेशियल ऑथेंटिकेशन (उम्मीदवार की लाइव तस्वीर का एप्लीकेशन वाली तस्वीर से मिलान) का पायलट प्रोजेक्ट चलाया। इसे 24 मई 2026 को सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा में बड़े पैमाने पर लागू किया गया, जहां लगभग 5.50 लाख उम्मीदवारों का फेस ऑथेंटिकेशन इनविजिलेटर के मोबाइल फोन के जरिए किया गया; इसमें हर उम्मीदवार पर लगभग 6-8 सेकंड का समय लगा।

सीएस (प्रारंभिक) परीक्षा 2026 से पहले, उम्मीदवारों के पिछले पंद्रह वर्षों के डेटा की जांच की गई और ऐसे 569 आवेदकों की पहचान करके उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया, जिन्होंने अतिरिक्त प्रयास पाने के लिए गलत जानकारी दी थी।

केस स्टडी 4: जरूरत के हिसाब से तेजी से भर्ती

जब भी देश को जरूरत पड़ी, आयोग ने अपने मानदंडों से समझौता किए बिना बार-बार भर्ती बढ़ाई। जुलाई 1948 में, एक स्पेशल रिक्रूटमेंट बोर्ड ने रिकॉर्ड और साक्षात्कार के आधार पर 27 से 45 साल की उम्र के अनुभवी लोगों को आईएएस और आईपीएस में भर्ती किया। 1956-57 में, एक विशेष अभियान के जरिए 22,000 से ज्यादा उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग की गई। 1958 में, एक स्पेशल रिक्रूटमेंट बोर्ड ने एक राष्ट्रीय पूल के लिए 197 वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविद चुने - जिनमें विदेश से आए उम्मीदवार भी शामिल थे - और 1962 तक इस पूल में लोगों की संख्या बढ़कर 500 हो गई। 1962 की इमरजेंसी के दौरान, एक आपात आयोग ने दो महीनों में रक्षा से जुड़े 1,353 पद भरे।

कोविड-19 के दौरान, जब ट्रेन सेवा बंद थीं, तो आयोग ने एक बार के उपाय के तौर पर साक्षात्कार देने वाले उम्मीदवारों का हवाई किराया वापस किया, राज्यों से कहा कि वे ई-समन लेटर वाले उम्मीदवारों को प्रतिबंधित क्षेत्र से गुजरने दें, रहने और परिवहन में मदद की, और हर उम्मीदवार को मास्क, फेस शील्ड, सैनिटाइजर और ग्लव्स की एक सीलबंद किट दी।

केस स्टडी 5: डिजाइन के जरिये समावेश

सबसे पहले पहुंच की बात आती है। आयोग ने 1994 में दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए स्क्राइब (लिखने में मदद करने वाले) की सुविधा शुरू की थी। आज, बेंचमार्क विकलांगता वाले लोगों के लिए स्क्राइब और अतिरिक्त समय का अधिकार एक हक है; उन्हें अपनी पसंद का केंद्र मिलता है, वे साथ में एक सहायक ला सकते हैं और साक्षात्कार के दौरान एक फैसिलिटेटर उनकी मदद करता है। महिला उम्मीदवारों को शुल्क में छूट मिलती है। उम्र में छूट उन लोगों को भी दी गई है जिनकी तैयारी ऐसी घटनाओं के कारण बाधित हुई जो उनके नियंत्रण से बाहर थीं - जैसे गोवा मुक्ति संग्राम (1961-62) के स्वतंत्रता सेनानी, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध और युगांडा-जंजीबार संकट (1971-72) के कारण विस्थापित भारतीय, और खाड़ी युद्ध (1991) से प्रभावित भारतीय। इसके बाद निष्पक्षता आती हैः एक ऐसा मूल्यांकन सिस्टम - लिखित परीक्षा से लेकर साक्षात्कार बोर्ड तक - जो उम्मीदवार की पहचान से प्रभावित नहीं होता। आयोग ने आरक्षण की नीति नहीं बनाई, लेकिन उसने इसे लागू करने वाला राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म तैयार किया। इसमें सीएसई 2019 से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) की श्रेणी और 2020 से ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म में ट्रांसजेंडर के लिए एक अलग कैटेगरी को शामिल करना शामिल है।

केस स्टडी 6: मेरिट लिस्ट से परे मेरिटः प्रतिभा सेतु

जो उम्मीदवार परीक्षा के सभी चरण पास कर लेते हैं लेकिन फाइनल लिस्ट में जगह बनाने से बहुत कम अंतर से चूक जाते हैं, वे सार्वजनिक सेवा को नहीं गंवाते। 20 अगस्त 2018 से लागू और सबसे पहले संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2017 के लिए इस्तेमाल की गई 'पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम' के तहत, ऐसे इच्छुक उम्मीदवारों की जानकारी नियोक्ताओं को उपलब्ध कराई गई थी। 9 जून 2025 को नए रूप में और 'प्रतिभा सेतु' नाम से शुरू की गई यह स्कीम उन्हें सत्यापित नियोक्ताओं से जोड़ती है, जिनमें मंत्रालय, पीएसयू, स्वायत्त संस्थाओं और निजी संगठन शामिल हैं।

आज का आयोग

आयोग के प्रमुख चेयरमैन डॉ. अजय कुमार हैं (15 मई 2025 से)। इसके आठ सदस्य हैं - लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला (रिटायर्ड), सुश्री सुमन शर्मा, श्री विद्युत बिहारी स्वैन, डॉ. दिनेश दासा, श्री शील वर्धन सिंह, श्री संजय वर्मा, श्रीमती सुजाता चतुवेर्दी और श्रीमती अनुराधा प्रसाद। इन आठ सदस्यों में से तीन महिलाएं हैं - यह संरचना दिखाती है कि यह संस्था सौ सालों में कितनी आगे बढ़ चुकी है।

कोई संस्था जो सौ सालों से कायम है, वह इसलिए नहीं कि वह बदलाव का विरोध करती है, बल्कि इसलिए कि वह जानती है कि क्या कभी नहीं बदलना चाहिए।

डॉ. अजय कुमार, चेयरमैन, यूपीएससी

सौ सालों से, यह आयोग देश की सबसे अहम जिम्मेदारियों में से एक निभा रहा हैः काबिलियत को पहचानना, निष्पक्षता बनाए रखना और यह पक्का करना कि मौके सिर्फ.विशेषाधिकार, जगह, भाषा या हालात तक ही सीमित न रहें। एक सदी पहले, लड़ाई भारतीयों के मुकाबला करने के अधिकार के लिए थी। आज, काम यह पक्का करना है कि यह अधिकार असल में हर उस काबिल भारतीय तक पहुंचे जो देश की सेवा करना चाहता है।

कठुआ में सीआईएसएफ जवानों के बीच गोलीबारी, चार की मौत

-जवान ने कमांडेंट समेत 4 साथियों को 15-15 गोलियां मारीं

जम्मू (एजेंसी)। जम्मू और कश्मीर के कठुआ जिले के बसोहली क्षेत्र स्थित एनएचपीसी के माशका सेवा-2 जल विद्युत परियोजना में मंगलवार को सीआईएसएफ जवानों के बीच हुई गोलीबारी में चार जवानों की मौत हो गई। मृतकों में असिस्टेंट कमांडेंट अंकित कुमार पांडे, सब इंस्पेक्टर लक्ष्मण सिंह, कॉन्स्टेबल रफीक अहमद और संदीप कुमार शामिल हैं। घटना के तुरंत बाद सभी घायल जवानों को इलाज के लिए हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के खैरी स्थित एनएचपीसी के चमेरा पावर स्टेशन-1 के परियोजना अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गोलीबारी के आरोपी हेड कांस्टेबल अवधेश कुमार को हिरासत में ले लिया गया है। कठुआ की एसएसपी मोहिता शर्मा ने जानकारी दी कि पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मंगलवार शाम करीब 4 बजे हेड कॉन्स्टेबल अवधेश कुमार ने अपनी सर्विस राइफल से साथी कर्मियों पर 10 से 15 गोलियां चलाईं। सूत्रों से पता चला है कि आरोपी सहायक कमांडेंट और अन्य साथियों से ड्यूटी संबंधी विवादों को लेकर नाराज था। इससे पहले भी उसकी कई बार बहस हो चुकी थी। घटना के बाद परियोजना अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। चूंकि घटना जम्मू-कश्मीर में हुई है, हिमाचल प्रदेश पुलिस ने इस पर आधिकारिक टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। हालांकि, सूत्रों के मुताबिक, डलहौजी से डीएसपी समेत पुलिस की एक टीम अस्पताल भेजी गई थी। बताया जा रहा है कि चारों शवों का पोस्टमार्टम बसोहली में ही किया जाएगा। घटना की जानकारी मिलते ही सीआईएसएफ के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और आरोपी कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल मामले की विस्तृत जांच जारी है।

सीईसी के घर कालिख पोतने के मामले में छह कांग्रेस कार्यकर्ता गिरफ्तार

नई दिल्ली (एजेंसी)। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के दिल्ली स्थित आवास पर कालिख पोतने के मामले में छह कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं के खिलाफ हत्या के प्रयास और दंगा सहित भारतीय न्याय संहिता की कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। करीब 20 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था। सूत्रों ने बताया कि प्रदर्शनकारियों पर घर के गेट और दीवारों पर काले रंग से नारे लिखने का आरोप है। गिरफ्तार किए गए लोगों में कांग्रेस नेता अनिल यादव, मुकेश धांगर, मनोज गौड़, राजेश कुमार, राजा गौतम और पंकज चौधरी शामिल हैं। इन सभी को मंगलवार को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। उप निरीक्षक गौरव गुप्ता की शिकायत पर हरिपर्वत थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। कांग्रेस के शहर अध्यक्ष अमित सिंह ने इन गंभीर धाराओं को गलत और अनावश्यक बताया है। उन्होंने कहा कि मामला केवल विरोध प्रदर्शन से संबंधित धाराओं तक सीमित रहना चाहिए था।

प्रिंसिपल की घिनौनी करतूत: 15 साल की छात्रा से यौन उत्पीड़न, एफआईआर दर्ज

चिकबल्लापुर (एजेंसी)। कर्नाटक के चिकबल्लापुर जिले में सरकारी रेजिडेंशियल स्कूल से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। शिडलघट्टा तालुक के गोरलुम्मनहल्ली स्थित मोरारजी देसाई मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के प्रिंसिपल ईश्वर रेड्डी पर 9वीं कक्षा की 15 वर्षीय छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न करने का गंभीर आरोप लगा है। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर आगे की जांच शुरू की है। यह सनसनीखेज घटना 26 सितंबर को दोपहर करीब ढाई बजे स्कूल के मेडिसिन रूम में घटी। शिकायत के मुताबिक, पीड़िता छठी कक्षा की एक बीमार छात्रा को दवा देने गई थी। इसी दौरान प्रिंसिपल ने छात्रा को कमरे के अंदर बुलाया, उसके साथ आपत्तिजनक हरकत की और यौन उत्पीड़न किया। आरोपी प्रिंसिपल ने पीड़िता को धमकी दी थी कि यदि उसने इस बारे में किसी को बताया, तब परिणाम भुगतना होगा। डरी-सहमी छात्रा ने यह बात अपने सहपाठियों को बात दी। इसके बाद इसकी जानकारी शिक्षकों और परिजनों तक पहुंची। 27 सितंबर को माता-पिता स्कूल पहुंचे और पूरी जानकारी मिलने पर वे पुलिस की शरण में पहुंचे। इसके बाद 28 सितंबर को बाल कल्याण अधिकारियों की उपस्थिति में चिकबल्लापुर में पीड़िता का बयान दर्ज किया गया।

आसाराम को गुजरात हाईकोर्ट से झटका, पत्नी से मिलने के लिए 20 दिन की अंतरिम जमानत खारिज

अहमदाबाद (एजेंसी)। गुजरात हाईकोर्ट ने 2013 के दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 86 वर्षीय आसाराम की 20 दिन की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी। आसाराम ने अस्पताल में भर्ती 83 वर्षीय पत्नी से मिलने के लिए मानवीय आधार पर राहत मांगी थी। सुनवाई के दौरान पुलिस की रिपोर्ट और इलाज कर रहे डॉक्टरों के बयान में बताया गया कि उनकी पत्नी की हालत स्थिर है, उपचार का अच्छा असर हो रहा है और अगले दो-तीन दिनों में उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। राज्य सरकार ने इसी आधार पर जमानत का विरोध किया।

हार के बाद ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रहा इंडिया गठबंधन: रामचंद्र राव

केरल में कांग्रेस नेता ने एसआईआर की तारीफ की थी

हैदराबाद , एजेंसी।
तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष रामचंद्र राव ने विपक्षी इंडिया गठबंधन पर आरोप लगाया है कि वे चुनाव हारने पर ईवीएम, चुनाव आयोग और विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया पर दोष देते हैं। हैदराबाद में प्रेस वार्ता के दौरान, राव ने विपक्षी दलों पर देश की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाकर कहा कि इंडिया गठबंधन सिर्फ उन राज्यों में एसआईआर का मुद्दा उठा रहा है जहाँ भाजपा की जीत हुई है, जबकि उनके शासित राज्यों में वे इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राव ने याद दिलाया कि 2018 से ही इंडिया गठबंधन के कई प्रमुख नेता, जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी, जवाहर सरकार और सचिन पायलट जैसे नाम शामिल हैं, स्वयं भारत सरकार और चुनाव आयोग से एसआईआर कराने तथा फर्जी व मृत मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाने की मांग करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब वहीं कांग्रेस पार्टी अचानक इस मामले को मुद्दा बना रही है, जबकि वोटों को हटाने का काम बीएलओ की रिपोर्ट के आधार पर ही होता है। राव ने केरल का उदाहरण देकर कहा कि कांग्रेस नेता रमेश चेन्निथला ने खुद स्वीकार किया था कि वे एसआईआर की वजह से चुनाव जीते, नहीं बहुत सारे फर्जी वोट पड़ते। उन्होंने सवाल उठाया कि कांग्रेस केरल में एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल क्यों नहीं उठा रही, जहाँ उन्हें जीत मिली है? राव ने लोगों को गुमराह करने और संवैधानिक संस्थाओं पर से उनका भरोसा उठाने की कांग्रेस की कोशिश बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा संवैधानिक संस्थाओं के साथ खड़ी है और उनके सम्मान व भरोसे को कायम रखने के लिए इस नकारात्मक राजनीति का मुंहतोड़ जवाब देगी।

इस दौरान, राव ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के उस दावे को खारिज किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा के शासन में मुस्लिम नेतृत्व नहीं पनप रहा है। राव ने सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास के भाजपा के मंत्र पर कहा कि पार्टी विकास या राजनीति को किसी धार्मिक आधार पर नहीं देखती। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और ओवैसी देश को धार्मिक आधार पर बांटने का काम कर रहे हैं। राव ने ओवैसी को नेतृत्व के बजाय मुसलमानों के विकास की बात करने की सलाह दी, यह भी बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बनाया था और अल्पसंख्यकों के विकास के लिए भारी रकम आवंटित की जा रही है।

सौरभ भारद्वाज और जरनैल सिंह सहित आप कार्यकर्ताओं पर एफआईआर, पुलिसकर्मी से मारपीट का आरोप

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सौरभ भारद्वाज, विधायक जरनैल सिंह और पार्टी के कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ एक पुलिसकर्मी से कथित मारपीट और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस के अनुसार, मामला भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 221, 132 और 115(2) के तहत दर्ज हुआ है। पुलिस के मुताबिक, घटना पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर इलाके में हुई, जब आप नेता पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ वहां पहुंचे थे। आरोप है कि सादे कपड़ों में मौजूद एक पुलिसकर्मी इलाके में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। इसी दौरान कुछ आप समर्थकों ने पुलिसकर्मी को घेरकर उसके साथ कथित तौर पर मारपीट की। घटना के बाद पुलिसकर्मी को चिकित्सकीय जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। आप के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने आरोप लगाया कि पुलिस ने कथित झड़प के मामले में एफआईआर दर्ज कर रविवार को हुई थप्पड़ मारने की घटना से ध्यान भटकाने की कोशिश की है। पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने भी पार्टी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की आलोचना की और पुलिस पर कार्रवाई में भेदभाव का आरोप लगाया। दरअसल, तिलक नगर में निरीक्षण के दौरान एक 22 वर्षीय युवक को कथित तौर पर थप्पड़ मारने के मामले में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री प्रवेश वर्मा के खिलाफ भी पुलिस ने असंज्ञेय रिपोर्ट (एनसीआर) दर्ज की है।

विजय थलपति ने पश्चिम बंगाल में खोला पार्टी का दफ्तर

दूसरे भाजपा राज्यों में भी खुलेंगे टीवीके के ऑफिस

कोलकाता, एजेंसी।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की नवगठित पार्टी, तामिलागा वेत्री कझगम (टीवीके) की नजरें अब अपने गृह राज्य से बाहर दूसरे राज्यों पर भी टिकती दिख रही हैं। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल में टीवीके के नाम से एक दफ्तर खोला गया है, हालांकि पार्टी ने आधिकारिक तौर पर इस कदम से दूरी बना ली है, लेकिन इससे जुड़ी गतिविधियों पर उसने कोई स्पष्ट टिप्पणी नहीं की है। माना जा रहा है कि टीवीके अन्य भाजपा शासित राज्यों में भी कार्यालय खोलने पर विचार कर रही है। पश्चिम बंगाल के पूर्व वर्धमान जिले के फागूपुर में रविवार को यह दफ्तर खोला गया। इस दौरान चैताली रॉय को पश्चिम बंगाल में पार्टी का संयोजक बनाया गया। बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से कई कार्यकर्ता शामिल हुए थे। हालांकि, इन खबरों के बीच टीवीके ने खुद को इस फैसले से दूर बताया है, लेकिन बंगाली शुभचिंतकों को शुभकामनाएं भी दी हैं।

वेबसाइट से बातचीत में पार्टी के प्रवक्ता एस.डी. तुहिनसैमुअल ने कहा कि फिलहाल टीवीके का तमिलनाडु से बाहर विस्तार का कोई प्लान नहीं है। इसके बावजूद, पश्चिम बंगाल में टीवीके के स्थानीय नेताओं का दावा है कि उन्हें तमिलनाडु से राज्य में अपनी सक्रियता बढ़ाने के निर्देश मिले हैं। इन निर्देशों में सामाजिक गतिविधियों में शामिल होने पर जोर दिया गया है, जिसके चलते ही बंगाल में भी संगठन विस्तार के लिए सामाजिक कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। बंगाल के नेताओं ने आगामी दिनों में जिले के अलग-अलग हिस्सों में कार्यक्रम आयोजित करने की योजना की बात कही है। पश्चिम बंगाल में टीवीके की संयोजक चैताली रॉय ने अपनी रणनीति का खुलासा करते हुए कहा कि शुरुआत में सोशल मीडिया के जरिए प्रचार किया जाएगा। इसके बाद लोगों की समस्याओं और लाभ के मुद्दों को सुनने के लिए जनसंपर्क अभियान पर जोर दिया जाएगा। रॉय ने पार्टी के मुख्य लक्ष्यों के रूप में शिक्षा और रोजगार को बताया। उन्होंने यह भी इच्छा व्यक्त की कि टीवीके चुनावों में उतरे, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि अंतिम निर्णय बंगाल की जनता की इच्छा और शीर्ष नेतृत्व के फैसले पर निर्भर करेगा। रॉय के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय वर्तमान में उपचुनावों में व्यस्त हैं और अगर उन्हें सफलता मिलती है, तो वह निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। उन्होंने बंगाल में पार्टी के समर्थकों की संख्या 5 हजार से अधिक होने का दावा किया है।

केजरीवाल बोले- हमने देश की बेहतरी के लिए पार्टी बनाई

नई दिल्ली, एजेंसी।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में एक कार्यक्रम में कहा कि उनका मकसद पार्टी नहीं, बल्कि देश है। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत यात्रा, आम आदमी पार्टी के गठन के पीछे के कारणों, दिल्ली सरकार में भ्रष्टाचार विरोधी कदमों और हाल ही में मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों पर खुलकर बात की। केजरीवाल ने बताया कि उन्होंने इनकम टैक्स में संयुक्त आयुक्त का पद छोड़कर 10 साल तक झुग्गियों में काम किया, जो लोगों को कम ही पता है। उनके मुताबिक, अन्ना आंदोलन के बाद जब लोकपाल बिल नहीं बना, तो देश की बेहतरी के लिए उन्हें पार्टी बनानी पड़ी। उनका कहना था कि यदि उस समय सरकार लोकपाल कानून बना देती, तो शायद उन्हें पार्टी बनाने की ज़रूरत ही न पड़ती।

दिल्ली सरकार के कामकाज पर बात करते हुए उन्होंने भ्रष्टाचार खत्म करने के उपायों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि पहले सरकारी ठेकों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता था, क्योंकि रेट सरकारी अधिकारी तय करते थे। उनकी सरकार ने ऑनलाइन ऑक्शन की व्यवस्था शुरू की, जिससे राजस्व दोगुना या तिगुना हो गया और पारदर्शिता आई। उन्होंने कहा कि जो ज्यादा बोली लगाएगा, वही ठेके ले जाएगा, यह एक सीधी और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था है। जेल से सरकार चलाने के मुद्दे पर केजरीवाल ने कहा कि विपक्षी ताकतें जानबूझकर मुख्यमंत्रियों पर फर्जी मुकदमे कर उन्हें गिरफ्तार करवाती हैं, ताकि उनकी सरकारें गिराई जा सकें। उन्होंने दावा किया कि वे इस रणनीति का मुकाबला करना चाहते थे कि गिरफ्तारी के बावजूद इस्तीफा नहीं देंगे और सरकार जेल से ही चलाएंगे। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश की टिप्पणी का भी हवाला दिया कि सरकार जेल से क्यों नहीं चल सकती। उन्होंने इस संदर्भ में कुछ अन्य मुख्यमंत्रियों की सरकारों का भी उल्लेख किया जिन पर इसी तरह के आरोप लगाकर कार्रवाई की गई थी। केजरीवाल ने मतदाता सूची में कथित हेरफेर को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि स्थानीय स्तर पर एसडीएम की वोट जोड़ने या हटाने की शक्ति को एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से कुछ इलाकों में हटा दिया गया है। उन्होंने गोवा का उदाहरण दिया, जहां मुख्य निर्वाचन अधिकारी को बार-बार पत्र लिखकर लोगों के नाम जोड़ने की गुहार लगानी पड़ रही थी, जबकि यह शक्ति स्थानीय एसडीएम के पास होनी चाहिए थी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि दिल्ली में बैठे लोग मनमाने ढंग से वोट हटाते या जोड़ते रहे, तो सरकारें बदल नहीं पाएंगी और लोकतंत्र का सत्यानाश हो जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है कि जनता सरकार से असंतुष्ट होने पर उसे बदल सकती है। उन्होंने बताया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने इस पूरी प्रक्रिया पर नज़र रखने के लिए एक बड़ी टीम बनाई है।

गौरव गोगोई का बीजेपी-एआईडीयूएफ पर हमला, मुश्किल में पड़ते ही अजमल को बुलाते हैं हिमंत

गुवाहाटी (एजेंसी)। असम में चुनावी सरगर्मियों के बीच भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी), ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईडीयूएफ) और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हुआ हैं। कांग्रेस की असम इकाई के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा और एआईडीयूएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल पर निशाना साधकर दोनों दलों के बीच 'गुप्त तालमेल' का आरोप लगाया। कोलमौबाड़ी में कांग्रेस उम्मीदवार शिवमणि बोरा के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा में गोगोई ने कहा कि जब भी मुख्यमंत्री शर्मा मुश्किल में पड़ते हैं, वह 108 एंबुलेंस सेवा की तरह अजमल को बुलाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और एआईडीयूएफ गरीब लोगों का राजनीतिक इस्तेमाल करने के लिए साथ काम कर रहे हैं, जबकि उनके नेता मुंबई और दुबई में अपनी संपत्ति बढ़ा रहे हैं।

गोगोई ने धुबरी लोकसभा चुनाव का जिक्र कर कहा कि 2024 में वहां की जनता ने अजमल को करीब 10 लाख मतों से हराया था। उन्होंने 2016 में दक्षिण सलमारा सीट से कांग्रेस नेता वाजेद अली चौधरी द्वारा अजमल को हराए जाने का भी उल्लेख किया। कांग्रेस नेता गोगोई ने आरोप लगाया कि अब सीएम शर्मा एआईडीयूएफ को राजनीतिक रूप से मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार देवाशीष शर्मा पर आरोप लगाकर कहा कि जिला आयुक्त के रूप में उनके कार्यकाल में निर्दोष लोगों को कथित तौर पर बांग्लादेश भेजा गया तथा बेदखली अभियानों के जरिए लोगों को परेशान किया गया। गोगोई ने मुख्यमंत्री पर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के कार्यकाल का भी उल्लेख किया और मतदाताओं से कांग्रेस उम्मीदवार शिवमणि बोरा के समर्थन की अपील की।

इस बार यूपी में पीडीए की सरकार बनेगी, बीजेपी को 50 सीटें भी नहीं मिलेंगी

-सपा सांसद अवधेश प्रसाद का दावा, देश गंभीर स्थिति का सामना कर रहा

अयोध्या, एजेंसी।
समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने इंडिया ब्लॉक की बैठक और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। सांसद ने दावा किया कि इस बार पीडीए की सरकार बनेगी और बीजेपी को 50 सीटें भी नहीं मिलेंगी। इंडी गठबंधन की बड़ी बैठक पर अवधेश प्रसाद ने कहा कि देश एक गंभीर और चिंताजनक स्थिति का सामना कर रहा है। युवाओं और छात्रों पर लाठीचार्ज, फायरिंग, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। छात्रों ने जायज मांगों को लेकर जंतर-मंतर पर महीने भर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बावजूद सरकार ने उनकी मांगों को सुनने के बजाय अड़ियल रवैया अपनाया।

उन्होंने कहा कि किसानों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली का भारी संकट है और कई इलाकों में रात के समय बिजली नहीं रहती। महंगाई लगातार बढ़ रही है और हमारी अर्थव्यवस्था अमेरिका पर निर्भर हो गई है। हमारी विदेश नीति कमजोर हुई है, लेकिन इस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं हो रही है। भ्रष्टाचार और हत्याएं भी बढ़ रहीं हैं। इन हालात में यह बैठक बहुत अहम है।

अखिलेश यादव के चुनावी मेनिफेस्टो पर अवधेश प्रसाद ने कहा कि महिलाओं को 40,000 रुपए और लैपटॉप दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में बंद हुए 28,000 स्कूल फिर से खोले जाएंगे और शिक्षा का स्तर सुधारा जाएगा। किसानों को मदद और मुफ्त बिजली मिलेगी। इन सभी बातों का जिक्र हमारे घोषणा-पत्र में है। हमारे लिए चुनावी घोषणा-पत्र किसी धार्मिक ग्रंथ की तरह है और यह हमारे और हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बाध्यकारी है। सरकार बनने के बाद घोषणा-पत्र में कही गई हर बात को लागू किया जाएगा।

सपा सांसद ने कहा कि जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, सीएम योगी की परेशानी बढ़ती जा रही है। इस बार पीडीए की सरकार बनेगी और बीजेपी को 50 सीटें भी नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री को अपनी राजनीतिक पहचान से जुड़े मुद्दों की तो चिंता है, लेकिन राज्य की जनता की समस्याओं की कोई परवाह नहीं है। उन्हें लोगों के कल्याण, विकास या भलाई की कोई चिंता नहीं है। राज्य में किसानों की आत्महत्या, बढ़ते अपराध और मौतों को लेकर चिंता है, लेकिन इन मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

भाजपा का कांग्रेस पर हिंदू समाज को बांटने का गंभीर आरोप

नई दिल्ली , एजेंसी।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के उस बयान पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है, जिसमें उन्होंने राम को अमीरों का और शिव को गरीबों का भगवान बताया था। भाजपा प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से हिंदू समाज को विभाजित करने के हर षड्यंत्र में शामिल रहती है। बीजेपी सांसद त्रिवेदी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को नास्तिक बातकर कहा कि उन्होंने 2014 के चुनाव में ईश्वर के नाम की शपथ ली, लेकिन 2024 में अंग्रेजी में शपथ ली। उन्होंने याद दिलाया कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जुबली हिल्स के उपचुनाव में पहले ही कांग्रेस मतलब मुसलमान और मुसलमान मतलब कांग्रेस का उद्घोष कर चुके हैं।

भाजपा प्रवक्ता ने कांग्रेस पर हिंदू समाज को दक्षिण और उत्तर में विभाजित करने का भी प्रयास करने का आरोप लगाया। उन्होंने कर्नाटक के वित्त मंत्री डीके सुरेश के दक्षिण ज्यादा टैक्स दे रहा है और पी. चिदंबरम के उत्तर भारत नहीं होता, तब दक्षिण बहुत प्रगति करता जैसे बयानों का हवाला दिया। त्रिवेदी ने रेवंत रेड्डी के हम द्रविड़ियन हैं और वे आर्यन हैं वाले बयान को मूर्खतापूर्ण और निराधार सिद्धांत करार दिया। बीजेपी नेता त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस प्रांतों, भाषा और फिर जाति के आधार पर भी विभाजन करना चाहती है। उन्होंने राहुल गांधी के स्मैश पेट्रीआर्की (पितृसत्ता को तोड़ो) बयान का जिक्र कर कहा कि यह सिर्फ हिंदू समाज के लिए है, क्योंकि जब केरल का ग्रैंड मुफ्ती कहता है कि महिलाओं को तिजोरी में नेकलेस की तरह रखना चाहिए, तब कांग्रेस नेता चुप रहते हैं। भाजपा ने कांग्रेस पर भगवानों को भी विभाजित करने का आरोप लगाकर उसकी विभाजनकारी राजनीति की कड़ी निंदा की।

लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने वालों को सजा दिलाएगा इंडिया ब्लॉक: राहुल गांधी

नई दिल्ली, एजेंसी।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया ब्लॉक भारतीय लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने वालों को सजा दिलाना सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि संबंधित लोगों का पद या वरिष्ठता मायने नहीं रखती, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र देश के हर नागरिक से बड़ा है। नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया ब्लॉक की बैठक के बाद राहुल गांधी ने कहा कि विपक्षी दलों के नेताओं ने मिलकर संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी ली है। राहुल गांधी ने कहा कि बैठक में चुनावों में कथित 'वोट चोरी' का मुद्दा प्रमुखता से उठा। उन्होंने दावा किया कि विपक्षी दलों का मानना है कि भाजपा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने भारतीय लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं की व्यक्तिगत प्रतिबद्धता है कि लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। कांग्रेस सांसद ने कहा कि विपक्ष जनता तक यह बात पहुंचाने में काफी हद तक सफल रहा है कि चुनावों में कथित अनियमितताओं को लेकर गंभीर सवाल हैं। उनके मुताबिक, युवाओं के बीच भी इन मुद्दों को लेकर असंतोष और प्रतिरोध की भावना दिख रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं को लगता है कि देश में जो कुछ हो रहा है, उसमें बदलाव की जरूरत है। राहुल गांधी ने विपक्षी नेताओं को संविधान का सामूहिक रक्षक बताते हुए कहा कि सभी दलों के साथ मिलकर काम करना उनके लिए सम्मान की बात है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले महीनों में विपक्ष देश में बड़े बदलाव लाएगा। इंडिया ब्लॉक के प्रमुख नेताओं ने बैठक में चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर उठाए जा रहे सवालों और देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की रणनीति पर चर्चा की। कांग्रेस ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को वापस लेने की मांग दोहरा दी। विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग के रवैये पर सवाल उठाकर कथित तौर पर त्रुटिपूर्ण और पक्षपातपूर्ण बताया। बैठक का उद्देश्य इन मुद्दों पर विपक्षी दलों को एकजुट करना और आगे के साझा कार्यक्रमों की रणनीति तय करना था।

गंगा कटाव से रेल ट्रैक पर मंडराया खतरा, दूसरे दिन भी युद्धस्तर पर बचाव कार्य जारी

झुंझरी पुल के समीप डाउन लाइन से महज 13 मीटर दूर पहुंचा कटाव, सभी ट्रेनों का परिचालन रोका गया

पप्पु पंडित/बिभा

साहेबगंज। बहरवा-साहेबगंज रेलखंड पर महाराजपुर एवं सकरीगली के बीच झुंझरी पुल के समीप गंगा नदी का कटाव लगातार बढ़ने से रेलवे प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। मंगलवार को अचानक तेज हुए कटाव के बाद रेल ट्रैक की सुरक्षा को लेकर रेलवे ने तत्काल बचाव कार्य शुरू किया था। बुधवार को लगातार दूसरे दिन भी मालदा रेल मंडल के एडीआरएम अमरेंद्र कुमार मौर्य की निगरानी में कटावरोधी कार्य युद्धस्तर पर जारी रहा। जानकारी के अनुसार, डाउन लाइन के पोल संख्या 219/32 के समीप मंगलवार दोपहर के बाद गंगा की ओर से अचानक कटाव तेज हो गया। कटाव धीरे-धीरे बढ़ते हुए रेल पटरी से करीब 13 मीटर की दूरी तक पहुंच गया। रेल लाइन के इतने करीब कटाव पहुंचने से रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया और अधिकारियों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया।

ट्रैक की सुरक्षा के लिए डाले जा रहे बोल्डर

कटाव को आगे बढ़ने से रोकने के लिए रेलवे की ओर से मौके पर विभिन्न संसाधनों के साथ बचाव कार्य किया जा रहा है। कटाव प्रभावित हिस्से में गर्दी, बोल्डर डालकर तट को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। रेलवे कर्मी लगातार कटाव वाले हिस्से की निगरानी कर रहे हैं। गंगा के जलस्तर और कटाव की दिशा पर भी नजर रखी जा रही है, ताकि स्थिति बिगड़ने पर तत्काल आवश्यक कदम उठाया जा सके। रेलवे प्रशासन की प्राथमिकता फिलहाल रेल ट्रैक को सुरक्षित करना है। इसी वजह से कटावरोधी कार्य में तेजी लाने के लिए रेल परिचालन को प्रभावित किया गया है।

ट्रेनों का परिचालन रद्द, कार्य पूरा होने के बाद होगा निर्णय

कटावरोधी कार्य को देखते हुए इस रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन फिलहाल रद्द रखा गया है, ताकि बचाव कार्य के दौरान किसी प्रकार का खतरा न हो और रेलवे कर्मी सुरक्षित तरीके से काम कर सकें। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, शाम चार बजे तक कटावरोधी कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं मालदा रेल मंडल के एडीआरएम अमरेंद्र कुमार मौर्य ने बताया कि कार्य पूरा होने के बाद तकनीकी शाखा के अधिकारियों द्वारा रेल लाइन एवं ट्रैक की सुरक्षा की जांच की जाएगी। तकनीकी टीम के मार्गदर्शन और स्थिति के आकलन के बाद ही रेल परिचालन को लेकर आगे का निर्णय लिया जाएगा।

तकनीकी जांच के बाद खुलेगा रेल मार्ग

रेलवे प्रशासन द्वारा केवल कटाव वाले हिस्से को मजबूत करने पर ही ध्यान नहीं दिया जा रहा है, बल्कि ट्रैक की स्थिति की तकनीकी जांच भी की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि कटावरोधी कार्य पूरा होने के बाद यह सुनिश्चित किया जाएगा कि रेल लाइन सुरक्षित है या नहीं। इसके बाद ही ट्रेनों के परिचालन को बहाल करने पर निर्णय लिया जाएगा। वहीं, यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे की ओर से स्पेशल ट्रेन के परिचालन की भी जानकारी दी गई है। रेल प्रशासन स्थिति के अनुसार यात्रियों के आवागमन को सुचारू रखने का प्रयास कर रहा है।

लगातार निगरानी में रेलवे अधिकारी

गंगा के कटाव की गंभीरता को देखते हुए रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर लगातार कैंप कर रहे हैं। एडीआरएम अमरेंद्र कुमार मौर्य स्वयं बचाव कार्य की निगरानी कर रहे हैं। रेलवे की टीम उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से कटाव को आगे बढ़ने से रोकने में जुटी है। स्थानीय स्तर पर भी गंगा के किनारे तेजी से हो रहे कटाव को लेकर लोगों में चिंता बनी हुई है। रेल ट्रैक से कटाव की दूरी कम होने के कारण रेलवे प्रशासन किसी भी तरह का जोखिम लेने के मूड में नहीं है। फिलहाल पूरा ध्यान कटाव प्रभावित हिस्से को मजबूत करने और रेल लाइन की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। मौके पर मुख्यालय के सीबी पंकज कुमार, डीप्टी चीफ अरूण कुमार सहित रेलवे के अधिकारी व कर्मी दिन रात लगे हुए है।

सफाई कर्मियों को किया गया सम्मानित

बिभा संवाददाता

उधवा । सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उधवा में बुधवार को स्वच्छता ही सेवा 2026 के तहत सफाई कर्मियों के सम्मान एवं स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य सफाई कर्मियों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के साथ-साथ उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। कार्यक्रम का आयोजन मास्टर जलसहिया असनारा बीबी की पहल पर किया गया। कार्यक्रम के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों ने सफाई कर्मियों को सम्मानित किया। इसके बाद उनकी स्वास्थ्य जांच की गई। चिकित्सकों ने सफाई कार्य से जुड़े कर्मियों के स्वास्थ्य को लेकर आवश्यक सावधानियों की जानकारी दी। उन्हें कार्य के दौरान सुरक्षा उपकरणों का अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करने की सलाह दी गई। ताकि काम के दौरान किसी प्रकार के संक्रमण या अन्य स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से बचा जा सकें। चिकित्सकों ने सफाई कर्मियों को व्यक्तिगत स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने की भी सलाह दी। हाथों की नियमित सफाई,साफ कपड़ों का उपयोग तथा कार्य समाप्त करने के बाद स्वयं की स्वच्छता बनाए रखने के महत्व के बारे में बताया गया। इसके अलावा संतुलित एवं पौष्टिक आहार लेने और समय-समय पर स्वास्थ्य जांच कराने की सलाह भी दी गई। मौके पर चिकित्सक डॉ. सैय्यद सद्दाम ने कहा कि सफाई कर्मचारी स्वास्थ्य व्यवस्था की अहम कड़ी है। अस्पताल एवं आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ रखने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मियों की नियमित स्वास्थ्य जांच जरूरी है। क्योंकि इससे किसी बीमारी के लक्षणों की समय पर पहचान कर आवश्यक उपचार शुरू किया जा सकता है। उन्होंने सफाई कर्मियों को अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं बरतने तथा किसी प्रकार की परेशानी होने पर चिकित्सकीय सलाह लेने की बात कही। कार्यक्रम में सफाई कर्मियों ने भी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त की और चिकित्सकों से अपनी समस्याओं को साझा किया। स्वास्थ्य कर्मियों ने उन्हें स्वच्छता और स्वास्थ्य के बीच संबंध के बारे में भी जागरूक किया। कार्यक्रम के दौरान स्वच्छता ही सेवा अभियान के उद्देश्यों पर भी चर्चा की गई। मौके पर डॉ. अभिनंदन कुमार,बीपीएम अनिल पाल, सावित्री देवी सहित अन्य मौजूद थे।

उपायुक्त ने की आपूर्ति विभाग की समीक्षा आज से शुरू होगा किसानों का पंजीकरण

बिभा संवाददाता

साहेबगंज । धान अधिप्राप्ति समेत आपूर्ति विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं और कार्यों की समीक्षा को लेकर मंगलवार को उपायुक्त दीपक कुमार दूबे की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। कार्यालय प्रकोष्ठ में हुई बैठक में धान अधिप्राप्ति की तैयारियों, गोदाम निर्माण, राशन कार्ड डिलीशन और खाद्य सुरक्षा योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में उपायुक्त ने एक अक्टूबर से किसानों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू करने को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने धान अधिप्राप्ति से जुड़ी सभी तैयारियां समयबद्ध तरीके से पूरी करने तथा प्रक्रिया के सुचारु संचालन पर विशेष ध्यान देने को कहा। इसके अलावा जिले के विभिन्न प्रखंडों में निमार्णाधीन 1000 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदामों की स्थिति की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्माण कार्य की गुणवत्ता की नियमित निगरानी करने का निर्देश दिया। साहिबगंज और राजमहल के अनुमंडल पदाधिकारियों को निमार्णाधीन गोदामों की गुणवत्ता की जांच कर अगली बैठक में जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया। साथ ही उपायुक्त ने पुराने गोदामों की मरम्मत में भी गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने तथा नए गोदामों के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा कराने के लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया। वहीं समीक्षा के दौरान जिले में राशन कार्ड डिलीशन की अद्यतन स्थिति की जानकारी भी ली गई। उपायुक्त ने शेष डिलीशन कार्य में तेजी लाने के साथ पात्र लाभुकों को समयबद्ध तरीके से राशन सुविधा से जोड़ने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी योग्य परिवार खाद्य सुरक्षा योजना के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने भंडारण क्षमता, राशन वितरण व्यवस्था और निगरानी तंत्र को और मजबूत करने तथा सभी कार्यों में पारदर्शिता एवं तत्परता बनाए रखने पर जोर दिया। मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी सह जिला आपूर्ति पदाधिकारी अमर जॉन आइन्द, सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, विभिन्न प्रखंडों के गोदाम प्रबंधक, संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी मौजूद थे।

जलापूर्ति योजनाओं का कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करें: डीडीसी

बिभा संवाददाता

साहेबगंज । ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सुचारु एवं गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने को लेकर बुधवार को उप विकास आयुक्त सतीश चंद्रा की अध्यक्षता में पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल की विभिन्न जलापूर्ति योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। बैठक कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित की गई। इस दौरान जिले में संचालित बहु ग्रामीण जलापूर्ति योजना एवं एकल ग्रामीण जलापूर्ति योजना (क्लस्टर) की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की गई। उप विकास आयुक्त ने योजनाओं की वर्तमान स्थिति की जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारियों, अभियंताओं और संवेदकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। वहीं डीडीसी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी जलापूर्ति योजनाओं का कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाए। निर्माण कार्य में गुणवत्ता के मानकों का विशेष ध्यान रखने तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरतने को कहा गया। उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन की नियमित निगरानी करने और कार्य में अनावश्यक विलंब नहीं होने देने का निर्देश दिया। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की जरूरत को देखते हुए जलापूर्ति योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने पर जोर दिया। साथ ही बैठक मे पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के संबंधित पदाधिकारी, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता एवं संवेदक उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत दिया गया प्रशिक्षण

बिभा संवाददाता

उधवा । उधवा प्रखंड मुख्यालय स्थित उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय गड़ल्ली में बुधवार को प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत संकुल साधनसेवी एवं संयोजिका को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। जानकारी के अनुसार प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य विद्यालयों में संचालित मध्याह्न भोजन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी,स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण बनाना है। कार्यक्रम में सीआरपी एवं प्रत्येक संकुल से एक संयोजिका की अनिवार्य रूप से भागीदारी रही। प्रशिक्षण के दौरान संकुल साधनसेवी एवं संयोजिका को भोजन तैयार करने के दौरान स्वच्छता,खाद्य सामग्री के सुरक्षित रख- रखाव, साफ- सफाई तथा बच्चों को पौष्टिक एवं सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने से संबंधित आवश्यक जानकारी दी गई। बीआरपी सह प्रशिक्षक मोहन लाल साहा ने भोजन बनाने से पहले हाथों की सफाई,रसोईघर की स्वच्छता और बर्तनों की साफ-सफाई पर विशेष जोर दिया। इस दौरान प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी अटल बिहारी भगत ने बताया कि पीएम पोषण योजना का मुख्य उद्देश्य विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। इसके लिए रसोइया-सह-सहायिकाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें योजना के निर्धारित मानकों के अनुसार कार्य करने और भोजन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए आवश्यक जानकारी दी गई। बीपीओ ने बताया कि प्रशिक्षण प्राप्त कर आगे संकुल स्तर पर रसोईया सह सहायिका को प्रशिक्षण दिया जाएगा। मौके पर संकुल साधनसेवी बाबूलाल मंडल,अशोक पाल,दिजेंद्र मंडल सहित अन्य मौजूद थे।

पीएम पोषण योजना की समीक्षा, कम छात्र उपस्थिति पर बीपीओ से मांगा जाएगा स्पष्टीकरण

बिभा संवाददाता

साहेबगंज । पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और बच्चों को योजना का लाभ सुनिश्चित कराने को लेकर बुधवार को जिला स्तरीय स्टेयरिंग-सह-मॉनिटरिंग समिति की बैठक हुई। उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी दीपक कुमार दूबे की अध्यक्षता में कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित बैठक में योजना की प्रखंडवार प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान पीएम पोषण योजना के तहत विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की औसत उपस्थिति की समीक्षा की गई। जिन प्रखंडों में अपेक्षित औसत उपस्थिति नहीं पाई गई, वहां उपायुक्त ने संबंधित प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारियों (बीपीओ) से स्पष्टीकरण लेने का निर्देश दिया। उन्होंने विद्यालयों में बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। बैठक में छात्र-छात्राओं को दी जाने वाली आयरन एवं फोलिक एसिड की गोलियों की उपलब्धता और वितरण की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि विद्यालयों में नामांकित बच्चों की संख्या के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में आईएफए की गोलियां उपलब्ध रहें। उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी को इस संबंध में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा। सभी बीपीओ को निर्देश दिया गया कि किसी भी परिस्थिति में विद्यालयों में आईएफए की कमी नहीं होनी चाहिए और बच्चों के बीच इसका समय पर वितरण सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा विद्यालयों में नेचुरल गार्डन की स्थिति तथा छात्र-छात्राओं की आधार सीडिंग की प्रगति की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को इन कार्यों में तेजी लाने और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मौके पर उप विकास आयुक्त सतीश चंद्रा, जिला शिक्षा पदाधिकारी नयन कुमार, जिला शिक्षा अधीक्षक उर्मिला हांसदा, जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी डॉ. किरणमाल, सभी संबंधित बीपीओ समेत अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी मौजूद रहे।

पूर्व मध्य रेल
ई–निविदा सूचना
उप मुख्य अभियंता (निर्माण) का कार्यालय, धनबाद, दिनांक: 26.09.2026

क्रम संख्या 1, ई–निविदा संख्या: ECR-DCE-DHN-03-26-27, कार्य का नाम, स्थान तथा समापन अवधि : कोडरमा–तिलैया नई B.G.रेल लाइन परियोजना से संबंधित कोडरमा (Ch. 64.500) से खेरौन्ध (यार्ड को छोड़कर) (Ch. 24.00) के बीच के सेक्शन को चालू करने से जुड़े शेष कार्य एवं सेक्शन खुलने के बाद इसके रखरखाव के कार्य (18 महीने)।, कार्य का लगभग लागत (रूपये में): Rs. 81,06,82,748.81/-ब्याने की राशि (रूपये में): ब्याने की राशि (रूपये में) http://www.ireps.gov.in पोर्टल पर दिखाये राशि के अनुसार लागू, निविदा बंद होने एवं खुलने की तारीख एवं समय: ई–निविदा बंद होने की तारीख 23.10.2026 को 15:00 बजे तक ई–निविदा खुलने की तारीख 23.10.2026 को 17.30 बजे से, बेवसाईट का विवरण: http://www.ireps.gov.in ई–निविदा के तहत मैनुअल प्रस्ताव स्वीकार नहीं की जायेगी।
नोट:– (i) हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में सूचना में अंतर होने पर अंग्रेजी भाषा में सूचना ही मान्य होगी।, (ii) प्रत्याशित निविदादाताओं को यह सलाह दी जाती है कि इस ई–निविदा की जारी होने की कोई भी परिवर्तन और शुद्धि पत्र की ओर ध्यान देने के लिए निविदा बंद होने की अंतिम तिथि से कम से कम पंद्रह दिन पहले वेबसाइट http://www.ireps.gov.in अवलोकन करें।, (iii) डाक/कूरियर/फैक्स या हाथ से भेजा गया कोई भी ई–निविदा स्वीकार नही किया जाएगा। निविदा की ऐसी सभी मैन्युअल प्रस्तुति, चाहे वह फर्म के लेटर पैड पर हो या समय पर प्राप्त हो, स्वीकार नहीं की जाएगी। उपरोक्त ई–निविदा दस्तावेज और पूरी जानकारी वेबसाइट http://www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है।
उप–मुख्य अभियन्ता (निर्माण)
पूर्व मध्य रेल, धनबाद
पीआर/1026/सीओएन डीएचएन/सीओएनएसटी/टी/26–27/52

पूर्व मध्य रेल
ई–निविदा सूचना
उप मुख्य अभियंता (निर्माण) का कार्यालय, धनबाद, दिनांक: 26.09.2026

क्रम संख्या 1, ई–निविदा संख्या: ECR-DCE-DHN-04-26-27, कार्य का नाम, स्थान तथा समापन अवधि : उप मुख्य अभियंता (निर्माण)/धनबाद के अधिकार क्षेत्र में तिलैया से कोडरमा के बीच नई BG लाइन से संबंधित खेरौन्ध (छोड़कर) से लेकर मेजर ब्रिज 108 (छोड़कर) तक और किमी 41.500 से 42.220 (बाई ओर बढ़ते हुए चेनेज की दिशा में) और किमी 41.710 से 41.900 (दाईं ओर बढ़ते हुए चेनेज की दिशा में) तक संवेदनशील जगहों पर चट्टान गिरने से बचाव, ढलान को स्थिर करने और मलबे के बहाव से बचाव के साथ–साथ अन्य संबंधित विविध कार्य। (18 महीने)।, कार्य की लगभग लागत (रूपये में): Rs. 79,27,86,067.05/-, ब्याने की राशि (रूपये में): ब्याने की राशि (रूपये में) http://www.ireps.gov.in पोर्टल पर दिखाये राशि के अनुसार लागू, निविदा बंद होने एवं खुलने की तारीख एवं समय: ई–निविदा बंद होने की तारीख 23.10.2026 को 15:00 बजे तक ई–निविदा खुलने की तारीख 23.10.2026 को 17.30 बजे से, बेवसाईट का विवरण: http://www.ireps.gov.in ई–निविदा के तहत मैनुअल प्रस्ताव स्वीकार नहीं की जायेगी।
नोट:– (i) हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में सूचना में अंतर होने पर अंग्रेजी भाषा में सूचना ही मान्य होगी।, (ii) प्रत्याशित निविदादाताओं को यह सलाह दी जाती है कि इस ई–निविदा की जारी होने की कोई भी परिवर्तन और शुद्धि पत्र की ओर ध्यान देने के लिए निविदा बंद होने की अंतिम तिथि से कम से कम पंद्रह दिन पहले वेबसाइट http://www.ireps.gov.in अवलोकन करें।, (iii) डाक/कूरियर/फैक्स या हाथ से भेजा गया कोई भी ई–निविदा स्वीकार नही किया जाएगा। निविदा की ऐसी सभी मैन्युअल प्रस्तुति, चाहे वह फर्म के लेटर पैड पर हो या समय पर प्राप्त हो, स्वीकार नहीं की जाएगी। उपरोक्त ई–निविदा दस्तावेज और पूरी जानकारी वेबसाइट http://www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है।
उप–मुख्य अभियन्ता (निर्माण)
पूर्व मध्य रेल, धनबाद
पीआर/1027/सीओएन डीएचएन/सीओएनएसटी/टी/26–27/60

राधानगर में आजीविका सखी मंडल की वार्षिक आमसभा आयोजित

बिभा संवाददाता

राधानगर । उधवा प्रखंड क्षेत्र के राधानगर पंचायत भवन सभागार में बुधवार को संकुल स्तरीय आजीविका सखी मंडल की वार्षिक आमसभा आयोजित की गई। कार्यक्रम में पंचायत के जनप्रतिनिधियों के अलावा स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। आमसभा में समूहों की गतिविधियों, उपलब्धियों, आय-व्यय और आगामी कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई। जानकारी के अनुसार राधानगर संकुल के अंतर्गत चार पंचायतें आती है। इन पंचायतों में कुल 260 स्वयं सहायता समूह संचालित है। जिनसे 2824 सदस्य जुड़ी हुई है। वार्षिक आमसभा के दौरान स्वयं सहायता समूहों की ओर से वर्षभर की आय-व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया। इसके साथ ही समूहों के माध्यम से संचालित विभिन्न आजीविका गतिविधियों और अब तक की उपलब्धियों की जानकारी भी साझा की गई। कार्यक्रम में बताया गया कि ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से विभिन्न आजीविका गतिविधियां संचालित की जा रही है। महिलाओं को मुर्गी पालन सहित अन्य स्वरोजगार गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है। वहीं प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं और युवाओं को कौशल विकास तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का भी प्रयास किया जा रहा है। मौके पर नेहा स्वर्णकार ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर ग्रामीण महिलाएं स्वरोजगार की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। समूहों के माध्यम से महिलाओं में बचत की आदत के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी बढ़ी है। जिससे वे आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है। आमसभा में स्वयं सहायता समूहों की उपलब्धियों की समीक्षा करते हुए आगामी कार्ययोजना पर भी चर्चा की गई। अधिक से अधिक ग्रामीण महिलाओं को आजीविका गतिविधियों से जोड़ने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर जोर दिया गया। मौके पर परवीन कुमार,सिद्धांत मंडल,हुमायूं मियां, अचिंत मंडल,पूनम कुमारी,पिंकी कुमारी, अमल मंडल,पिकाय घोष,मामुनि मंडल,मीना साहा,आशा देवी,चांदनी खातून,अंजू देवी, सुनीता देवी सहित अन्य मौजूद थे।

मौर्य एजुकेशन सेंटर में विकसित भारत ऑनलाइन क्विज आयोजित

बिभा संवाददाता

बरहरवा। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग-2027 के तहत बुधवार को कुशवाहा टोला स्थित मौर्य एजुकेशन सेंटर में विकसित भारत ऑनलाइन क्विज का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व माय भारत की राष्ट्रीय युवा स्वयंसेविका प्रियंका कुमारी ने किया। क्विज में मौर्य एजुकेशन सेंटर के दर्जनों छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में बतौर अतिथि पूर्व नगर उपाध्यक्ष सह कोचिंग संचालक लोकेश कुशवाहा मौजूद रहे। इस दौरान एनवाईवी प्रियंका कुमारी ने विद्यार्थियों को क्विज की प्रक्रिया, पंजीकरण तथा प्रतियोगिता के विभिन्न चरणों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि क्विज के माध्यम से युवाओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के साथ-साथ देश के विकास से जुड़े विषयों पर अपनी सोच और विचार रखने का अवसर मिलेगा। चयनित प्रतिभागियों को आगे जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा प्रदर्शित करने का मौका मिल सकता है। वहीं क्विज में देश, इतिहास, विज्ञान, सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाओं और विकसित भारत से जुड़े विभिन्न विषयों पर प्रश्न पूछे गए। विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ प्रश्नों के उत्तर दिए। पूर्व नगर उपाध्यक्ष लोकेश कुशवाहा ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से विद्यार्थियों में ज्ञान के साथ आत्मविश्वास और प्रतियोगी भावना का विकास होता है। युवाओं को ऐसे अवसरों का लाभ उठाकर आगे बढ़ना चाहिए। मौके पर मौर्य एजुकेशन सेंटर के दर्जनों छात्र-छात्राएं मौजूद थे।

संक्षिप्त डायरी

बिहार में किसानों को फ्री में मिलेगी बिजली, सोलर प्लांट के लिए लैंड बैंक भी होगा तैयार

पटना (एजेंसी) बिहार के किसानों की सहूलियत के लिए सरकार कई योजनाओं को लेकर तैयारी कर रही है. अब उन्हें मुफ्त में बिजली देने की तैयारी है, जिससे उन्हें खेतों की सिंचाई में आसानी हो सके. इतना ही नहीं, सोलर प्लांट के लिए लैंड बैंक भी तैयार किया जाएगा. बिहार के किसानों से जुड़ी जरुरी खबर है. सरकार किसानों को फ्री में बिजली देने की तैयारी में है. इससे किसानों के लिए सिंचाई की परेशानी काफी हद तक कम हो सकेगी. मुफ्त बिजली मिलने से खेतों को सींचना आसान हो जाएगा. इस योजना को लेकर प्रस्ताव ऊर्जा विभाग की ओर से तैयार किया जा रहा है. जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी मिलने की संभावना जताई जा रही है. अभी बिजली के लिए कितने देने पड़ते हैं रुपये? जानकारी के मुताबिक, वर्तमान में किसानों को खेतों की सिंचाई के लिए 55 पैसे प्रति यूनिट बिजली पे करना होता हैं. लेकिन सोलर सिस्टम से खेती के लिए 2560 फीडर से 2585 मेगावाट बिजली तैयार करने की योजना है. यह अगले तीन सालों में किया जाएगा. सरकार इसके लिए लगभग 2714 करोड़ रुपये खर्च करने की तैयारी में है. अगले 3 सालों में मिलेगी पर्याप्त बिजली माना जा रहा है कि सोलर पैनल के जरिए जो हरित ऊर्जा की खरीद के लिए ऊर्जा कंपनियों को खर्च करना पड़ता है, उसमें कमी आएगी. अभी खेती के लिए ऊर्जा की खरीद पर 6 रुपये 19 पैसे प्रति यूनिट खर्च किए जा रहे हैं. बताया जा रहा है कि सरकार एक करोड़ 5 लाख रुपये का अनुदान कृषि फीडर सोलराइजेशन करने वाली एजेंसियों को देगी. इस तरह से अगले तीन सालों में किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली मिल सकेगी. बिहार से जुड़ी अन्य ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें किसानों को होंगे ये फायदे सरकार की इस प्लानिंग से किसानों को खास फायदा हो सकेगा. किसानों के लिए खेती में लागत कम हो सकेगी. सौर ऊर्जा में उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आमदनी भी बढ़ सकेगी. इतना ही नहीं, प्रदूषण में भी कमी आ सकेगी. इस तरह से सरकार किसानों के लिए नई योजना बनाने में जुटी है, जिसका सीधा फायदा राज्य के किसानों को हो सकेगा. सोलर प्लांट के लिए तैयार होंगे लैंड बैंक दूसरी तरफ, सोलर पैनल लगाने को लेकर भी अपडेट है. मिली जानकारी के अनुसार, जिन भी राज्य में किसानों को फ्री में बिजली दी जा रही है, उन राज्यों के मॉडल की स्टडी कराई गई है. इसके बेसिस पर ही यह तय किया गया है कि सोलर प्लांट लगाने के लिए लैंड बैंक स्थापित किया जाएगा. इसके लिए निर्धारित राशि भी सोलर प्लांट के लिए जमीन देने वाले, किसानों और अन्य लोगों को दी जाएगी.

नितिन गडकरी 1 अक्टूबर को पटना में करेंगे एनएच की समीक्षा, सीएम आवास में होगी बैठक, सरकार रखेगी ये मांगें

पटना (एजेंसी) केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 1 अक्टूबर को पटना में एनएच परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे. मुख्यमंत्री आवास में सीएम संग बैठक में राज्य की प्रमुख मांगों पर भी चर्चा होगी. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी एक अक्तूबर को पटना आएंगे. अपने बिहार दौरे के दौरान वह राज्य में चल रही राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे. इस दौरान परियोजनाओं को तय गति से पूरा करने को लेकर संबंधित पदाधिकारियों को दिशा-निर्देश भी दिए जाएंगे. मुख्यमंत्री आवास में होगी समीक्षा बैठक नितिन गडकरी की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री आवास में होगी. बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी शामिल होंगे. राज्य में एनएच से जुड़ी परियोजनाओं की मौजूदा स्थिति, निर्माण की प्रगति और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है. एनएच निर्माण को लेकर राज्य सरकार रखेगी अपनी मांग बैठक में राज्य सरकार बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ी अपनी मांगों को भी केंद्रीय मंत्री के सामने रखेगी. राज्य सरकार की ओर से पूर्व में भेजे गये प्रस्तावों को मंजूरी देने का आग्रह भी किया जाएगा. इससे बिहार में एनएच से जुड़ी प्रस्तावित और लंबित परियोजनाओं को लेकर केंद्र के स्तर पर आगे की प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद रहेगी.

बाढ़ प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए मंत्री लखेंद्र पासवान ने मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया एक माह का वेतन

एजेंसी

पटना। बिहार में बाढ़ से प्रभावित परिवारों की सहायता एवं राहत कार्यों में सहयोग के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री लखेंद्र पासवान ने बुधवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात कर अपने एक माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में योगदान किया है।

मंत्री लखेंद्र पासवान ने कहा कि प्राकृतिक आपदा की इस कठिन घड़ी में बाढ़ प्रभावित परिवारों के साथ खड़ा होना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

मंत्री लखेंद्र पासवान ने कहा कि बाढ़ से प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है तथा जरूरतमंद परिवारों तक आवश्यक सहायता पहुँचाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में बाढ़ प्रभावित परिवारों के साथ वे स्वयं और पूरी एनडीए सरकार मजबूती से खड़ी है। सरकार का प्रयास है कि आपदा से प्रभावित प्रत्येक परिवार को आवश्यक सहायता उपलब्ध हो और उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। राहत एवं सहायता कार्यों में हरसंभव सहयोग के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रतिबद्ध है।

मंत्री श्री पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री राहत कोष आपदा और संकट की परिस्थितियों में प्रभावित लोगों की सहायता का महत्वपूर्ण माध्यम है।

उन्होंने आम लोगों से भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार मुख्यमंत्री राहत कोष में सहयोग करने की अपील की, ताकि बाढ़ प्रभावित परिवारों तक राहत और सहायता को और प्रभावी ढंग से पहुँचाया जा सके।

उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने हमेशा आपदा और विपरीत परिस्थितियों में एक-दूसरे का साथ दिया है। इस कठिन समय में भी सामूहिक सहयोग और संवेदनशीलता के माध्यम से बाढ़ प्रभावित परिवारों की मदद की जा सकती है। राज्य सरकार प्रभावित लोगों के जीवन को सामान्य बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के प्रति पूरी तरह सजग और प्रतिबद्ध है।

बाढ़ पीड़ितों की मदद को आगे आए विधायक दुलाल चंद्र गोस्वामी, सीएम राहत कोष में दिया एक माह का वेतन

कटिहार। बिहार में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए कदवा विधानसभा क्षेत्र के विधायक दुलाल चन्द्र गोस्वामी ने मानवीय पहल की है। उन्होंने बुधवार को अपने एक माह के वेतन की पूरी राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में दान कर दी। इस कदम का उद्देश्य बाढ़ प्रभावित इलाकों में चलाए जा रहे राहत और बचाव कार्यों को गति देना है। विधायक दुलाल चंद्र गोस्वामी ने बिहार विधान परिषद के मुख्य सचेतक एवं जनता दल (यूनाइटेड) के वरिष्ठ नेता संजय कुमार सिंह से मुलाकात कर उन्हें अपने एक माह के वेतन का चेक सौंपा। इस अवसर पर विधायक गोस्वामी ने कहा कि बाढ़ की इस भीषण प्राकृतिक आपदा ने बड़ी संख्या में परिवारों को बेघर और संकटग्रस्त कर दिया है। ऐसी कठिन परिस्थितियों में प्रभावित लोगों तक पहुंचना, उनका संबल बनना और राहत कार्यों में सहयोग करना हर जनप्रतिनिधि व नागरिक का प्राथमिक सामाजिक और मानवीय दायित्व है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आपदा पीड़ितों की त्वरित सहायता, भोजन-दवा की उपलब्धता और उनके सुरक्षित पुनर्वास के लिए चलाए जा रहे हर सरकारी व गैर-सरकारी प्रयास में वे लगातार सक्रिय भागीदारी निभाते रहेंगे।

एनडीए के सभी घटक दल संयुक्त रूप से चलाएं अभियान: नीतीश कुमार

पटना। जनता दल यूनाईटेड (जदयू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 7, सर्कुलर रोड स्थित अपने आवासीय कार्यालय में पार्टी नेताओं से विधान परिषद् की आठ सीटों पर हो रहे स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव का जायजा लिया और उन्हें जरूरी निर्देश दिए। इस दौरान जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, मंत्री एवं विधायक दल के नेता श्रवण कुमार, विधान परिषद् में सत्तारूढ़ दल के उपनेता ललन सर्राफ, मुख्य सचेतक संजय गांधी, मंत्री अशोक चौधरी, मंत्री जमां खां, मंत्री श्वेता गुप्ता, विधायक दुलाल चंद्र गोस्वामी, विधायक ललित नारायण मंडल आदि उपस्थित रहे। नीतीश कुमार ने पार्टी नेताओं से कहा कि सभी आठ सीटों पर एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी घटक दल एक साथ चुनाव अभियान चलाएं।

चिराग पासवान से उन्हीं के गठबंधन के नेता नाराज, बोले- शर्मिंदा हैं तो कुछ करें

पटना (एजेंसी) केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जमुई और समस्तीपुर में लड़कियों के साथ हुई घटना को लेकर सवाल खड़े किए थे. उन्होंने शर्मिंदगी की बात कही थी. केंद्रीय मंत्री के इस बयान के बाद एनडीए के नेता ही उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं. बिहार के जमुई और समस्तीपुर जिले के अलावा अन्य जिलों में लड़कियों के साथ छेड़खानी के मामले में राजनीतिक बयानबाजी खूब हुई. विपक्ष ने तो कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया ही लेकिन एनडीए के गठबंधन के नेताओं ने भी बयान दिए. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इस तरह की घटनाओं को लेकर शर्मिंदा होने की बात ही थी. केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने किया हमला चिराग पासवान के इस बयान को

लेकर एनडीए में खींचतान की खबर सामने आ रही है. एनडीए के घटक दल के नेता ने ही चिराग पासवान के खिलाफ और उन्हें नसीहत देते हुए बयान दे रहे हैं. केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तो साफ कहा कि जो इस तरह से बोल रहे हैं उनको समझना चाहिए कि शर्मिंदा हैं तो आपको अगली कार्रवाई करनी चाहिए. हम तो इस सरकार का हिस्सा रह कर गौरवान्वित महसूस करते हैं. आगे जीतन राम मांझी ने यह भी कहा, हमें गर्व है कि कि सम्राट चौधरी जैसे युवा और मजबूत मुख्यमंत्री बिहार को मिले हैं, जो त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं. बात विकास की हो या लॉ एंड ऑर्डर की, हर तरह से बहुत अच्छे से काम हो रहा है. नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार चल रही है. पहले कोई अपराध करता था तो एक अणे मार्ग बुलाकर सुलह कर दिया जाता था. लेकिन आज अपराध होने पर कार्रवाई की जाती है. बिहार सरकार के मंत्री ने दी नसीहत दूसरी तरफ, बिहार सरकार के मंत्री लखेंद्र पासवान ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को सीधे नसीहत ही दे दी है. लखेंद्र पासवान ने कहा, जो भी लोग प्रशासन से दुखी होने की बात कह रहे हैं, वह मीडिया से हटकर और सरकार के साथ बैठकर समाधान निकालें. यह ज्यादा सही रहेगा. उन्होंने यह भी कहा कि चिराग पासवान बड़े नेता हैं, उन्हें बिहार आकर ध्यान देना चाहिए. सरकार चिराग पासवान की राय मानने के लिए तैयार है. लेकिन बिहार में लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है. बिहार से जुड़ी अन्य ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें चिराग पासवान ने जताई थी शर्मिंदगी इस तरह से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को लेकर एनडीए के घटक दलों के नेताओं के बीच ही चर्चा तेज हो गई है. ऐसे में देखना होगा कि आगे इस मामले में और क्या कुछ बयानबाजी होती है. हाल ही में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मीडिया के सामने लड़कियों के साथ घटनाओं पर कहा था, आज की तारीख में कोई सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा. यह हमारी सरकार की चिंता है. सरकार का सहभागी होने के नाते मैं खुद इस सवाल से नहीं भाग सकता. आगे उन्होंने कहा था, मुझे शर्मिंदगी होती है कि मैं एक मिली जानकारी के मुताबिक, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अब उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर एक्शन मोड में आ गए हैं. 28 सितंबर को प्रयागराज में ह्ययूथ बोले तोह्म कार्यक्रम के दौरान यूपी में चुनाव लड़ने की बात कही. उन्होंने स्पष्ट किया था कि उनकी पार्टी लोजपा (रामविलास) यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है. लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि लोजपा (रामविलास) यूपी में एनडीए के साथ लड़ेगी या फिर अकेले, यह आने वाले दिनों में तय किया जाएगा.

पटना में खतरे के निशान के ऊपर गंगा, गोपालगंज-सारण समेत बिहार के इन नौ जिलों में बढ़ा बाढ़ का खतरा

पटना (एजेंसी) बिहार में नदियों का पानी तेजी से बढ़ रहा है. माना जा रहा है कि जल्द ही कई प्रमुख नदियां खतरे के निशान को पार कर सकतीं हैं. ऐसे में कई प्रभावित इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है. इस वजह से बिहार में लाखों की आबादी खतरे में है. मॉनसून कमजोर पड़ रहा है लेकिन बिहार में बाढ़ का तांडव जारी है. गंगा, गंडक, सोन, घाघरा जैसी प्रमुख नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है. केंद्रीय जल आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक कई जगह नदियों का जलस्तर लाल निशान के करीब पहुंच गया है. कुछ जगह नदियों का जलस्तर लाल निशान के पार पहुंच चुका है. गंडक नदी में आई बाढ़ की वजह से पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण में बाढ़ का विकराल रूप देखने को मिल रहा है. कई

तटबंध टूट गए और कई रिहायशी इलाके बाढ़ के पानी में डूब गए. गंडक नदी की बाढ़ के कारण लोग खुद का घर छोड़ने तक के लिए मजबूर हैं. इन दोनों जिले के अलावा गोपालगंज, सारण और वैशाली जिले में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं. पटना में उफान पर गंगा आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, सहरसा, दरभंगा, गोपालगंज और पूर्णिया के 24 प्रखंडों के 65 गांवों में 1.50 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है. पटना के गांधी घाट पर गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 17 सेंटीमीटर ऊपर रिकॉर्ड किया गया है. जलस्तर में इजाफे के अनुमान विभाग ने जताए हैं. दीघा घाट पर गंगा खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं. हाथीदह में जलस्तर 42 सेंटीमीटर और कहलगांव में 17 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है. ये नदियां भी रौद्र रूप में गंगा नदी के अलावा दूसरे नदियों की बात करें तो, पटना के मनेर में सोन नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है. जबकि गोपालगंज जिले में गंडक नदी उफान पर है. जिले में नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 176 सेंटीमीटर ऊपर है. इसके अलावा पश्चिम चंपारण नदी का जलस्तर 80 सेंटीमीटर तक बढ़ने की संभावना जताई गई है. दूसरी तरफ, सीवान जिले में घाघरा नदी भी रौद्र रूप में है. फिलहाल यह नदी खतरे के निशान से नीचे है लेकिन बढ़ोतरी की संभावना है. बिहार से जुड़ी अन्य ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें गोपालगंज और सारण में खतरा गहरा मिली जानकारी के अनुसार, गोपालगंज और सारण जिले में बाढ़ का खौफनाक मंजर देखने के लिए मिल रहा है. गोपालगंज जिले में गंडक नदी में आई बाढ़ की वजह से 43 गांवों में आफत आ गई है. घरों के साथ-साथ कई स्कूलों में पानी घुस गया है. लेकिन इस बीच प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट दिखा. बताया जा रहा है कि डीएम समीर सौरभ समेत अन्य अधिकारी बांध के पास रातभर पेट्रोलिंग करते रहे. दूसरी तरफ, सारण जिले की बात करें तो, गंडक नदी के उफान से सारण जिले के कई प्रखंडों में पानी घुस गया. अब तो किसानों की फसलें भी डूबने लगीं हैं. लाखों की आबादी गंडक में आई बाढ़ की वजह से प्रभावित हो रही है. खासकर निचले इलाकों में रह रहे लोगों की परेशानी बनी हुई है. आज भी नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी की संभावना है. लेकिन मौसम विभाग की ओर से यह संभावना जताई गई है कि अगले कुछ दिनों तक राज्य में बारिश से राहत रहेगी.

पश्चिम चंपारण पहुंचे CM सम्राट का बड़ा ऐलान, गंडक और कोसी नदी के तटबंधों का होगा पक्कीकरण

पटना (एजेंसी) मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पश्चिम चंपारण के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और गंडक व कोसी नदी के तटबंधों के पक्कीकरण की घोषणा की. जानिए इस बड़ी पहल से क्या है उम्मीदें. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बुधवार को करीब 12:02 बजे पश्चिम चंपारण के बथना स्थित पीएम श्री राजकीय +2 उच्च विद्यालय परिसर पहुंचे. हेलीकॉप्टर से पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों से बाढ़ की स्थिति और प्रशासनिक तैयारियों की जानकारी ली. उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर बनी व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया. मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान किया है. बिहार में गंडक और कोसी नदी के तटबंधों के पक्कीकरण का ऐलान किया है. इसके लिए सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है. इससे बाढ़ के दौरान तटबंधों की सुरक्षा मजबूत होने और प्रभावित इलाकों को राहत मिलने की उम्मीद है. मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए बथना से बनकटवा और शिवराजपुर तक प्रशासनिक और पुलिस टीमों को अलर्ट

रखा गया था. मुख्य सचिव और डीजीपी समेत अधिकारी मौजूद मुख्यमंत्री के पहुंचने से पहले ही मुख्य सचिव, डीजीपी समेत कई वरीय अधिकारी बथना पहुंच चुके थे. सांसद डॉ. संजय जायसवाल भी मौके पर मौजूद रहे. मुख्यमंत्री ने स्कूल परिसर में बने नवनिर्मित हेलीपैड, सुरक्षा व्यवस्था और बाढ़ आश्रय केंद्र से जुड़ी तैयारियों का भी जायजा लिया. बनकटवा के आगे का दौरा रद्द, पटना के लिए रवाना बथना में तैयारियों का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री को मच्छरगांवा होते हुए बनकटवा जाना था. वहां उन्हें आसपास के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करना था, लेकिन इसी बीच किसी वजह से उनका आगे का दौरा स्थगित कर दिया गया और वे हेलीकॉप्टर से वापस पटना के लिए लौट गए. बथना से बनकटवा तक प्रशासन अलर्ट मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर बथना, मच्छरगांवा, बनकटवा और शिवराजपुर इलाके में प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गयी थीं. पुलिस और प्रशासन की टीमें सुरक्षा के साथ-साथ मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवागमन की व्यवस्था संभाल रही थीं.

नीदरलैंड्स में गूंजा भारतीय लोकगीत, मैथिली ठाकुर ने अपने सुर से बांधा समां

पटना (एजेंसी) मैथिली ठाकुर ने नीदरलैंड्स में भारतीय लोकसंगीत और संस्कृति का सम्मान किया. इंडिया हाउस में आयोजित कॉन्सर्ट में विदेशी और भारतीय समुदाय ने मंत्रमुग्ध होकर सुना. बिहारी गर्व: लोक गायिका व दरभंगा के अलीनगर से बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने नीदरलैंड्स में आयोजित एक कॉन्सर्ट में भारतीय लोक संगीत और सांस्कृतिक परंपराओं की प्रस्तुति दी. नीदरलैंड्स स्थित इंडिया हाउस में आयोजित कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के साथ विदेशी अतिथियों ने भी हिस्सा लिया. कार्यक्रम में भारतीय लोक संगीत और सांस्कृतिक विरासत को केंद्र में रखा गया. इंडिया हाउस में राजदूत ने किया स्वागत कार्यक्रम से पहले नीदरलैंड्स में भारत के राजदूत कुमार तुहिन ने मैथिली ठाकुर का इंडिया हाउस में स्वागत किया. आयोजन के दौरान भारतीय लोक एवं सांस्कृतिक परंपराओं

से जुड़े संगीत की प्रस्तुति हुई. मैथिली ठाकुर ने कार्यक्रम के बाद राजदूत कुमार तुहिन के प्रति आभार जताया. उन्होंने आयोजन और आतिथ्य के लिए धन्यवाद दिया. उनके अनुसार, कॉन्सर्ट में व्यक्तिगत रूप से शामिल होने से लेकर पूरी टीम के साथ सहयोग तक राजदूत का व्यवहार उनके लिए विशेष अनुभव रहा. लोकगीतों से जुड़ा भारतीय समुदाय कॉन्सर्ट के दौरान मैथिली ठाकुर ने लोकगीतों और भारतीय संगीत की प्रस्तुति दी. कार्यक्रम में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों के साथ विदेशी अतिथियों ने भी संगीत का आनंद लिया. भारतीय लोक संगीत की प्रस्तुति के माध्यम से बिहार समेत देश की लोक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को विदेश में मौजूद दर्शकों के सामने रखा गया.

बिहार के दो जिले बनेंगे टेक्सटाइल हब, तैयार होगा उद्योगों का नेटवर्क, मिलेगा रोजगार

पटना (एजेंसी) बिहार को टेक्सटाइल हब बनाने के लिए सरकार तैयारियों में जुटी है. दो जिले मुजफ्फरपुर और भागलपुर को लेकर योजना बनाई गई है. इससे दोनों जिलों में उद्योगों का नेटवर्क तैयार हो सकेगा. साथ ही युवाओं को रोजगार मिल सकेगा. (पटना से अनुराग प्रधान की रिपोर्ट) : बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई पहल कर रही है. निवेश को बढ़ावा देने के लिए इंवेस्टर्स से जुड़ी कई योजनाएं लाईं जा रहीं हैं. ऐसे में राज्य के दो जिलों को टेक्सटाइल हब बनाने की तैयारी है. मुजफ्फरपुर और भागलपुर में उद्योगों को स्थापित किया जाएगा. इससे युवाओं के लिए उनके ही

जिले में रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे. दो जिलों में लगाए जायेंगे यूनिट्स मुजफ्फरपुर में लेदर, फुटवियर और टेक्सटाइल आधारित पार्क विकसित किया जा रहा है. जबकि भागलपुर सिल्क उद्योग को आधुनिक टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जोड़ रहा है. मुजफ्फरपुर के महबल में 62.17 एकड़ इलाके में मेगा लेदर और फुटवियर एक्सेसरीज पार्क विकसित किया जा रहा है. यहां बैग, फुटवियर, लेदर और टेक्सटाइल से जुड़े उत्पादन यूनिट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है. भागलपुर में बैग, फुटवियर और होजरी निर्माण जानकारी के मुताबिक, टेक्सटाइल पार्क में हाई स्पिरिट कमर्शियल वेंचर्स की 43 हजार वर्गफुट की मॉडर्न उत्पादन यूनिट शुरू की गई है. मुजफ्फरपुर के बेला इंडस्ट्रियल एरिया और महबल में इंडस्ट्रियल शेडों की संख्या बढ़ाई जा रही है. सिल्क सिटी के रूप में पहचान रखने वाला भागलपुर अब टेक्सटाइल के साथ बैग, फुटवियर और होजरी निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहा है. बिहार से जुड़ी अन्य ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें बढ़ेंगे रोजगार के अवसर इन परियोजनाओं का उद्देश्य केवल इंडस्ट्रियल यूनिट्स स्थापित करना नहीं बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार, कौशल विकास और सहायक उद्योगों का नेटवर्क तैयार करना भी है. मुजफ्फरपुर की भौगोलिक स्थिति और भागलपुर की पारंपरिक टेक्सटाइल पहचान को देखते हुए इन दोनों औद्योगिक केंद्रों से बिहार के साथ पड़ोसी राज्यों और नेपाल-भूटान जैसे बाजारों तक तैयार उत्पाद पहुंचाने की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं. गया के औद्योगिक क्लस्टर पर अपडेट गया

स्वस्तिक इंफ्रा का शेयर आठ फीसदी से अधिक बढ़कर बाजार में सूचीबद्ध

नई दिल्ली ।

स्वस्तिक इंफ्रा लिमिटेड का शेयर अपने 185 रुपये के निर्गम मूल्य के मुकाबले आठ प्रतिशत से अधिक की बढ़त के साथ बुधवार को बाजार में सूचीबद्ध हुआ। शेयर ने बीएसई और एनएसई दोनों पर 200 रुपये के भाव पर शुरुआत की, जो निर्गम मूल्य से 8.10 प्रतिशत अधिक है। इसके बाद बीएसई पर शेयर 13.48 प्रतिशत उछलकर 209.95 रुपये पर पहुंच गया, जो दिन की 'अपर सर्किट' सीमा है। एनएसई पर शेयर 13.51 प्रतिशत चढ़कर 210 रुपये पर पहुंच गया, जो दिन की अधिकतम कारोबार सीमा है। कंपनी का बाजार मूल्यांकन 716.35 करोड़ रुपये रहा। स्वस्तिक इंफ्रा के 161 करोड़ रुपये के आईपीओ को पिछले सप्ताह शुक्रवार को बोली के अंतिम दिन 7.60 गुना अभिदान मिला था। आईपीओ के लिए मूल्य दायरा 175-185 रुपये प्रति शेयर था।

एड्रोइट इंडस्ट्रीज के शेयर बाजार में 86.5 प्रतिशत उछलकर सूचीबद्ध

नई दिल्ली ।

एड्रोइट इंडस्ट्रीज के शेयर ने बुधवार को बाजार में मजबूत शुरुआत की और 134 रुपये के निर्गम मूल्य से 86.5 प्रतिशत उछलकर सूचीबद्ध हुआ।बीएसई पर शेयर 250 रुपये पर सूचीबद्ध हुआ, जो निर्गम मूल्य से 86.56 प्रतिशत अधिक है। एनएसई पर यह निर्गम मूल्य से 75.37 प्रतिशत की बढ़त के साथ 235 रुपये पर खुला। कंपनी का बाजार मूल्यांकन 1,112.82 करोड़ रुपये रहा। एड्रोइट इंडस्ट्रीज के 151 करोड़ रुपये के आईपीओ को शुक्रवार को बोली के अंतिम दिन 176.85 गुना अभिदान मिला था। आईपीओ के लिए मूल्य दायरा 126-134 रुपये प्रति शेयर था।वर्ष 1966 में स्थापित एड्रोइट इंडस्ट्रीज प्रोपेलर शाफ्ट (ड्राइव शाफ्ट/कार्डन शाफ्ट) और 'टॉर्क ट्रांसमिशन' से जुड़े कलपुर्जों की एकीकृत विनिर्माता एवं आपूर्तिकर्ता है। कंपनी फोर्जिंग, प्रिसिजन मशीनिंग, हीट ट्रीटमेंट, असेंबली, बैलेंसिंग और परीक्षण का काम भी खुद करती है।

सरकार ने अधिसूचित किए नए एएफई-3 मानदंड

यात्री वाहनों में बढ़ेगी ईंधन दक्षता, 1 अप्रैल 2027 से लागू होंगे नए नियम

नई दिल्ली ।

भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2027 से लागू होने वाले नए कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता (सीएएफई-3) मानदंडों को अधिसूचित किया है। इन नियमों का उद्देश्य यात्री वाहनों की ईंधन दक्षता में सुधार करना और कार्बन उत्सर्जन को कम करना है, जो 2032 तक कठोर लक्ष्य निर्धारित करेंगे। ये मानदंड हैचबैक, सेडान और एसयूवी सहित सभी यात्री कारों पर लागू होंगे। एक महत्वपूर्ण बदलाव के तहत, 909 किलोग्राम से कम वजन वाली पेट्रोल कारों के लिए प्रस्तावित रियायत हटा दी गई है। अब लक्ष्य रेखा को समतल किया गया है, जिससे हल्के वाहनों के लिए नरम और भारी वाहनों के लिए सख्त ईंधन दक्षता आवश्यकताएं होंगी। संदर्भ वजन को 1,082 किलोग्राम से बढ़ाकर 1,229 किलोग्राम किया गया है, जो बेड़े की बदलती विशेषताओं को दर्शाता है। यह ढांचा इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के लिए सुपर क्रेडिट की सुविधा देगा, जिससे निर्माताओं को स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। 2027-28 में 3.996 लीटर प्रति 100 किलोमीटर की ईंधन खपत को 2031-32 तक घटाकर 3.3273 लीटर प्रति 100 किलोमीटर करने का लक्ष्य है, जो 16.7 फीसदी सुधार दर्शाता है। नई क्रेडिट-डेबिट व्यवस्था भी निर्माताओं को लक्ष्यों को पूरा करने में लचीलापन प्रदान करेगी। ये मानदंड भारत की ऊर्जा सुरक्षा और टिकाऊपन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

आरमी इंफोटेक के शेयर की बाजार में कमजोर शुरुआत

नई दिल्ली (ईएमएस)। आरमी इंफोटेक लिमिटेड के शेयर बुधवार को निराशाजनक शुरुआत के साथ बाजार में सूचीबद्ध हुए। कंपनी का शेयर 375 रुपये के निर्गम मूल्य से करीब दो प्रतिशत की गिरावट के साथ खुला और कारोबार के अंत तक 16 प्रतिशत से अधिक टूट गया। बीएसई पर शेयर 368.85 रुपये पर सूचीबद्ध हुआ, जो निर्गम मूल्य से 1.64 प्रतिशत कम था। यह बाद में 15.76 प्रतिशत टूटकर 315.90 रुपये पर आ गया। वहीं, एनएसई पर शेयर 375 रुपये के निर्गम मूल्य पर सूचीबद्ध होने के बाद 16.29 प्रतिशत फिसलकर 313.80 रुपये पर बंद हुआ। इस गिरावट के बाद कंपनी का बाजार मूल्यांकन 1,002.71 करोड़ रुपये रहा। पिछले सप्ताह कंपनी के 300 करोड़ रुपये तक के आईपीओ को 2.44 गुना अभिदान मिला था। सरकारी विभागों और कॉर्पोरेट कंपनियों को विशेषकर आर्मी इंफोटेक कंप्यूटर, इंटरनेट और प्रौद्योगिकी से जुड़ी सेवाएं प्रदान करती है।

शेयर बाजार गिरावट पर बंद

सेंसेक्स 48, निफ्टी 95 अंक गिरा

मुम्बई ।

घरेलू शेयर बाजार बुधवार को हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ। बाजार में ये गिरावट दुनिया भर से मिले-जुले संकेतों के साथ ही बिकवाली हावी रहने से आई है। इसी कारण दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 48.78 अंक की गिरावट के साथ ही 72,480.29 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 95.75 अंक टूटकर 22,620.45 पर बंद हुआ। बाजार में आज अच्छी शुरुआत रही थी पर अंत में गिरावट से बाजार टूट गया। आज टीसीएस के शेयर ऊपर आये जबकि मिडकैप इंडेक्स में आरवीएनएल और प्रेस्टीज एस्टेट्स के शेयरों में तेजी रही। वहीं सबसे अधिक नुकसान वाले शेयरों में हेल्थकेयर और फार्मास्युटिकल क्षेत्र के शेयर रहे। निफ्टी के तहत अपोलो हॉस्पिटल्स, मैक्स हेल्थकेयर इंस्टीट्यूट और डॉ. रेड्डीज लेबोरेटरीज आज के सबसे अधिक नुकसान वाले शेयर रहे।

वहीं एशियाई बाजारों में मिला-जुला कारोबार दिखा। हैंगसेंग 0.53 फीसदी और शंघाई इंडेक्स 0.02 फीसदी गिरकर कारोबार करता नजर आया। वहीं निक्केई 1.20 फीसदी और कोस्पी 0.50 फीसदी की तेज के साथ कारोबार कर रहे थे। दूसरी ओर अमेरिकी बाजार भी मंगलवार को गिरावट के साथ बंद हुए। डाउ जोन्स 0.26 फीसदी, एसएंडपी 500 0.17 फीसदी और नैस्डैक 0.09 फीसदी नीचे रहा। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से भी बाजार में गिरावट हावी रही। ब्रेंट क्रूड 1.14 फीसदी चढ़कर 103 डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया।

विश्लेषकों का अनुमान है कि भारतीय इक्विटी बाजार अब कंसोलिडेशन के चरण में प्रवेश करेगा। यह छह महीने के निचले स्तर और लगातार आठवें साप्ताहिक नुकसान के बाद हो रहा है, जो 2020 के बाद की सबसे लंबी गिरावट का सिलसिला है। बाजार में विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली जारी है। यह बाजार की धारणा पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। कच्चे तेल की ऊंची कीमतें भी एक प्रमुख कारण हैं।

आरबीआई बढ़ा सकता है रेपो रेट, बैंक ऑफ अमेरिका का अनुमान

रेपो रेट में कुल 100 बेसिस पॉइंट तक की कर सकता है बढ़ोतरी

नई दिल्ली ।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) आने वाले महीनों में ब्याज दरें और बढ़ा सकता है। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज की नई रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई 2027 की पहली छमाही तक रेपो रेट में कुल 100 बेसिस पॉइंट यानी 1 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी कर सकता है। ब्रोकरेज ने अपनी पिछली भविष्यवाणी में पहली बढ़ोतरी का अनुमान दिसंबर से आगे बढ़ाकर अक्टूबर कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर की मौद्रिक नीति बैठक में रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की संभावना है। इसके बाद 75 बेसिस पॉइंट की और बढ़ोतरी हो सकती है। इस तरह रेपो रेट 6.25 फीसदी तक पहुंचने का अनुमान है। बैंक आफ अमेरिका ने पहले आरबीआई की ओर से कुल 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया था। अब ब्रोकरेज ने इसे दोगुना कर 100 बेसिस पॉइंट कर दिया है। हालांकि, यह एक ब्रोकरेज का अनुमान है और वास्तविक फैसला आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति के निर्णय पर निर्भर करेगा।अगर आर्थिक वृद्धि करीब 7 फीसदी बनी रहती है और महंगाई 5.5 फीसदी के आसपास रहती है, तो ब्याज दरों में 100 बेसिस पॉइंट से भी ज्यादा बढ़ोतरी की संभावना पर चर्चा हो सकती है। ऐसी स्थिति में कुछ फंट-एंड रेट 6.5 फीसदी से ऊपर जा सकते हैं।

भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर से होगा लागू

प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों, मसालों पर शुल्क होगा शून्य, ओशिनिया में मिलेगी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त

नई दिल्ली ।

भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) आगामी 20 अक्टूबर से प्रभावी होगा। यह समझौता घरेलू कृषि उत्पाद और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को मजबूत करेगा। व्यापार संवर्धन निकाय टीपीसीआई ने बुधवार को यह जानकारी दी, जिससे भारतीय निर्यातकों में नई उम्मीद जगी है। टीपीसीआई के अनुसार, समझौते के लागू होते ही प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, मसाले, सीजनिंग, कन्फेक्शनरी, बेकरी उत्पाद, पैकेटबंद अनाज, सॉस, फलों के रस और प्रसंस्कृत सब्जियों पर लगने वाला शुल्क 5 प्रतिशत से घटकर तत्काल शून्य हो जाएगा। यह भारतीय कृषि-खाद्य उत्पादों को न्यूजीलैंड के बाजार में अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बनाएगा। टीपीसीआई के एक अधिकारी ने बताया कि सभी उत्पाद श्रेणियों में 100 प्रतिशत शुल्क-मुक्त पहुंच सुनिश्चित होने से भारतीय निर्यातकों, विशेषकर खाद्य प्रसंस्करण और कपड़ा क्षेत्र को ओशिनिया (ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागर के द्वीपों का क्षेत्र) में अभूतपूर्व प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल होगी। परिषद सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों और कृषि-खाद्य कारोबारों को इन शुल्क रियायतों का लाभ उठाने, तकनीकी मानकों को पूरा करने और न्यूजीलैंड में खरीदारों से दीर्घकालिक संबंध बनाने में सहायता करेगी। सिंगला ने कहा कि शुल्क-मुक्त पहुंच भारत के मूल्यवर्धित कृषि उत्पादों के लिए हिंद-प्रशांत क्षेत्र की आपूर्ति श्रृंखलाओं में शामिल होने की महत्वपूर्ण संभावनाएं खोलेगी।

अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए टीपीसीआई निर्यातक जागरूकता सत्र और लक्षित खरीदार-विक्रेता बैठकें आयोजित करेगा।

टैक्स बचाने के लिए बिना बिल सोना खरीद रहे लोग, क्या है खतरा?

- बढ़ती कीमत और जीएसटी के बोझ से बचने ग्राहकों ने एक नया रास्ता चुना

नई दिल्ली ।

सोने की कीमतों में हालिया गिरावट के बावजूद पीली धातु अभी भी एक साल पहले के मुकाबले करीब 28 फीसदी अधिक महंगी है। इस बढ़ती कीमत और 3 फीसदी जीएसटी के बोझ से बचने के लिए ग्राहकों ने एक नया रास्ता अख्तियार किया है। कई ग्राहक बिना बिल के कैश में सोना खरीद रहे हैं, जहां उन्हें बाजार भाव से 6 फीसदी तक का आकर्षक डिस्काउंट मिल रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी मात्रा में सोना खरीदने पर अनौपचारिक कैश डील में ग्राहकों को बाजार भाव से लगभग 6 फीसदी तक की छूट मिल रही है, जो प्रति 10 ग्राम सोने पर 10,000 रुपए तक हो सकती है। कारोबार से जुड़े डीलरों के अनुसार टैक्स और अन्य लागत में होने वाली बचत का कुछ हिस्सा वे ग्राहक को डिस्काउंट के रूप में देते हैं। एक 55 वर्षीय महिला ने बताया कि बेटी की शादी के लिए ज्वेलरी खरीदते समय उन्हें प्रति 10 ग्राम सोने पर करीब 5,000 रुपए की छूट मिली, हालांकि इस सौदे में उन्हें कोई रसीद नहीं दी गई।

भारत में खुदरा ग्राहकों को सोने की खरीद पर 3 फीसदी जीएसटी और आयात शुल्क देना होता है, जिससे आधिकारिक चैनल से मिलने वाले सोने की कीमत बढ़ जाती है। इसी अतिरिक्त लागत से बचने के लिए कुछ खरीदार कैश और बिना बिल वाली खरीदारी की ओर रुख कर रहे हैं। बाजार से जुड़े लोग दावा करते हैं कि अनौपचारिक कैश

मार्केट में सोना घरेलू बाजार की कीमत से करीब 200 डॉलर प्रति औंस तक कम मिल सकता है, हालांकि यह छूट ग्राहक और डीलर के बीच बातचीत पर निर्भर करती है।

भारत दुनिया के सबसे बड़े सोना उपभोक्ताओं में से एक है, जहां शादियों, त्योहारों और पारिवारिक बचत के लिए सोने की मांग काफी मजबूत रहती है। हालांकि, कम कीमत के लालच में बिना बिल सोना खरीदना जोखिम भरा हो सकता है। बिना रसीद के खरीदारी होने पर सोने की शुद्धता, स्वामित्व, दोबारा बिक्री और टैक्स से जुड़े मामलों में कोई औपचारिक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं रहता। ऐसे में शुरुआती डिस्काउंट के साथ-साथ ऐसी खरीदारी के संभावित जोखिमों को भी ध्यान में रखना ग्राहकों के लिए बेहद जरूरी है।

रिटायरमेंट प्लानिंग में इक्विटी से कब और कैसे करें डी-रिस्किंग?

रिटायरमेंट से 5 से 10 साल पहले शुरू करें इक्विटी घटाना

नई दिल्ली ।

रिटायरमेंट की तैयारी केवल एक बड़ा फंड बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि जमा पूंजी को बाजार के उतार-चढ़ाव से बचाने की रणनीति बनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक्सपर्ट्स इस बात पर सहमत हैं कि रिटायरमेंट से पहले इक्विटी निवेश को धीरे-धीरे कम जोखिम वाले विकल्पों की ओर मोड़ना एक बेहतर रणनीति है। विशेषज्ञों के मुताबिक रिटायरमेंट के दिन अचानक इक्विटी से सारा पैसा निकालने के बजाय, पोर्टफोलियो को चरणबद्ध तरीके से डी-रिस्क करना चाहिए। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि रिटायरमेंट से करीब 7 से 10 साल पहले इक्विटी से जोखिम कम करने की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। इससे निवेशक को एक साथ बड़ा बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि, वह 100 माइनस एज जैसे नियमों को केवल शुरुआती संकेत मानते हैं, कोई तय फॉर्मूला नहीं। वहीं व्यावहारिक तौर पर रिटायरमेंट से लगभग 5 साल पहले इक्विटी एक्सपोजर कम करना शुरू किया जा सकता है। इस दौरान निवेश का फोकस पैसा बढ़ाने से बदलकर पूंजी को सुरक्षित रखने और नियमित आय सुनिश्चित करने पर केंद्रित हो जाता है। हालांकि, यह 5 साल का नियम भी हर निवेशक के लिए समान नहीं है और यह रिटायरमेंट कॉर्पस, आय आवश्यकताओं, जोखिम सहनशीलता और अन्य वित्तीय परिस्थितियों के आधार पर भिन्न हो सकता है। रिटायरमेंट के बाद इक्विटी में कितना निवेश रखना चाहिए, इस पर भी अलग-अलग राय है। विशेषज्ञों के अनुसार रिटायरमेंट के बाद निवेशक अपने कुल फंड का 30-40 फीसदी इक्विटी और 60-70 फीसदी डेट व फिक्स्ड इनकम में रख सकते हैं। एक अन्य विशेषज्ञ की सलाह है कि 52 साल की उम्र तक इक्विटी की हिस्सेदारी घटाकर करीब 50 फीसदी और रिटायरमेंट तक इसे 20-25 फीसदी (मुख्य रूप से लार्ज कैप फंड में) किया जा सकता है।

चीन में विनिर्माण गतिविधियां बढ़ीं, अर्थव्यवस्था को मिला सहारा

हांगकांग ।

चीन की विनिर्माण गतिविधियां सितंबर में तीन महीने के बाद विस्तार के दौर में लौट आई हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार विनिर्माण खरीद प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) अगस्त के 49.8 से बढ़कर सितंबर में 50.1 हो गया, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संकेत है। पीएमआई का यह स्तर अर्थशास्त्रियों के अनुमानों के अनुरूप रहा।

50 से ऊपर का स्तर विस्तार और 50 से नीचे का स्तर संकुचन दर्शाता है। उत्पादन संबंधी उप-सूचकांक बढ़कर 51.7 हो गया, जो मजबूत वृद्धि का संकेत है। हालांकि, नए ऑर्डर और नए निर्यात ऑर्डर के उप-सूचकांक क्रमशः 50.5 और 50.0 पर लगभग स्थिर रहे। यह सुधार ऐसे समय में आया है जब चीन अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए संघर्ष कर रहा है, जिसे कमजोर घरेलू मांग और संपत्ति क्षेत्र की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कृत्रिम मेधा (एआई) के कारण उच्च-प्रौद्योगिकी निर्यात में तेजी ने भी विनिर्माण क्षेत्र को बल दिया है।

विशेषज्ञों के अनुसार, विनिर्माण की मजबूती बाहरी मांग पर अधिक निर्भर है।

एआई से बने विज्ञापनों पर एएससीआई सख्त, अब लेबल लगाना जरूरी

- उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए पारदर्शिता पर जोर

नई दिल्ली।

ब्रांड्स द्वारा विज्ञापनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के बढ़ते उपयोग को देखते हुए, एडवरटाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया (एएससीआई) ने उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनका लक्ष्य ग्राहकों को भ्रमित होने से बचाना और विज्ञापनों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। ये नए नियम जारी होने की तारीख से तीन महीने बाद लागू होंगे। एएससीआई के अनुसार सिंथेटिक कंटेंट (एसजीसी) तब भ्रामक या नुकसानदेह हो सकता है, जब यह झूठी उम्मीदें जगाए, कमजोर वर्गों का अनुचित फायदा उठाए, या गलत और भ्रामक जानकारी पेश करे। परिषद ने कुछ विज्ञापनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है, जिनमें गैर-कानूनी सामग्री, अधिकारों का उल्लंघन, भ्रामक दावे, सिंथेटिक फोटो-वीडियो के जरिए उत्पादों के परिणामों को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाना, नकली जगहों को असली बताना और बिना अनुमति के डीपफेक का इस्तेमाल शामिल है।

एएससीआई की एक अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि केवल एआई का लेबल लगा देने से कोई भ्रामक विज्ञापन सही नहीं हो जाता, और विज्ञापनदाता की जिम्मेदारी होगी कि जानकारी सही और साफ हो।

नए दिशानिर्देशों के तहत, एआई या सिंथेटिक कंटेंट के इस्तेमाल पर लेबल लगाना अनिवार्य होगा जब यह ग्राहकों के निर्णयों को सीधे प्रभावित करे, वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स या ब्रांड एंबेसडर का उपयोग हो, या काल्पनिक घटनाओं व माहौल को दर्शाया जाए जो उत्पाद या सेवा की ग्राहक समझ को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा, एआई द्वारा दिए जाने वाले पेड या स्पॉन्सर्ड सुझावों पर भी साफ लेबलिंग आवश्यक होगी।

हालांकि, सामान्य एडिटिंग (जैसे कलर करेक्शन), सजावटी/फंतासी आधारित बैकग्राउंड या प्रशासनिक कार्यों (जैसे विज्ञापन टेक्स्ट लिखना) के लिए लेबलिंग की आवश्यकता नहीं होगी।

जेएसडब्ल्यू सीमेंट का शिवा सीमेंट में विलय, एकीकृत मंच बनाने का लक्ष्य

बोर्ड ने दी मंजूरी; परिचालन, वित्तीय एवं प्रबंधन स्तर पर तालमेल से दक्षता बढ़ाने पर जोर

-नई दिल्ली ।

सज्जन जिंदल के नेतृत्व वाले जेएसडब्ल्यू समूह की कंपनी जेएसडब्ल्यू सीमेंट लिमिटेड अपनी सूचीबद्ध अनुषंगी शिवा सीमेंट में विलय करने जा रही है। मंगलवार देर रात कंपनी ने शेयर बाजार को सूचित किया कि उसके निदेशक मंडल ने इस व्यवस्था योजना को मंजूरी दे दी है। इस कदम का उद्देश्य एक एकीकृत सीमेंट मंच तैयार करना और परिचालन, वित्तीय तथा प्रबंधन स्तर पर व्यापक तालमेल का लाभ उठाना है। जेएसडब्ल्यू सीमेंट के निदेशक मंडल ने शिवा सीमेंट के जेएसडब्ल्यू सीमेंट में विलय को स्वीकृति प्रदान की है। इस योजना के तहत शिवा सीमेंट के शेयरधारकों को उनके प्रत्येक 41 रुपये अंकित मूल्य के दो रुपये वाले शेयर के बदले जेएसडब्ल्यू सीमेंट के 10 रुपये अंकित मूल्य वाले पांच शेयर जारी किए जाएंगे। यह विलय विभिन्न नियामक प्राधिकरणों, जैसे सेबी, एनसीएलटी, शेयर बाजारों और संबंधित सरकारी निकायों की अनिवार्य मंजूरियों पर निर्भर करेगा। कंपनी को उम्मीद है कि आवश्यक मंजूरियां समय पर मिलने की स्थिति में यह लेनदेन अगले 12-14 महीनों में पूरा हो जाएगा। जेएसडब्ल्यू सीमेंट ने बताया कि विलय से वित्तीय, प्रबंधकीय, तकनीकी, वितरण और विपणन संसाधनों का एकीकरण होगा, जिससे समग्र परिचालन दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इससे शिवा सीमेंट की 'क्लिंकर' इकाई के माध्यम से पिछड़े एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा, जिससे बाहरी खरीद पर निर्भरता कम होगी। 'क्लिंकर' सीमेंट बनाने का एक प्रमुख मध्यवर्ती पदार्थ है। वित्तीय स्तर पर, कंपनी को बेहतर वित्तपोषण सुविधा, कम वित्तपोषण लागत और अंतर-कंपनी गारंटी खत्म होने से लाभ मिलेगा। साथ ही, प्रशासनिक कार्यों की दोहराव और अनुपालन संबंधी जरूरतें भी कम होंगी। जेएसडब्ल्यू सीमेंट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह विलय अधिक एकीकृत और कुशल व्यवसाय बनाने की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। इससे परिचालन और वित्तीय तालमेल बढ़ेगा, तथा शिवा सीमेंट के सार्वजनिक शेयरधारकों को एक बड़ी सूचीबद्ध कंपनी की वृद्धि में सीधे भाग लेने का अवसर मिलेगा।

सरकारी कोशिशें बेअसर, खुदरा बाजार में प्याज 60 के पार

- बफर स्टॉक से बिक्री और कांदा एक्सप्रेस भी बेअसर

नई दिल्ली । केंद्र सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद खुदरा बाजार में प्याज की कीमतें 60 रुपये प्रति किलोग्राम से ऊपर बनी हुई हैं, जिससे आम जनता को राहत नहीं मिल पा रही है। सरकार ने बफर स्टॉक से 35 रुपये प्रति किलो की रियायती दर पर प्याज बाजार में उतारा और कांदा एक्सप्रेस भी चलाई, लेकिन मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे बड़े शहरों में दाम अभी भी ऊंचे बने हुए हैं। केंद्र सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद खुदरा बाजार में प्याज की कीमतें 60 रुपये प्रति किलोग्राम से ऊपर बनी हुई हैं, जिससे आम जनता को राहत नहीं मिल पा रही है। सरकार ने बफर स्टॉक से 35 रुपये प्रति किलो की रियायती दर पर प्याज बाजार में उतारा और देश में इसकी सप्लाई बेहतर करने के लिए 'कांदा एक्सप्रेस' भी शुरू की। हालांकि, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के मुताबिक, देश में प्याज की औसत खुदरा कीमत 54 रुपये प्रति किलोग्राम है, लेकिन मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे बड़े शहरों में यह 60 रुपये प्रति किलो या उससे भी अधिक पर बिक रहा है। देश की सबसे बड़ी थोक प्याज मंडी लासलगांव में पिछले एक महीने में अच्छी गुणवत्ता वाले प्याज के दाम करीब 23 प्रतिशत बढ़कर 5,160 रुपये प्रति क्विंटल पहुंच गए हैं। इस मूल्यवृद्धि का मुख्य कारण महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे प्रमुख उत्पादक राज्यों में असमय हुई भारी बारिश से फसल को हुआ भारी नुकसान है, जिससे दूसरी फसल की आवक में देरी हुई है। प्याज कारोबारियों का अनुमान है कि नई फसल की आवक अक्टूबर के आखिरी हफ्ते या नवंबर की शुरुआत में शुरू हो सकती है। मंडियों में प्याज की सप्लाई बढ़ने के साथ ही कीमतों में गिरावट आने की उम्मीद है, तब तक उपभोक्ताओं को महंगे प्याज से जूझना पड़ सकता है।

पेज एक का शेष

चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्षी दल....

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि पूरा विपक्ष एकजुट है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कई राज्यों में 'वोट चोरी' कर चुनाव जीते हैं और चुनाव आयोग तथा शीर्ष न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के बावजूद विपक्ष की शिकायतों का समाधान नहीं हुआ। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के तत्काल इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि यदि उन्हें पद से नहीं हटाया गया तो आंदोलन और आगे बढ़ाया जाएगा।

उन्होंने पश्चिम बंगाल में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) को लेकर भी आरोप लगाये। श्री गांधी ने कहा कि 'वोट चोरी' के मुद्दे पर सभी विपक्षी दलों की राय एक जैसी है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, श्री शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला किया है। श्री गांधी ने कहा कि लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जाएगी। इंडिया गठबंधन एकजुट होकर संविधान की रक्षा की लड़ाई लड़ेगा।

गठबंधन की बैठक में श्री खरगे के अलावा कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की महबूबा मुफ्ती, पूर्व केन्द्रीय मंत्री कपिल सिब्बल, समाजवादी पार्टी के सांसद हरेन्द्र सिंह मलिक और मोहिबुल्ला नदवी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) की सुप्रिया सुले और जितेंद्र आव्हाड, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव एम ए बेबी तथा सांसद जॉन ब्रिटास, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव और आरएसपी के एन.के. प्रेमचंद्रन तथा कुछ अन्य दलों के नेता मौजूद थे।

शिवसेना (यूबीटी) अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने ऑनलाइन माध्यम से बैठक में अपनी बात रखी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव बैठक में मौजूद नहीं थे। बताया गया कि वह लखनऊ में पार्टी के कार्यों में व्यस्त होने के कारण नहीं आ पाये। आम आदमी पार्टी तथा द्रविड़ मुनेत्र कषगम ने पहले ही बैठक में शामिल नहीं होने कि घोषणा कर दी थी।

उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय में राजभाषा पखवाड़ा समारोह संपन्नः महाप्रबंधक ने विजेताओं को किया पुरस्कृत, हिंदी को बताया सांस्कृतिक धरोहर

बिहान भारत

प्रयागराज : उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय में महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह द्वारा दीप प्रज्वलन और माँ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ 'राजभाषा पखवाड़ा' के मुख्य समारोह एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का भव्य उद्घाटन किया गया।

समारोह को संबोधित करते हुए महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर, राष्ट्रीय मूल्यों और विविधता में एकता का प्रतीक है। आज के तकनीकी युग में हिंदी संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के हर माध्यम में वैश्विक स्तर पर स्थापित हो चुकी है। उन्होंने प्रयागराज को साहित्य और संस्कृति की राजधानी बताते हुए सभी अधिकारियों व कर्मचारियों से अपने दैनिक शासकीय कार्यों में अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग करने का आह्वान किया।

मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं प्रधान मुख्य यांत्रिक इंजीनियर अनिल कुमार द्विवेदी ने कहा कि भारतीय रेल की तरह ही हिंदी भी विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं को एक सूत्र में पिरोती है। उन्होंने बताया कि मुख्यालय में कंप्यूटरों पर हिंदी टाइपिंग कार्यशालाएं, साहित्यिक गोष्ठियां और प्रतियोगिताएं निरंतर आयोजित की जा रही हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास), प्रयागराज द्वारा 'चल वैजयंती' का द्वितीय पुरस्कार मिला है।

समारोह में सांस्कृतिक टीम द्वारा सरस्वती वंदना और 'संत कबीर का ताना-बाना' नृत्य नाटिका की मनमोहक प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर आयोजित भव्य राजभाषा प्रदर्शनी में वैगन मरम्मत कारखाना, झाँसी को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनी शील्ड प्रदान की गई, जबकि सिग्नल एवं दूरसंचार विभाग को द्वितीय और रेल सुरक्षा बल को तृतीय स्थान मिला। इसके अलावा विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं और हिंदी में सराहनीय कार्य करने वाले 89 अधिकारियों व कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया।

कार्यक्रम में अपर महाप्रबंधक राजकुमार वानखेड़े सहित सभी विभागों के विभागाध्यक्ष, वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। मंच संचालन वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी यथार्थ पाण्डेय ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन उप मुख्य राजभाषा अधिकारी डॉ. गरिमा त्रिपाठी द्वारा किया गया।

सेल सैटेलाइट टाउनशिप में 'स्वच्छता ही सेवा' अभियानः सफाई मित्र हुए सम्मानित

बिभा संवाददाता

रांची : स्वच्छता में सहभाग; स्वच्छ भारत, विकसित भारत‡ थीम के तहत आयोजित 'स्वच्छता ही सेवा 6.0-2026' पखवाड़े के अंतर्गत 30 सितंबर को सेल सैटेलाइट टाउनशिप, रांची स्थित आईईएच में विशेष सफाई अभियान चलाया गया।

अभियान की शुरूआत स्वच्छता शपथ के साथ हुई, जिसके बाद अधिकारियों और कर्मचारियों ने आईईएच परिसर तथा आसपास के क्षेत्रों में श्रमदान कर सफाई की। इस दौरान सामुदायिक भागीदारी और सामूहिक जिम्मेदारी का संदेश दिया गया। कार्यक्रम का सफल समन्वय सीईटी के एजीएम (एचआर) सुरजीत सिंह और एस. के. मेहेर ने किया। कार्यक्रम के समापन पर परिसर को स्वच्छ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाने वाले सफाई मित्रों और स्वच्छता कर्मियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सीईटी के ईडी एस. सुब्बाराज, आरबीयू के सीजीएम (एचआर) समरजीत जचक, सीईटी के सीजीएम सहित बड़ी संख्या में अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

पीवीयूएनएल में स्वास्थ्य जागरूकता पर विशेष वार्ता का आयोजन

स्वस्थ जीवनशैली ही स्वस्थ जीवन की आधारशिला : अरुण ऋषि स्वर्गीय

बिभा संवाददाता

पतरातूः पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (पीवीयूएनएल) द्वारा कर्मचारियों एवं उनके परिवारजनों के बीच स्वास्थ्य एवं स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से अरन्या भवन में एक विशेष स्वास्थ्य जागरूकता वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्री अरुण ऋषि स्वर्गीय ने स्वास्थ्य, शरीर के महत्व तथा दैनिक जीवन में अपनाई जाने वाली स्वस्थ आदतों के संबंध में विस्तार से जानकारी साझा की।

कार्यक्रम में पीवीयूएनएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ए.के. सहगल, स्वर्णरेखा महिला समिति की अध्यक्ष रेनू सहगल, जीएम (प्रोजेक्ट) बिष्णु दत्ता दाश, जीएम (एफएम) प्रशांत पाटिल, जीएम (ऑपरेशन) अरुण कुमार सिंह, जीएम (कमिशनिंग) आर.के. निरंजन सहित पीवीयूएनएल के कर्मचारी एवं उनके परिवारजन उपस्थित रहे।

अपने संबोधन में अरुण ऋषि स्वर्गीय ने कहा कि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ जीवन के लिए दैनिक जीवनशैली में छोटे-छोटे सकारात्मक बदलाव महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने शरीर की कार्यप्रणाली को समझने, नियमित दिनचर्या अपनाने तथा स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने पर जोर दिया।

वार्ता के दौरान उन्होंने एक्यूप्रेशर के विभिन्न बिंदुओं, भोजन एवं दिनचर्या से संबंधित आदतों तथा शारीरिक गतिविधियों के महत्व के बारे में जानकारी दी। नियमित रूप से पैदल चलने तथा नंगे पैर चलने जैसी गतिविधियों के संबंध में अपने अनुभव और सुझाव साझा किए। इसके अलावा, उन्होंने स्वस्थ जीवनशैली के लिए विभिन्न सरल तकनीकों एवं दैनिक अभ्यासों के बारे में भी बताया, जिन्हें व्यक्ति अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकता है।

कार्यक्रम के दौरान कर्मचारियों एवं उनके परिजनों ने स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न पहलुओं को ध्यानपूर्वक सुना और वक्ता द्वारा बताए गए सरल उपायों एवं तकनीकों के बारे में जानकारी प्राप्त की। वार्ता का उद्देश्य स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ कर्मचारियों और उनके परिवारों को अपनी दैनिक जीवनशैली में सकारात्मक एवं स्वस्थ आदतों को अपनाने के लिए प्रेरित करना रहा।

कार्यक्रम का समापन स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने तथा स्वस्थ एवं संतुलित जीवनशैली अपनाने के संदेश के साथ हुआ।

संक्षिप्त खबरें

दिवंगत प्रवासी श्रमिक के आश्रित पिता को उपायुक्त ने सौंपा 50 हजार का चेक

देवघर(बिभा) : देवघर समाहरणालय सभागार में बुधवार को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार भुवानिया ने दिवंगत प्रवासी मजदूर सुरेंद्र टुडू के आश्रित पिता चुड़का टुडू से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार को 'मुख्यमंत्री झारखण्ड प्रवासी श्रमिक दुर्घटना कोष' के तहत 50,000 रुपये का सहायता चेक सौंपा। इसके साथ ही उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि परिवार को अविलंब आवास योजना और सामाजिक सुरक्षा के तहत मिलने वाले पारिवारिक लाभ सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं से तत्काल जोड़ा जाए। जानकारी के अनुसार, सुरेंद्र टुडू मुंबई से जसीडीह लौट रहे थे, तभी मध्य प्रदेश के बुरहानपुर और खंडवा के बीच अचानक तबीयत बिगड़ने से उनका निधन हो गया। देवघर जिला प्रशासन के सहयोग और समन्वय से उनके पार्थिव शरीर को मध्य प्रदेश से उनके पैतृक गांव लाया जा रहा है। उपायुक्त ने जिले के सभी प्रवासी श्रमिकों से अपील की कि वे झारखण्ड सरकार के 'श्रमाधान पोर्टल' पर अपना निबंधन अवश्य कराएं, ताकि संकट के समय आश्रितों को सरकारी योजनाओं का त्वरित लाभ मिल सके। बैठक में डीडीसी पीयूष सिन्हा और श्रम अधीक्षक शैलेंद्र कुमार शाह सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे।

डीएसपीएमयू में ए मैनेजर्स गाइड टू कंप्यूटिंग प्रिंसिपल्स पुस्तक का कुलपति ने किया लोकार्पण

रांची(बिभा) : डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, रांची में आधुनिक तकनीकी प्रणालियों, सॉफ्टवेयर सिद्धांतों और डेटा प्रबंधन पर केंद्रित पुस्तक ए मैनेजर्स गाइड टू कंप्यूटिंग प्रिंसिपल्स का औपचारिक विमोचन किया गया। पुस्तक का लोकार्पण विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. (डॉ.) राजीव मनोहर के कर-कमलों द्वारा संपन्न हुआ। यह संपादित पुस्तक आधुनिक संगठनों व उच्च शिक्षण संस्थानों में कंप्यूटिंग सिद्धांतों, डेटा प्रबंधन और तकनीकी स्वचालन की भूमिका को रेखांकित करती है। पुस्तक के मुख्य संपादक डॉ. राहुल देव साह हैं। इसमें डॉ. राजेंद्र कुमार महतो, डॉ. राहुल देव साह, डॉ. राजाराम दत्ता, डॉ. आशीष गुप्ता, डॉ. राजू मांझी, डॉ. महापात्रा, खुशबु कुमारी, उर्मिला कुमारी, ममता कुमारी सहित विभिन्न संस्थानों के शिक्षाविदों व शोधकताओं ने अपने अध्यायों के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस अवसर पर विज्ञान संकायाध्यक्ष डॉ. नमिता सिंह, डॉ. अभय कृष्ण सिंह और डॉ. अनुपम कुमार विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित शिक्षकों व अतिथियों ने संपादक मंडल एवं सभी सह-लेखकों को इस शैक्षणिक उपलब्धि पर बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय धनबाद में समापक भुगतान समारोह का किया गया आयोजन

धनबाद(बिभा): धनबाद मंडल में सितम्बर माह 2026 में सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों का समापक भुगतान किया गया। इस माह में कुल 21 सेवानिवृत्ति के मामले आए थे, जिनमें सभी कर्मचारियों का समापक भुगतान कर दिया गया है` विदित हो कि धनबाद मंडल में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के समापक भुगतान को प्राथमिकता दी जाती है` मंडल प्रशासन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है` उल्लेखनीय है कि धनबाद मंडल में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के समापक भुगतान की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। मंडल प्रशासन सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। इस अवसर पर अपर मंडल रेल प्रबंधक(इन्फ्रा) संतोष कुमार द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सम्मानित किया गया एवं उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दिया गया` उन्होंने उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दीं। इस अवसर पर मंडल के अन्य अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं यूनियन तथा एसोसिएशन के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे।

एसआईआर की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने की समीक्षा, अनाथालय व वृद्धाश्रम का भी लिया जायजा

बिभा संवाददाता

गिरिडीह : समाहरणालय सभागार में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार की अध्यक्षता में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर-2026) को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विधानसभा क्षेत्रवार फॉर्म-6, 6ए, 7 और 8 के आवेदनों, उनके सत्यापन, लंबित मामलों और नोटिस सुनवाई की विस्तृत समीक्षा की गई। बताया गया कि 5 अगस्त से 29 सितंबर 2026 तक जिले में फॉर्म-6 के 49,612, फॉर्म-7 के 569 तथा फॉर्म-8 के 55,626 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि आवेदनों के सत्यापन और नोटिस सुनवाई में निर्वाचन आयोग के नियमों का पूरी पारदर्शिता से पालन किया जाए, ताकि किसी भी पात्र मतदाता को असुविधा न हो। उन्होंने 30 सितंबर की अंतिम तिथि के आलोक में सभी प्रक्रियाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा कर मतदाता सूची को शुद्ध, त्रुटिरहित और अद्यतन बनाने पर जोर दिया। बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त रामनिवास यादव सहित सभी प्रशासनिक और निर्वाचन पदाधिकारी उपस्थित थे।

समीक्षा बैठक के बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने ईसाई मिशनरी द्वारा संचालित अनाथालय 'प्रेमदान' तथा शहर स्थित वृद्धाश्रम का दौरा किया। प्रेमदान में उन्होंने महिलाओं और सेविकाओं से मतदाता सूची संबंधी प्रक्रियाओं की जानकारी ली और बच्चों के आवश्यक दस्तावेज नियमानुसार तैयार कराने के निर्देश दिए। वहीं वृद्धाश्रम में बुजुर्गों से संवाद के दौरान दस्तावेज छूट जाने की समस्या सामने आने पर उन्होंने अधिकारियों को विशेष शिविर आयोजित कर वृद्धजनों के नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने और पहचान संबंधी प्रक्रियाएं पूरी कराने का निर्देश दिया।

धनबाद मंडल में सफाई मित्र सुरक्षा शिविर का आयोजन

धनबाद(बिभा): स्वच्छता ही सेवा अभियान के चौदहवें दिन धनबाद रेल मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर सफाई मित्र सुरक्षा शिविर का आयोजन किया गया` इस अवसर पर रेलवे चिकित्सा टीम द्वारा विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाकर सफाई मित्रों के रक्तचाप, ब्लड शुगर एवं सामान्य स्वास्थ्य की जांच की गई तथा आवश्यक दवाओं का वितरण किया गया` साथ ही, सफाई मित्रों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा एवं बीमा योजनाओं की जानकारी देकर उनके लाभ के प्रति जागरूक किया गया। इस पहल का उद्देश्य सफाई मित्रों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उनके कल्याण और सम्मान की भावना को सुदृढ़ करना है।

सिल्ली में सड़क हादसे रोकने के लिए पुलिस सतर्क, खतरनाक स्थलों पर लगाए जा रहे चेतावनी बोर्ड

सिल्ली(बिभा): सिल्ली एवं आसपास के क्षेत्र में आए दिन हो रहे सड़क दुर्घटना से निपटने के लिए पुलिस की तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं। लगातार हुई सड़क दुर्घटना को देखते हुए सड़कों पर संभावित खतरनाक स्थलों को चयनित कर चेतावनी बोर्ड लगाए जा रहे हैं। लगातार हो रही दुर्घटना को लेकर सिल्ली थाना प्रभारी नवीन कुमार ने उच्च अधिकारियों से पत्राचार कर इस दिशा पर आवश्यक कदम उठाने की अपील की थी। थाना प्रभारी नवीन कुमार ने बताया कि सड़क दुर्घटना रोकने के लिए पुलिस अपने संसाधनों के माध्यम से सभी प्रयास कर रही है। सड़कों पर खतरनाक स्थलों पर चेतावनी बोर्ड के सिल्ली टीकर रंगामाटी सड़क पर लगाया गया है। इनके अलावा अन्य ग्रामीण सड़कों में भी इस तरह के बोर्ड लगाए जाएंगे। वहीं वाहन चालकों को सड़कों पर गति नियंत्रण रखने और सावधानी बरतने के भी निर्देश दिए जा रहे हैं। साथ ही ग्रामीणों को जागरूक करने प्रयास किया जा रहा है। जिससे आए दिन हो रहे दुर्घटना से बचा जा सके। बहुत जल्द चिन्हित स्थानों पर ब्रेकर भी लगाई जाएगी।

'स्वच्छता ही सेवा 2026': पूर्व रेलवे के चारों मंडलों में सफाई मित्रों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के लिए विशेष अभियान

बिहान भारत

कोलकाता : पूर्व रेलवे की महाप्रबंधक गीतिका पाण्डेय के नेतृत्व में पूर्व रेलवे के चारों मंडलों–आसनसोल, हावड़ा, सियालदह और मालदा–में 'स्वच्छता ही सेवा 2026' अभियान के तहत सफाई मित्रों और हाउसकीपिंग कर्मचारियों के कल्याण, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके तहत व्यापक स्वास्थ्य जांच, सुरक्षा उपकरण (पीपीई) किट वितरण और पर्यावरण स्वच्छता से जुड़ी गतिविधियां चलाई गईं।

आसनसोल मंडल में मंडल रेल अस्पताल सहित सीतारामपुर, पानागढ़ और अंडाल में स्वास्थ्य शिविर लगाकर कर्मचारियों के बीएमआई, शुगर व बीपी की जांच की गई और जीवनशैली परामर्श दिया गया। साथ ही जसीडीह, दुगार्पुर, चित्तरंजन, रानीगंज व मधुपुर में सुरक्षा किट बांटी गईं। हावड़ा मंडल में स्वास्थ्य शिविरों के अलावा टी-शर्ट वितरण, प्लास्टिक संग्रहण, सिंगल-यूज प्लास्टिक के खिलाफ जागरूकता और सौंदर्यीकरण अभियान चलाए गए।

सियालदह मंडल में सफाई कर्मियों और उनके परिजनों के लिए सिंगल-विंडो स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए। साथ ही उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत (पीएम-जय), सुरक्षा बीमा और जन धन योजना जैसी प्रमुख केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया। मालदा मंडल में मालदा अस्पताल, साहिबगंज, जमालपुर और भागलपुर हेल्थ यूनिट में सुरक्षा एवं सम्मान शिविर के तहत स्वास्थ्य जांच की गई। पूर्व रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिबराम माझि ने कहा कि रेलवे अपने फ्रंटलाइन कर्मियों के स्वास्थ्य, गरिमा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए स्वच्छ और हरित वातावरण के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है।

सफाई मित्र सुरक्षा सेवा एवं सम्मान शिविर के साथ खड़गपुर मंडल ने स्वच्छता ही सेवा अभियान को दी गति

बिहान भारत

खड़गपुरः स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 के तहत खड़गपुर मंडल ने स्वच्छता, साफ-सफाई एवं सफाई कर्मचारियों के कल्याण पर केंद्रित विभिन्न गतिविधियों की श्रृंखला को जारी रखा।

30 सितंबर को मंडल द्वारा खड़गपुर, बालेश्वर, संतरागाछी तथा अन्य प्रमुख स्थानों पर सफाई मित्र सुरक्षा सेवा एवं सम्मान शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों में रेलवे की स्वच्छता गतिविधियों से जुड़े सफाई मित्रों के स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया।

इस पहल के अंतर्गत सफाई मित्रों के लिए सिंगल-विंडो स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए गए। इनमें संविदा पर कार्यरत स्वच्छता एवं OBHS कर्मचारी, ट्रैक किनारे सफाई कर्मचारी तथा रेलवे कॉलोनियों में कार्यरत स्वच्छता कर्मी शामिल थे। स्वास्थ्य जांच की इस पहल के अंतर्गत उनके आश्रितों को भी शामिल किया गया। मंडल द्वारा सफाई मित्रों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (ढढए) किट एवं सुरक्षा सामग्री का वितरण भी किया गया। इसका उद्देश्य कार्य के दौरान व्यावसायिक सुरक्षा के महत्व को रेखांकित करना तथा सफाई कर्मियों को आवश्यक सुरक्षात्मक उपकरण उपलब्ध कराना था।

इसके अलावा, पात्र सफाई मित्रों को विभिन्न सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने की दिशा में भी प्रयास किए गए। अभियान के तहत स्टेशनों एवं रेलवे कॉलोनियों में सफाई मित्रों और स्वच्छाग्रहियों को उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मानित एवं अभिनंदित किया गया। रेलवे परिसरों में स्वच्छता एवं साफ-सफाई बनाए रखने में उनके योगदान को इस अवसर पर विशेष रूप से रेखांकित किया गया।

इन पहलों के माध्यम से खड़गपुर मंडल ने रेलवे परिसरों को स्वच्छ एवं स्वच्छतापूर्ण बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सफाई मित्रों के कल्याण, गरिमा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।

स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत खड़गपुर मंडल कल, 01 अक्टूबर 2026 को राष्ट्रव्यापी सामूहिक श्रमदान ह्लएक दिन, एक घंटा, एक साथह्व में भी भाग लेगा। खड़गपुर के लोकल मार्केट, गोल बाजार में श्रमदान का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही मंडल के अन्य प्रमुख रेलवे स्टेशनों एवं रेलवे कॉलोनियों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें रेलवे कर्मचारी, नागरिक एवं अन्य हितधारक स्वच्छता एवं साफ-सफाई के सामूहिक प्रयासों में भाग लेंगे।

इस पहल का उद्देश्य स्वच्छ रेलवे परिसरों एवं स्वच्छ समाज के निर्माण में सामूहिक जिम्मेदारी और जनभागीदारी के संदेश को और मजबूत करना है।

पूर्व मध्य रेल द्वारा मात्र 182 दिनों में 100 मीलियन टन का किया गया माल लदान

बिहान भारत

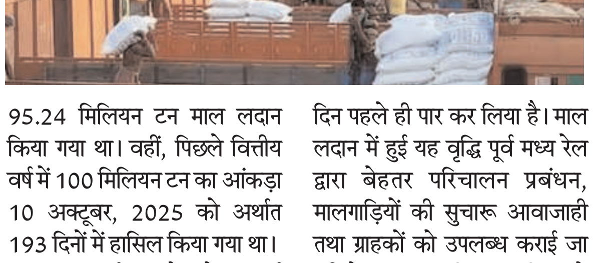

हाजीपुरः पूर्व मध्य रेल ने माल लदान के क्षेत्र में एक और उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में 01 अप्रैल से 29 सितम्बर, 2026 तक मात्र 182 दिनों में 100.41 मिलियन टन माल लदान किया गया।

यह उपलब्धि पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की तुलना में किये गये लदान से 5.17 मिलियन टन अधिक है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 01 अप्रैल से 29 सितम्बर, 2025 तक 95.24 मिलियन टन माल लदान किया गया था। वहीं, पिछले वित्तीय वर्ष में 100 मिलियन टन का आंकड़ा 10 अक्टूबर, 2025 को अर्थात 193 दिनों में हासिल किया गया था। इस प्रकार, पूर्व मध्य रेल ने इस वर्ष 100 मिलियन टन का आंकड़ा 11 दिन पहले ही पार कर लिया है। माल लदान में हुई यह वृद्धि पूर्व मध्य रेल द्वारा बेहतर परिचालन प्रबंधन, मालगाड़ियों की सुचारू आवाजाही तथा ग्राहकों को उपलब्ध कराई जा रही बेहतर माल परिवहन सुविधाओं को दशार्ती है।

पूर्व मध्य रेल द्वारा माल लदान में निरंतर वृद्धि के लिए लोडिंग क्षमता के बेहतर उपयोग, मालगाड़ियों की औसत गति में सुधार, परिचालन दक्षता बढ़ाने तथा रेल परिवहन को अधिक सुविधाजनक एवं प्रतिस्पर्धी बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। पूर्व मध्य रेल की यह उपलब्धि भारतीय रेल के माल परिवहन को सुदृढ़ करने तथा देश की अर्थव्यवस्था के विकास में रेल की महत्वपूर्ण भूमिका को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

आसनसोल मंडल में ऑन-डेट भुगतान समारोह: 22 सेवानिवृत्त रेल कर्मियों को सौंपे गए पेंशन दस्तावेज

बिहान भारत

आसनसोल : पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल द्वारा 30 सितंबर 2026 को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के नए सम्मेलन कक्ष में सितंबर माह के लिए 'ऑन-डेट भुगतान समारोह' का आयोजन किया गया। समारोह के दौरान अपर मंडल रेल प्रबंधक देबब्रत चटर्जी ने 22 सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों को उनके सेवानिवृत्ति देय, पेंशन भुगतान आदेश तथा अंतिम भुगतान से संबंधित विवरण सौंपे। इस पहल का उद्देश्य सेवानिवृत्त कर्मियों के सभी बकायों का समयबद्ध निपटान और पेंशन औपचारिकताओं को बिना किसी देरी के सुचारु रूप से पूरा करना रहा। इस अवसर पर वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी बिजॉय कुमार चटर्जी, मंडल रेल अस्पताल के सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारी अनुष टी. एल. सहित कार्मिक विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।

बिहान भारत की ओर से स्वात्वाधिकारी प्रकाशक एवं मुद्रक **संजय कुमार** के लिए वाटिका अपार्टमेंट,भोसले गली,हरिहर सिंह रोड,बरियातू,रांची-834009(झारखंड) दूरभाषः 7761060594, 7004767601 से प्रकाशित तथा डी बी कॉर्प लिमिटेड ,प्लॉट नंबर- 535 व 1272, नियर फारेस्ट ऑफिस, ललगुटवा, रांची - 835303, झारखंड से मुद्रित। समस्त दीवानी विवाद, न्यायोचित कार्रवाई एवं दंडित परिवादो के लिए क्षेत्राधिकार रांची न्यायालय में रहेगा। **संपादक : कविता साहू**(*पीआरबी एक्ट के तहत खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार)। **प्रबंध संपादक : बीरेन्द्र महली** ।
Email-bihanbharat@gmail.com, bihanbharatranchinews@gmail.com